डॉ.एम. इस्माइल फारूकी ईटीसी।

क.

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

24 अक्टूबर, 1994

[एम. एन. वेंकटचलिया, सी. जे., ए. एम. अहमदी, जे. एस. वर्मा, बी.

जी. एन. राय और एस. पी. भरुचा, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 143 (1)-कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण

अयोध्या अधिनियम, 1993-धारा 4 (3)-इसकी संवैधानिकता-क्या अनुच्छेद 143 (1) के तहत दिया गया संदर्भ प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान है।

तंत्र-(प्रति बहुमत) मुकदमे सी में निर्धारण के लिए प्रश्न जो संदर्भ द्वारा कवर नहीं किया गया है-अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा, प्रतिकूल कब्जे सहित, संदर्भ में शामिल नहीं है-संदर्भ का उत्तर भी मुकदमों में मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं देगा-अनुच्छेद 143 (1) द्वारा संदर्भ, प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान नहीं माना गया

तंत्र-धारा 4 (3), अभिनिर्धारित, असंवैधानिक-आयोजित, इसके अलावा, सभी लंबित मुकदमे

डी.

और कानूनी कार्यवाही पुनर्जीवित हो जाती है-संदर्भ अनावश्यक और अनावश्यक न्यायालय संदर्भ का जवाब देने से इनकार कर रहा है।

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण-धारा 7-क्या

7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान हिंदू समुदाय के पक्ष में है-मुकदमे का इतिहास, और हिंदुओं की संपत्तियों वाले विवादित स्थल से बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण इंगित करता है कि ई दोनों समुदायों के अधिकार प्रभावित हुए, न कि केवल दोनों समुदायों के अधिकार।

अल्पसंख्यक समुदाय-वास्तव में, धारा 7 (2) 7 जनवरी, 1993 की स्थिति को रोकती है जो हिंदू भक्तों के लिए पूजा का कम अधिकार था जो लंबे समय से अस्तित्व में था-हालाँकि, यह उचित है और क्योंकि मस्जिद को ध्वस्त करने वाले उपद्रवियों को संदिग्ध व्यक्तियों एफ

हिंदू धर्म का पालन करने का दावा करना-धर्मनिरपेक्षता।भारत का संविधान-अनुच्छेद 25 और 26-क्या एक मस्जिद को अधिग्रहण से मुक्त किया गया है-आयोजित, (बहुमत के अनुसार) एक मस्जिद एक अधिकार नहीं है।

मुसलमानों द्वारा इस्लाम धर्म और नमाज़ (प्रार्थना) के अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा कहीं भी पेश किया जा सकता है-तदनुसार, इसका अधिग्रहण नहीं

जी से मस्जिद की संवैधानिक रूप से निषिद्ध स्थिति और प्रतिरक्षा

अधिग्रहण चर्च, मंदिर सहित अन्य धार्मिक पूजा स्थलों के समान और समान है-इसके अलावा, प्रत्येक अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए-हालांकि, किसी भी धार्मिक स्थान का अधिग्रहण केवल असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप एच के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

धर्म का पालन करें।

2

भारत का संविधान-अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची-अधिग्रहण

क.

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का-विधायी क्षमता-पीठ और सार-अधिनियम, अभिनिर्धारित, (बहुमत के अनुसार) सूची III प्रविष्टि 42 में पता लगाने योग्य और सूची II प्रविष्टि में नहीं 1-"संपत्ति का अधिग्रहण" और "सार्वजनिक व्यवस्था" कानून का सार और सार नहीं है-अनुच्छेद 356।

भारत का संविधान-"धर्मनिरपेक्षता"-का अधिग्रहण

+

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के विरुद्ध अधिनियम द्वारा संपत्ति-(बहुमत के अनुसार) सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने से रोकने और सांप्रदायिक समझौते और सद्भाव को प्राप्त करने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को गैर-धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता विरोधी या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है-इसके अलावा, समग्र रूप से क़ानून को चुनौती देने के लिए तथ्यात्मक आधार और धारा 7 (2) विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता और समानता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर गैर-मौजूद-प्रस्तावना और अनुच्छेद 25 और 28-अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण-धारा 7 (2)।

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण-धारा 3 और धारा 6 के साथ पढ़ा जाता है।7- " वेस्ट "-सीमित वेस्टिंग या पूर्ण वेस्टिंग का अर्थ-आयोजित,

डी (प्रति बहुमत) "बनियान" का अर्थ उस संदर्भ से रंग लेता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि आगे आयोजित प्रत्येक प्रावधान या संदर्भ में समान हो, जबकि विवादित क्षेत्र केंद्र सरकार के पास निहित है -

...

वैधानिक प्राप्तकर्ता, विवादित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के केंद्र सरकार में निहित होना निरपेक्ष है-विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण, निर्णय लेने पर, ई का हकदार पाए जाने वाले व्यक्ति को बाद में हस्तांतरण के उद्देश्य से-धारा 6, अभिनिर्धारित, सांविधानिक रूप से वैध कानूनों की व्याख्या-प्रासंगिक व्याख्या विधायी आशय।

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण-धारा 7 (2) और 2 (ए)-"क्षेत्र"-जिसका अर्थ है-आयोजित, (प्रति बहुमत) "क्षेत्र"।7 (2) सीमित

जिस स्थान पर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की संरचना थी,

च

जबकि धारा 2 (ए) के तहत इसका मतलब क़ानूनों की अनुसूची व्याख्या-प्रासंगिक व्याख्या में निर्दिष्ट पूरा क्षेत्र है।

विधियों की व्याख्या-पृथक्करण का सिद्धांत-अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण-धारा 4 (3)-आयोजित, (बहुमत के अनुसार) धारा 4 (3),

अलग किए जाने योग्य और इसकी असंवैधानिकता शेष जी क़ानून को वैध बनाए रखने में बाधा नहीं है।

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण-धारा 8-केवल पूरी तरह से अधिग्रहित संपत्ति के लिए आयोजित (बहुमत के अनुसार) मुआवजे का भुगतान-विवादित क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा केवल एक वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में लिया जा रहा है, यह माना जाता है कि मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यह मुकदमों में सफल पक्ष को सौंपा जाना है।

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई.

3

क़ानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण निर्माण-आयोजित, निर्माण ए जिसे क़ानून की भाषा राष्ट्रीय उद्देश्य को सहन कर सकती है और बढ़ावा दे सकती है, गुटबाजी और कलह को बढ़ावा देने के लिए एक सख्त और शाब्दिक निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद संरचना के विध्वंस के बाद, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। इसके बाद, 7 जनवरी, 1993 को अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993 लागू किया गया।

इस तरह के अध्यादेश को बाद में उसी प्रभाव के लिए एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।साथ ही, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया था।एस.

न्यायालय को भेजा गया प्रश्न थाः

" चाहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी (जिसमें ऐसे मंदिर के आंतरिक और बाहरी प्रांगण भी शामिल थे)।

डी.

संरचना) जिस क्षेत्र में संरचना खड़ी थी?" संदर्भ को अस्पष्ट होने और अपने आप में नहीं होने के रूप में चुनौती दी गई थी

वास्तविक विवाद का निर्णायक।यह तर्क दिया गया कि प्रश्न अकादमिक था, और इस बात का कोई निश्चित संकेत नहीं दिया कि केंद्र सरकार संदर्भ का उत्तर दिए जाने के बाद किस तरह से कार्य करने का इरादा रखती है और ई कि यह किसी भी संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है जिसके लिए अदालत के सलाहकार अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है; और यह कि वास्तविक उद्देश्य मुसलमानों के पूजा स्थल को छीनना और इसे हिंदुओं को देना था।इसलिए यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय को संदर्भ का जवाब देने से इनकार कर देना चाहिए।

च

भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर-जनरल ने एक

बयान, अन्य बातों के साथ-साथ, कि सरकार इस न्यायालय के निष्कर्ष को अंतिम और बाध्यकारी मानेगी, और इस न्यायालय की राय के आलोक में और इसके अनुरूप, सरकार बातचीत की प्रक्रिया द्वारा विवाद को हल करने का प्रयास करेगी।यदि बातचीत से समझौता विफल हो जाता है, तो सरकार इस न्यायालय की राय के अनुरूप एक समाधान लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी।यदि इस न्यायालय को यह पता चलता कि एक हिंदू

जी.

ध्वस्त संरचना के निर्माण से पहले मंदिर/संरचना मौजूद थी, सरकारी कार्रवाई हिंदू समुदाय की इच्छाओं के समर्थन में होगी।यदि इसे नकारात्मक पाया जाता है, तो सरकारी कार्रवाई मुस्लिम समुदाय की इच्छाओं के समर्थन में होगी।

एच.

टी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी.5 एस. सी. आर. ए. कानून को चुनौती देने का ध्यान धर्मनिरपेक्षता, समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर था।यह तर्क दिया गया था कि मस्जिद, धार्मिक पूजा का स्थान होने के नाते, राज्य की अधिग्रहण की शक्ति से मुक्त है और यह क़ानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है।यह आगे तर्क दिया गया कि अधिनियम न्यायनिर्णयन के न्यायिक उपचार से वंचित करता है

बी एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किए बिना; और यह कि इसने 400 से अधिक वर्षों के लिए प्रतिकूल कब्जे सहित मुकदमों में लिए गए बचाव को समाप्त कर दिया।यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 7 7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देकर मस्जिद के विध्वंस की शरारत को कायम रखती है, जो हिंदुओं को विवादित स्थल में मुसलमानों को उस क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर रखते हुए किसी प्रकार की पूजा के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है, और यह भेदभाव केंद्र सरकार द्वारा किसी भी समय तक कायम रखा जा सकता है।अधिग्रहण की वैधता को उन लोगों द्वारा भी चुनौती दी गई थी जिनकी संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था, हालांकि संपत्तियां विवादित क्षेत्र के बाहर स्थित थीं।

डी.

केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि सांप्रदायिकता को देखते हुए

विशेष रूप से, अधिनियम के तहत अधिग्रहण और वहां संबोधित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए विशेष संदर्भ से समस्या का बातचीत से समाधान करने में सुविधा होगी और यदि यह विफल हो जाता है, तो बातचीत से समाधान लाने के लिए, यह उचित कार्रवाई करेगा जैसा कि माना जाएगा।

सुविधाजनक।इसने तर्क दिया कि अधिग्रहण का उद्देश्य ई समुदाय को वंचित करना नहीं था, बल्कि 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में हुई घटना के मद्देनजर विवाद के बढ़ने से बचने के लिए अधिनियम पारित किया गया था और यह अधिनियम उस दिशा में एक आवश्यक कदम था।

संदर्भ को वापस करना और मामलों का निपटारा करना, यह न्यायालय

च

हेल्ड (प्रति बहुमत) (जे. एस. वर्मा, जे. अपने लिए एम. एन. वेंकटचलैया, सी. जे., जी. एन. रे, जे.)

1. अधिनियम बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण प्रविष्टि जी 42, सूची III से पता लगाया जा सकता है।यू. पी. राज्य में उपयुक्त समय पर राष्ट्रपति शासन होने के कारण संसद की विधायी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।विधान का सार और सार 'संपत्ति का अधिग्रहण' है और यह पूरी तरह से प्रविष्टि 42, सूची III के दायरे में आता है।'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित प्रतियोगी प्रविष्टि प्रविष्टि 1, सूची 2 है।'सार्वजनिक व्यवस्था' के बजाय 'संपत्ति का अधिग्रहण' क़ानून का सार है।(39- जी. एच)

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई.

5

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रविष्टि 42, सूची III का संशोधन और प्रविष्टि 33, ए सूची I और प्रविष्टि 36, सूची II का लोप इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि इस तरह का अधिग्रहण अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रविष्टि 42, सूची III के दायरे में आता है।(40 - एच, 41-ए)।बिहार राज्य बनाम।महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह

दरभंगा, [1952] एस. सी. आर. 889 और उपायुक्त और कलेक्टर, बी. कामरूप बनाम।दुर्गा नाथ शर्मा, [1968] 1 एससीआर 561, का उल्लेख किया गया है।2. लंबित मुकदमों में बनाए गए मुद्दों से यह स्पष्ट है कि मुकदमों में निर्धारण के लिए मुख्य प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है -

संदर्भ दिया गया।इसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा उठाए गए बचाव को भी शामिल नहीं किया गया है, जिसमें 400 से अधिक वर्षों से विवादित क्षेत्र पर प्रतिकूल कब्जा भी शामिल है।यह भी स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर, चाहे वह कुछ भी हो, लंबित मुकदमों में निर्धारण के लिए मूल प्रश्न का उत्तर नहीं देगा और यह विवादित क्षेत्र से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवाद को अपने आप हल नहीं करेगा।इसके अलावा, केंद्र सरकार, अपने बयान के अनुसार, बातचीत की एक प्रक्रिया का सहारा लेने का प्रस्ताव करती है, और यदि वह विफल रहती है, तो इस तरह के पाठ्यक्रम डी को अपनाने का प्रस्ताव करती है जो उसे परिस्थितियों में उचित लगे।इन परिस्थितियों में, अनुच्छेद 143 (1) के तहत दिए गए संदर्भ को लंबित मुकदमों के प्रतिस्थापन में एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है जो अधिनियम की धारा 4 (3) द्वारा निरस्त किए गए हैं।यह अधिनियम की धारा 4 (3) को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।हालांकि, धारा 4 (3) अलग करने योग्य है, और इसलिए इसकी अयोग्यता शेष ई के लिए बाधा नहीं है।

कानून को वैध माना जा रहा है।(41 - सी-ई) श्रीमती।इंदिरा नेहरू गांधी बनामश्री राज नारायण, [1975] पूरक।एस. सी. सी. 1, संदर्भित।

3.1 .संवैधानिक योजना सभी व्यक्तियों और समूहों को उनके धर्म की परवाह किए बिना एफ धर्म के मामले में समानता की गारंटी देती है।

इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य का कोई धर्म नहीं है।विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 28 के साथ पठित संविधान की प्रस्तावना इस पहलू पर जोर देती है और इंगित करती है कि यह इस तरह की अवधारणा है -

भारतीय लोगों द्वारा अपनाए गए एक पंथ के रूप में संवैधानिक योजना में सन्निहित धर्मनिरपेक्षता को संविधान की कसौटी पर किसी भी कानून की जी संवैधानिक वैधता को समझते हुए समझना होगा।(49 - बी)

एम. सी. सीतलवाड़, पटेल मेमोरियल व्याख्यान 1985 धर्मनिरपेक्षता पर; डॉ. शंकर दयाल शर्मा, "भारतीय लोकाचार में धर्मनिरपेक्षता", डॉ. जाकिर हुसैन स्मारक व्याख्यान (1989); एस. आर. बोम्मई बनाम

भारत संघ, [1994] सर्वोच्च न्यायालय/रिपोर्ट [1994] समर्थन।5 एस. सी. आर. ए. 3 एस. सी. सी. 1 और एम. एन. वेंकटचलैया, जे., "लॉ इन ए प्लुरलिस्ट सोसाइटी", का उल्लेख किया गया है।

3.2 .6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस के परिणामस्वरूप एक सांप्रदायिक नरसंहार हुआ।सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है

बी, किसी भी तर्क के विस्तार से, गैर-धर्मनिरपेक्ष, बहुत कम धर्मनिरपेक्ष विरोधी या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है।तथ्य यह भी इंगित करते हैं कि संपत्तियों का अधिग्रहण दोनों समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करता है न कि केवल मुस्लिम समुदाय के।धारा 7 (2) के तहत 7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखना हिंदू भक्तों को पहले की तुलना में पूजा का कम अधिकार प्रदान करता है।

विवादित ढांचे के विध्वंस तक लंबे समय तक।इसलिए, इसका हिंदू को प्रदान करने या देने का प्रभाव नहीं पड़ता है।

इससे समुदाय को कोई और लाभ होता है।यह प्रावधान विवादित क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के पूजा के अधिकार को कम नहीं करता है, क्योंकि 1949 से वास्तव में इस प्रथा या पूजा का कोई अभ्यास नहीं हुआ है।(53 - जीएच, 55-ई, 56-सी)

डी.

4. संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण के अधीन, मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि जैसे धार्मिक पूजा स्थलों को राज्य की अधिग्रहण की संप्रभु शक्ति के तहत प्राप्त किया जा सकता है।इस तरह का अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं करता है।(64 - ई)

ई.

खजामियन वक्फ एस्टेट बनाम।मद्रास राज्य, [1971] 2 एस. सी. आर. 791 और आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंद प्रसादजी महाराज आदि।गुजरात राज्य, [1975] 2 एस. सी. आर. 317, पर निर्भर था।

अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास एफ के लिए है जो धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है।एक प्रथा एक धार्मिक प्रथा हो सकती है लेकिन उस धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं हो सकती है।जबकि प्रार्थना या पूजा की पेशकश एक धार्मिक प्रथा है, हर उस स्थान पर इसकी पेशकश जहां ऐसी प्रार्थना की जा सकती है, ऐसी धार्मिक प्रथा का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं होगा जब तक कि उस स्थान का उस धर्म के लिए कोई विशेष महत्व न हो ताकि एक जी आवश्यक या अभिन्न अंग बन सके।उस धर्म के लिए विशेष महत्व रखने वाले किसी भी धर्म के पूजा स्थल, इसे धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग बनाने के लिए, एक अलग आधार पर खड़े हैं और उनके साथ अलग और अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।(65 - एफ-एच)

राजा सूर्यपालसिंह बनाम।उत्तर प्रदेश सरकार, आकाशवाणी (1951) सभी 674 (एफ. बी.), एच.

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई.

7

5. एक मंदिर, चर्च या मस्जिद आदि अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति हैं और अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण के अधीन हैं। प्रत्येक अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है।उचित परिप्रेक्ष्य में देखने पर, एक मस्जिद को कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलती है जो अन्य धर्मों के धार्मिक पूजा स्थलों के लिए उपलब्ध नहीं है।(66 - जी)

6. एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज (प्रार्थना) कहीं भी, यहां तक कि खुले में भी अदा की जा सकती है।तदनुसार, इसके अधिग्रहण द्वारा निषिद्ध नहीं है

भारत का संविधान।एक मस्जिद के अधिग्रहण से स्थिति और प्रतिरक्षा सी अन्य धर्मों, अर्थात् चर्च, मंदिर, आदि के पूजा स्थलों के समान और बराबर है। जाहिर है, किसी भी धार्मिक स्थान का अधिग्रहण केवल असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किया जाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अभ्यास करने का अधिकार समाप्त नहीं होना चाहिए।

धर्म, यदि उस स्थान का महत्व इस प्रकार है।पूजा करने का अधिकार डी

यह किसी भी और हर स्थान पर नहीं है, जब तक कि इसका प्रभावी ढंग से अभ्यास किया जा सके, जब तक कि किसी विशेष स्थान पर पूजा करने का अधिकार स्वयं उस अधिकार का एक अभिन्न अंग न हो।(67 - ए-डी)

एम. हिदायतुल्ला, मुल्ला के मुहम्मद कानून के सिद्धांत (19 वां संस्करण) धारा 217 और ए. आई. आर. (1940) पी. सी. 116 का उल्लेख किया गया है।

ई.

7.1 .यह विचार कि एक बार मस्जिद का निर्माण हो जाने के बाद, यह हमेशा एक मस्जिद के रूप में पूजा का स्थान बना रहता है, भारतीय अदालतों द्वारा अनुमोदित भारत का मुसलमान कानून नहीं है।(62 - जी)

मस्जिद के रूप में जानी जाने वाली मस्जिद शाहिद गंज बनाम।शिरोमणि गुरुद्वारा एफ. प्रबंधक समिति, ए. आई. आर. (1938) लाह 369 ने इस पर भरोसा किया।

मुथियालू चेट्टी बनाम।बापुन सैब, आई. एल. आर. 2 मैड 140 और सुंदरम चेट्टी बनाम।रानी आई. एल. आर. 6 मैड 203, संदर्भित।

7.2 .अधिग्रहण की शक्ति संपत्ति प्राप्त करने के लिए राज्य की संप्रभु या विशेषाधिकार शक्ति जी है।ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 300 ए या पूर्ववर्ती अनुच्छेद 31 से स्वतंत्र है जो केवल

राज्य द्वारा अधिग्रहण की शक्ति पर सीमाओं को इंगित करें।(63 - जी) चिरनजीतलाल चौधरी बनाम।भारत संघ, [19501 एस. सी. आर. 869 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम।इसके बाद सुबोध गोपाल बोस, [1954] एस. सी. आर. 587 आया।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

8.1 .'बनियान' शब्द का अर्थ संदर्भ से रंग लेता है

क.

जिसका उपयोग किया जाता है।इसके उपयोग के संदर्भ के आधार पर यह एक ही क़ानून के विभिन्न हिस्सों में या यहां तक कि एक ही खंड में भी भिन्न हो सकता है।(50 - जी) महाराज सिंह बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य, [1977] 1 एस. सी. आर. 1072, पर निर्भर था।बी 8.2।इसका मतलब यह नहीं है कि हर स्थिति में पूरी तरह से निहित होना चाहिए और यह सीमित निहित होने का अर्थ वहन करने में सक्षम है, जो शीर्षक और अवधि में सीमित है।अधिनियम की धारा 3 के आधार पर निहित होने के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की स्थिति विवादित क्षेत्र के संबंध में एक सांविधिक प्राप्तकर्ता की है, साथ ही अयोध्या में विवादित ढांचे से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवाद के निर्णय के अंतिम परिणाम तक विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने के प्रबंधन और प्रशासन का कर्तव्य है।हालाँकि, विवादित क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की केंद्र सरकार में निहित होना निरपेक्ष है।'बनियान' के अर्थ में धारा 3 और 6 में ये अलग-अलग रंग हैं।

अधिनियम द्वारा अधिग्रहित पूरे क्षेत्र के दो भागों के संबंध में।(59 - ए-बी डी 9।धारा 7 (2) के साथ पठित धारा 6 (1) इस आशय के क़ानून में एक अंतर्निहित संकेत है कि विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण और

केंद्र सरकार में निहित होना निरपेक्ष नहीं है, बल्कि विवाद के निर्णय के परिणामस्वरूप इसके हकदार व्यक्ति को इसके बाद के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए है, जिसके समाधान के लिए यह कदम अभ्यास का हिस्सा है।अनुच्छेद 143 (1) ई के तहत एक साथ अध्यादेश जारी करने के साथ संदर्भ, जिसे बाद में अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, इस विधायी इरादे का भी संकेत है कि विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण निरपेक्ष नहीं बल्कि सीमित था।(57 - एफ)

10. जिस संदर्भ में धारा 7 (2) में 'क्षेत्र' शब्द का उपयोग किया गया है, वह इंगित करता है कि इसका अर्थ धारा 2 (ए) के समान नहीं है, जिसका अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट एफ पूरे क्षेत्र से है।

इसका अर्थ यह है कि यह केवल उस स्थान तक सीमित है जिस पर यह संरचना, जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, वह स्थान या क्षेत्र निस्संदेह अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर छोटा है।(38 - जी)

जी.

11.1 .धारा 7 एक अस्थायी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य स्थिति बनाए रखना है।

विवादित क्षेत्र में यथास्थिति, जब तक कि विवाद के समाधान पर केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाता है।यह तय करने में कि क्या यह प्रावधान जो यथास्थिति बनाए रखने को अनिवार्य करता है, और समग्र रूप से कानून जो अधिग्रहण को प्रभावित करता है, हिंदू समुदाय के पक्ष में है, एच विवादित क्षेत्र के तुलनात्मक उपयोगकर्ता और दो एम. आई. फारूकी बनाम द्वारा उसमें प्रचलित पूजा के अधिकार को याद करना आवश्यक है।

यू. ओ. आई.

9 7 जनवरी, 1993 को समुदाय और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए ए

उससे पहले।दिसंबर 1949 में राम चबूतरे से उन मूर्तियों को विवादित ढांचे में स्थानांतरित करने से पहले ही विवादित ढांचे के प्रांगण में विवादित स्थल पर खड़ी राम चबूतरे में स्थापित मूर्तियों की पूजा मुसलमानों की बिना किसी आपत्ति के की गई थी। 1950 में निचली अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार, मूर्तियां उसी स्थान पर रहीं जहां उन्हें स्थापित किया गया था और हिंदू भक्तों द्वारा वहां मूर्तियों की पूजा जारी रही।इस अंतरिम आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने 1955 में की थी।जिला न्यायाधीश ने 1 फरवरी, 1986 को विवादित ढांचे में मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाली ग्रिल पर रखे गए ताले को खोलने का आदेश दिया और वहां हिंदू भक्तों को मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी।यह स्थिति 6 दिसंबर, 1992 तक थी।विध्वंस के बाद से, केवल पुजारी द्वारा सी की मूर्तियों की पूजा जारी है।दूसरी ओर, मुसलमान विवादित स्थल पर किसी भी स्थान पर पूजा नहीं कर रहे हैं, हालांकि मुकदमों के मुकदमे में यह पता चल सकता है कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।(52 , सी, 53-ए-एफ)

डी.

11.2 .इसके अलावा, जैसा कि अयोध्या को विशेष कहा जाता है

हिंदुओं के लिए राम के जन्म स्थान के रूप में महत्वपूर्ण, यह मस्जिद मुस्लिम समुदाय के लिए 1526 ईस्वी में मीर बाकी द्वारा बनाई गई एक प्राचीन मस्जिद के रूप में महत्वपूर्ण थी।एक मस्जिद के रूप में यह केवल मुसलमानों द्वारा पूजा का एक धार्मिक स्थान था।यह दोनों समुदायों के लिए विवादित स्थल के तुलनात्मक महत्व को दर्शाता है, और यह भी कि अधिग्रहण का प्रभाव हिंदू समुदाय के अधिकार और हित पर समान रूप से पड़ता है।तथ्यों का वर्णन इंगित करता है कि अधिनियम के तहत संपत्तियों का अधिग्रहण दोनों समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करता है न कि केवल मुस्लिम समुदाय के।(55 - डी)

ई.

12. हालाँकि विध्वंस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

च

विवादित संरचना कुछ उपद्रवी थे जिनकी तुलना पूरे हिंदू समुदाय के साथ नहीं की जा सकती और बर्बरता का कार्य नहीं किया जा सकता।

पूरे हिंदू समुदाय के एक कार्य के रूप में माना जाता है, धारा 7 (2) में अधिनियमित हिंदू समुदाय की पूजा के अधिकार के प्रयोग को सीमित करना उचित और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत होता है कि मस्जिद को ध्वस्त करने वाले उपद्रवियों पर संदेह है कि वे व्यक्ति हैं जो हिंदू धर्म का पालन करने वाले जी को स्वीकार करते हैं।(55 - जी)

13. हिंदुओं की संपत्तियों के बड़े हिस्से वाले एक बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण का औचित्य यह है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्णय का अंतिम परिणाम न दिया जाए

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी. पी. में हिंदुओं की संपत्तियों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है।

5 एस सी आर।

यदि मुसलमान विवादित स्थल के हकदार पाए जाते हैं तो विवादित संरचना के आसपास का क्षेत्र।विवादित संरचना, जो अपने आप में एक अद्वितीय वर्ग है, से निकटता को देखते हुए आस-पास के मंदिरों या धार्मिक भवनों को प्राप्त करने की आवश्यकता अनुमत है।(54 बी एंड ई) एम. पद्मनाभ अयंगर बनाम।सरकार.ए. पी., ए. आई. आर. (1990) ए. पी. 357 और बी. अखाड़ा श्री ब्रह्म बुटा बनाम।पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1990) पी और एच 198, को मंजूरी दी गई।

14. हालांकि, बाद के चरण में जब अधिग्रहण के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिग्रहित सटीक क्षेत्र की आवश्यकता होती है

यह निर्धारित किया गया है कि अनावश्यक अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए ऐसी किसी भी संपत्ति के मालिक के लिए यह खुला रहेगा।यह सिर्फ नहीं होगा

एस.

अनुज्ञेय लेकिन वांछनीय है कि अनावश्यक क्षेत्र को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए और इसके पहले के मालिक को वापस कर दिया जाए।(54 - जी)

15. धारा 8 केवल विवादित क्षेत्र के अलावा पूरी तरह से अर्जित संपत्ति के लिए है, जो विवादित क्षेत्र डी के निकट और आसपास है।विवादित क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा केवल एक वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में लिया जा रहा है, इसके लिए मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इसे मुकदमों में सफल पक्ष को सौंपा जाना है।(60 - जी)

16. एक ऐसा निर्माण जिसे क़ानून की भाषा वहन कर सकती है और एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा दे सकती है, उसे सख्त शाब्दिक निर्माण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ई.

गुटबाजी और कलह को बढ़ावा देने के लिए निर्माण।(61 - बी)

17. इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार के बयान

यह विध्वंस कि मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा, संसद की शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है, और अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए सामग्री नहीं है।कानून की वैधता होनी चाहिए

च

यह संविधान की कसौटी पर निर्धारित किया जाता है न कि इससे पहले दिए गए किसी भी बयान पर।(56 जी-एच; 57 ए)

18. धारा 4 (3) को छोड़कर पूरा क़ानून वैध पाया जा रहा है, और लंबित मुकदमे और कानूनी कार्यवाही जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लिया जाना है, को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

जी.

अनुच्छेद 143 (1) के तहत दिया गया संदर्भ अनावश्यक और अनावश्यक हो जाता है।इसलिए यह न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने से इनकार कर देता है और उसी को वापस कर देता है।(67 ई, एफ)

19. सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जाता है, और उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

एम. आई. फारूकी बनाम।यू. ओ. आई.

11

विवादित क्षेत्र केंद्र सरकार के पास एक सांविधिक ए रिसीवर के रूप में निहित है, जिसका कर्तव्य है कि वह धारा 7 (2) के आधार पर अधिनियम में प्रदान किए गए तरीके से इसका प्रबंधन और प्रशासन करे।केंद्र सरकार उस संपत्ति को किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या ट्रस्ट को सौंपने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी।

अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार।एक वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में केंद्र सरकार बी को निर्देश देने के लिए लंबित कानूनी कार्यवाही में अदालतों की शक्ति सीमित और सीमित होगी

अधिनियम के प्रावधानों द्वारा खुले रखे गए क्षेत्र का विस्तार।केंद्र सरकार मुकदमों और अन्य कानूनी कार्यवाही में निर्णय को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और मुकदमों में किए गए अंतिम निर्णय पर विवादित क्षेत्र को उसी पक्ष को सौंपने के लिए बाध्य होगी।(67 - जी-एच, 68-ए-बी) अयोध्या पर श्वेत पत्र, जिसका उल्लेख है।

प्रति अल्पसंख्यक (एस. पी. भरुचा, जे. द्वारा अपने लिए और ए. एम. अहमदी,

जे.)

डी.

1. “ एरिया "अंडर।धारा 2 (ए) और 3 अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।धारा 4 (1) के कारण, "क्षेत्र" में परिसंपत्तियाँ और सभी चल और अचल संपत्ति, और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल हैं।धारा 4 (2) के कारण, संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल केंद्र सरकार में निहित है जो सभी बाधाओं से मुक्त और मुक्त है।अधिनियम की धारा 4 का प्रभाव यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो विवादित ढांचे में रखी गई मस्जिद का प्रशासन करता था, और मुस्लिम समुदाय 1528 ईस्वी से 1949 तक विवादित स्थल पर प्रतिकूल कब्जे का अनुरोध करने का अपना अधिकार खो देता है, यह देखते हुए कि मूर्तियां अब तक वहां बनी हुई हैं।

ई.

विवादित संरचना केवल अदालतों के आदेशों के तहत।(82 - एफ, 87-बी) एफ

2. हक के बारे में विवाद मुआवजे के उद्देश्य से बने रहते हैं, जिसके लिए धारा 8 के तहत हक को अदालत के समक्ष नहीं बल्कि दावा आयुक्त के समक्ष स्थापित करना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, जो अपनी प्रक्रिया तैयार करने का हकदार है।धारा 4 (3) के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों के समाप्त होने के साथ, विवादित स्थल के स्वामित्व के निर्णय के लिए मंच अदालतों से दावा आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया जाता है।दीवानी अदालत में अपील या निर्देश का कोई अधिकार इस परिणाम के लिए प्रदान नहीं किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक उपाय को छोड़कर दावा आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।(87 - ई-एफ) एच

जी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी.5 एस सी आर।

12

3. इसलिए, धारा 4 और 8 के प्रावधानों को इस प्रकार माना जाना चाहिएः

क.

मनमाना और अनुचित।(87 - एफ)

4. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान, क्योंकि वे सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को वंचित करते हैं

अभिवचन करने और प्रतिकूल अधिकार स्थापित करने का अधिकार रखने वाला समुदाय और बी संदर्भ द्वारा प्रस्तुत सीमित प्रश्न और उसके बाद की बातचीत के संदर्भ में अपनी शिकायत के निवारण को प्रतिबंधित करता है, और अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल केंद्र सरकार को सौंपते हैं, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, जिसे एक धार्मिक समुदाय के पक्ष में दूसरे के खिलाफ झुकाया जाता है।(87 - जी-एच)

केशवानंद भारती बनाम।केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी. 225 और एस. आर. बोम्मई बनामभारत संघ, [1994] 3 एस. सी. सी. 1, पर निर्भर था।

राज्य का कोई धर्म नहीं है।राज्य सभी धर्मों के बीच भी डी का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए बाध्य है।यह एक धर्म के उद्देश्य को दूसरे के नुकसान के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता है।(89 - ए)

5. अधिनियम के मुख्य प्रावधान धारा 3,4 और 8 हैं।अधिनियम के अन्य प्रावधान केवल धारा 3,4 और 8 के सहायक और आनुषंगिक हैं।चूंकि धारा 3,4 और 8 के मुख्य प्रावधान हैं -

ई.

असंवैधानिक, अधिनियम अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता है।(89 - बी)

6. धारा 7 के प्रावधानों को इसके समर्थन में संदर्भित किया गया है

यह पाते हुए कि अधिनियम एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म के पक्ष में तिरछा है।इस प्रावधान के लिए आवश्यक है कि विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद शुरू की गई पूजा तब तक जारी रहे जब तक कि अधिनियम के तहत संपत्ति का एफ प्रबंधन जारी रहे।इस तरह के प्रबंधन को कब तक जारी रखना है और किस घटना के होने पर यह समाप्त हो जाएगा, इसका संकेत नहीं है।इसलिए धारा 7 (2) विवादित स्थल पर पूजा के प्रदर्शन को कायम रखती है।इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि उस पर संरचना को नष्ट कर दिया गया था

धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर प्रहार करने वाला निंदनीय कार्य

जी.

और कानून का शासन।न ही यह तथ्य कि उस स्थान के संबंध में कोई विवाद है जिस पर पूजा की जानी है, और यह कि दिसंबर, 1949 की रात तक, जब मूर्तियों को विवादित ढांचे में रखा गया था, विवादित ढांचे का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा था; और यह कि मुस्लिम समुदाय को उसमें नमाज अदा करने का अधिकार है।(89 - एफ-जी)

13

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई.

अयोध्या पर श्वेत पत्र का उल्लेख किया गया है।

क.

7. धर्मनिरपेक्षता को संविधान में गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है।इसका उद्देश्य सभी धर्मों को संरक्षित और संरक्षित करना है, सभी धर्मों को स्थापित करना है।

बराबर पर समुदाय।इसलिए, जब अधिकांश भारतीय नागरिकों के धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के पूजा स्थल पर दावा करते हैं और हमला करते हैं और संख्या के आधार पर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जो सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए अनुकूल हों, तो यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह उस पूजा स्थल की रक्षा करे और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखे, इस उद्देश्य के लिए कानून और व्यवस्था के ऐसे साधनों और ताकतों का उपयोग करे जो आवश्यक हैं।के प्रावधानों के तहत यह अस्वीकार्य है

सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस पूजा स्थल का अधिग्रहण करने के लिए राज्य का संविधान।ऐसी सी परिस्थितियों में पूजा स्थल के अधिग्रहण को माफ करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को समाप्त करना है

संविधान।(90 - एफ, जी)8. हालाँकि, यह जोड़ा जा सकता है कि यदि पूजा स्थल का अधिकार अदालत में विवाद में है, और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में है, तो केंद्र सरकार के लिए दो मार्ग खुले हैं:यह संबंधित न्यायालय को पूजा स्थल का प्राप्तकर्ता नियुक्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, ताकि उसके अधिकार का अंतिम निर्णय होने तक इसे सुरक्षित रखा जा सके, या वह ऐसा कानून बना सकता है जो उसे निर्णय होने तक वैधानिक प्राप्तकर्ता बनाता है।किसी भी स्थिति में, केंद्र सरकार खुद को सौंपने के लिए बाध्य होगी

उस पार्टी के लिए पूजा का स्थान जिसका पक्ष में शीर्षक पाया जाता है।(90 - एच.ई.

91 - ए-बी) आयुक्त, एच. आर. ई. बनाम।श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, [1954] एससीआर 1005, का उल्लेख किया गया है।

9. व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करना, अभ्यास करना और

धर्म का प्रचार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है।धर्मनिरपेक्षता निरपेक्ष है; एफ राज्य धर्मों के साथ इस आधार पर अलग व्यवहार नहीं कर सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता है।यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से स्पष्ट होता है जो

अनुच्छेद 15 और 16 के प्रावधानों को उजागर करता है, अनुच्छेद 27 द्वारा धर्म के मामलों में राज्य के लिए आवश्यक 'व्यावहारिक दृष्टिकोण', और

अनुच्छेद 29 (2) की पूर्ण शर्तें।(91 - एच, 92-सी)

जी.

10.1 .यह न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत उसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने का हकदार है यदि वह मानता है कि ऐसा करना उचित या संभव नहीं है, लेकिन उसे अपने कारणों को इंगित करना होगा।(94 - बी)

1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 और विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, [1979] 3 एस. सी. आर. 476 पर भरोसा किया गया था।

एच 14

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. 10.2।संदर्भ का उत्तर निम्नलिखित के लिए नहीं दिया जाना चाहिएः

कारणःअधिनियम और संदर्भ एक धार्मिक समुदाय का पक्ष लेते हैं और दूसरे को नापसंद करते हैं; इसलिए, संदर्भ का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और असंवैधानिक है।इसके अलावा, संदर्भ एक संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।(94 - डी)

दूसरा, संदर्भ से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय

सरकार न्यायालय की राय के संदर्भ में विवाद को निपटाने का प्रस्ताव नहीं करती है, बल्कि इसे बातचीत के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव करती है।

इस तरह की बातचीत के परिणामस्वरूप विवाद के समाधान को 'उक्त राय के संदर्भ में' विवाद का समाधान नहीं कहा जा सकता है।तीसरा, साक्ष्य का एक पहलू है।न्यायिक राय देने की अंतर्निहित अयोग्यता सी के अलावा, जो अदालत के लिए विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए, राय एक या दोनों पक्षों की आलोचना के लिए उत्तरदायी होगी कि यह उन्हें या उनके साक्ष्य को सुने बिना दी गई थी।इसका आम तौर पर कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि उन्होंने दूर रहना चुना था, लेकिन इस राय का उद्देश्य लोगों के लिए एक सार्वजनिक वातावरण बनाना है।

बातचीत और आलोचनाओं को जनता के कान लगेंगे, कुछ नहीं कहेंगे

डी तथ्य यह है कि यह इस न्यायालय की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा।(94 - ई, 95-ए-बी) नागरिक मूल न्यायनिर्णयःहस्तांतरित मामला (सी) सं।41 ,

43 और 1993 का 45 आदि।

ई. टी. पी. सं. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.9.93 न्यायालय के आदेश से।669-75 1993 में।

टी. सी. में याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से (ग) संख्या।41 और 44/93।

डी. पी. गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल, सतीश चंद्र, राजीव धवन, ओ. पी. शर्मा, एम. के. बनर्जी, पी. पी. मल्होत्रा, जितेंद्र शर्मा, वी. एम. तारकुंडे, अनिल बी. दीवान, डी. वी. सहगल, पी. पी. राव, पी. एन. डूडा, एफ. एस. नरीमन, अशोक एच. देसाई, जोसेफ वेल्लापल्ली, बी. पी. अग्रवाल, एस. वेंकट रेड्डी, पी. एल. मिश्रा, सी. एस. अशरी, आर. पी. वाधवानी, अरुण कुमार सिन्हा, जाकी अहमद खान, मनोज सक्सेना, इरशाद अहमद, सुश्री अपर्णा विश्वनाथन, मुस्ताक अहमद, एम. एम. कश्यप, सुश्री

च

प्रकाश, ए. सुब्बा राव, हेमंत शर्मा, एस. ए. सैयद, शाहिद रिज़वी, ए. एन. एम. तैयब खान, सुश्री दीपाली तलवार, आर. एस. मेसी वर्मा, एम. ज़कीखान, एम. टी. खान, अब्दुल मन्नान, शकील अहमद सैयद, जेड. जिलानी, एम. ए. सिद्दीकी, सुश्री गुनवंत दारा, सुश्री निलोफर भागवत, सुश्री पी. गौर, आर. सी. वर्मा, आर. बी. मिश्रा, ए. पी. धमीजा, एस. के. जैन, सिबा शंकर मिश्रा, ए. भट्टाचार्जी, पी. पी. सिंह, रणधीर जैन, के. सी. दुआ,

जी.

एफ.

सर्व मित्तर, एम. वीरप्पा, एस. सी. शर्मा, के. एच. नोबिन सिंह, एस. एम. जाधव, ए.

ए. एस. भासमे, वी. के. बीरन, एम. टी. जॉर्ज, बी. पी. अग्रवाल, अरुणेश्वर गुप्ता, जी. प्रकाश, कैप्टन।के. एस. भाटी, एस. वेंकट रेड्डी, कृष्णा कौंडिन्य, सुश्री प्रोमिला चौधरी, निखिल नय्यर, T.V.S.N. चारी, एन. के. शर्मा, आर. सी. मिश्रा, डॉ. मीरा अग्रवाल, एस. एन. भुइयां, एस. के. नंदी, बड़ा अहमद, जे. बी. दादाचंजी, सुश्री तमाली सेन गुप्ता, जे. बी. डी. एंड कंपनी के लिए ए. एस. पारिच, एस. एन. मेहता, आर. पी. सिंह, एच. के. पुरी, एस. के. पुरी, देवकी नंदन अग्रवाल, आई. एस. गोयल, सुश्री इंदु मल्होत्रा, ए. के. गोयल, ए. एस.एस.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. एस. वर्मा, जे. " हमारे पास नफरत करने के लिए पर्याप्त धर्म है, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

- जोनाथन स्विफ्ट डी

स्वामी विवेकानंद ने कहा था -

" धर्म सिद्धांतों में नहीं है, हठधर्मिता में नहीं है, न ही बौद्धिक तर्क में है; यह होना और बनना है, यह प्राप्ति है।जब हम इसकी जड़ों पर विचार करते हैं तो यह विचार दिमाग में आता है।

विवाद।इस विवाद की उत्पत्ति का पता हमारी राजनीति की बहुवचन प्रतिबद्धताओं के कुछ मौलिक मूल्यों के क्षरण से लगाया जा सकता है।

कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता

अयोध्या अधिनियम, 1993 (1993 का सं. 33) (इसके बाद "अधिनियम सं. 33" के रूप में संदर्भित)

च

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए 1993 के विशेष संदर्भ संख्या 1 (जिसे इसके बाद "विशेष संदर्भ" के रूप में संदर्भित किया गया है) और 1993 के विशेष संदर्भ संख्या 1 (जिसे इसके बाद "विशेष संदर्भ" के रूप में संदर्भित किया गया है) की स्थिरता निर्णय के लिए प्रश्न हैं।जिस पृष्ठभूमि में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, वह भारत सरकार द्वारा फरवरी 1993 में जारी अयोध्या पर श्वेत पत्र में बताए गए तथ्यों में निहित है।सुनवाई में उभरने वाले कुछ निर्विवाद तथ्य भी हो सकते हैं

इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता।इन प्रश्नों का उत्तर इस आधार पर दिया जाता है, उन तथ्यों को छोड़ते हुए जो विवाद के क्षेत्र में हैं और जिनका निर्णय लिया जाना बाकी है।

एक पृष्ठभूमि

च

विधेयक को उपरोक्त अधिनियम के नेतृत्व में संसद में पेश किया गया था और

इस न्यायालय का उक्त संदर्भ श्वेत पत्र में उल्लिखित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया गया था।वास्तव में, दोनों समान कार्य एक संकेत हैं।

:

कानून के अधिनियमन के लिए विधायी इरादे का, संदर्भ है

बी अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने की दृष्टि से उसी अभ्यास के एक भाग के रूप में बनाया गया है।उन्हें इस तरह से देखा जाना चाहिए।

अध्याय 1 में श्वेत पत्र के प्रारंभ में "अवलोकन"

इस प्रकार कहता हैः

1.1 .भारत के उत्तर में स्थित अयोध्या एक बस्ती है।

एस.

उत्तर प्रदेश का जिला फैजाबाद।यह लंबे समय से एक जगह रही है

महाकाव्य में इसके उल्लेख के कारण पवित्र तीर्थयात्रा का

श्री राम के जन्म स्थान के रूप में रामायण।संरचना

आमतौर पर राम जन्म भूमि के नाम से जानी जाने वाली बाबरी मस्जिद थी

1528 में अयोध्या में मीर बाकी द्वारा एक मस्जिद के रूप में बनाया गया था।

एडी।यह कुछ वर्गों द्वारा दावा किया जाता है कि इसे बनाया गया था

डी.

यह स्थल श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है जहाँ

मंदिर पहले खड़ा था।इसके परिणामस्वरूप एक लंबे समय तक

विवाद।

1.2 .दिसंबर, 1949 में विवादित ढांचे में मूर्तियों को रखने के साथ विवाद ने एक नए चरण में प्रवेश किया।द.

ई.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिसर कुर्क किए गए थे।इसके तुरंत बाद दीवानी मुकदमे दायर किए गए।इन दीवानी मुकदमों में अंतरिम आदेशों ने पक्षों को मूर्तियों को हटाने या उनकी पूजा में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।नतीजतन, दिसंबर, 1949 से 6 दिसंबर, 1992 तक इस संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया गया था।

च

विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी जो बड़े विवाद और तनाव का विषय बन गया। इसके कारण कई वार्ताएँ हुईं, जिनका विवरण वर्तमान उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।ये पार्ले

जी.

हालांकि, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (एआईबीएमएसी) इस विवाद को हल करने में विफल रहे।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा जून 1991 में उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के साथ मंदिर के निर्माण के अभियान में एक नया आयाम जोड़ा गया, जिसने मंदिर निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।

मंदिर का निर्माण और भूमि अधिग्रहण जैसे कुछ कदम उठाए

एच.

विवादित संरचना को छोड़ते हुए विवादित संरचना से सटे हुए एम. आई. फारूकी बनाम।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 17

स्वयं अधिग्रहण से।अक्टूबर 1991 से मंदिर निर्माण आंदोलन ए का ध्यान विवादित संरचना को अक्षुण्ण रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर 'कार सेवा' के माध्यम से मंदिर का निर्माण शुरू करना था।यह प्रयास सफल नहीं हुआ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय में भी मुकदमा चलाया गया।6 दिसंबर, 1992 से कार-सेवा को फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया था और आयोजकों द्वारा की गई घोषणा इस अदालत में लंबित कार्यवाही सहित अदालत के आदेशों के बी उल्लंघन के बिना एक प्रतीकात्मक कार-सेवा के लिए थी।6 तारीख को अयोध्या से प्रारंभिक रिपोर्टों के बावजूद

दिसंबर, 1992 सामान्य स्थिति का संकेत देते हुए, दोपहर के आसपास भाजपा, विहिप आदि के नेताओं द्वारा संबोधित एक भीड़ राम जन्मभूमि पर चढ़ गई।

बाबरी मस्जिद (आर. जे. एम.-बी. एम.) संरचना और गुंबदों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया।थोड़े ही समय में पूरी संरचना को ध्वस्त कर दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया।ग वास्तव में, यह "राष्ट्रीय शर्म" का कार्य था।जिसे ध्वस्त किया गया वह केवल एक प्राचीन संरचना नहीं थी; बल्कि न्याय और बहुमत की निष्पक्षता के अर्थ में अल्पसंख्यकों का विश्वास था।इसने कानून के शासन और संवैधानिक प्रक्रियाओं में उनके विश्वास को हिला दिया।एक पाँच सौ साल पुरानी संरचना जो रक्षाहीन थी और जिसकी सुरक्षा राज्य डी के हाथों में पवित्र विश्वास था

सरकार ध्वस्त हो गई।इस त्रासदी के विवरण का उल्लेख करने के बाद, "अवलोकन" पर अध्याय 1 में श्वेत पत्र इस प्रकार निष्कर्ष निकालता हैः—

" 1.25 .6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद संरचना का विध्वंस एक सबसे निंदनीय कार्य था। इस कृत्य के अपराधियों ने न केवल एक पूजा स्थल के खिलाफ हमला किया, बल्कि

धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांत

हमारे संविधान में निहित।अचानक से शर्मनाक कदम उठाते हुए, कुछ हजार लोगों ने सभी समुदायों के लाखों भारतीयों की भावनाओं को आहत करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने इस घटना पर पीड़ा और निराशा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 1.26 .6 दिसंबर, 1992 को जो हुआ वह समग्र रूप से व्यवस्था की विफलता नहीं थी, न ही भारत के संविधान में निहित ज्ञान की, न ही सहिष्णुता, भाईचारा और करुणा की शक्ति की, जिसने स्वतंत्र भारत के बारे में इतनी स्पष्ट रूप से जानकारी दी है।सर्वोच्च न्यायालय ने उस दिन कहा था, "यह बहुत अफ़सोस की बात है कि एक संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकी।

इस संवेदनशीलता और परिमाण के मामले में, "न्यायालय और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संसद और एच.

आई 18

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. लोगों को बस किनारे कर दिया गया था।इसमें विफलता से,

क.

उसमें विश्वासघात।

1.27 .आज भारत अपने घावों को भरने का प्रयास कर रहा है, न कि अपने घावों को फिर से खोलने का; उम्मीद के साथ आगे देखने का, न कि डर के साथ पीछे हटने का; विश्वास के साथ तर्क का सामंजस्य स्थापित करने का।इन सबसे ऊपर, भारत राष्ट्रीय एजेंडा के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

विचलन "।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि विवादित संरचना के प्रांगण के भीतर विवादित स्थल पर राम-चबूतरा नामक एक संरचना खड़ी थी।यह

संरचना को भी 6 दिसंबर, 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था (श्वेत पत्र का परिशिष्ट-V)।ऐसा प्रतीत होता है कि दिसंबर 1948 में विवादित ढांचे के राम-चबूतरे से मूर्तियों को स्थानांतरित करने से पहले, आम तौर पर हिंदू भक्तों द्वारा राम-चबूतरे पर स्थापित मूर्तियों की पूजा, मुसलमानों द्वारा उस स्थान पर इसकी पूजा के लिए बिना किसी आपत्ति के काफी समय तक की गई थी।6 दिसंबर, 1992 को भी राम चबूतरे के विध्वंस के परिणामस्वरूप, उस स्थान पर भी सामान्य रूप से हिंदुओं द्वारा की जाने वाली पूजा बाधित हो गई थी।इसके बाद, मूर्तियों की पूजा केवल जनता तक पहुंच के बिना इस उद्देश्य के लिए नामित पुजारी द्वारा की जा रही है।

इस संबंध में कुछ मुकदमों का संक्षिप्त संदर्भ अब दिया जा सकता है।1950 में, कुछ हिंदुओं द्वारा दो मुकदमे दायर किए गए थे; जनवरी 1950 में इनमें से एक मुकदमे में, निचली अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किए जिसके तहत मूर्तियां उसी स्थान पर रहीं जहां उन्हें दिसंबर 1949 में स्थापित किया गया था और हिंदुओं द्वारा उनकी पूजा जारी रही।अप्रैल 1955 में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश की पुष्टि की गई थी।1 फरवरी, 1986 को जिला न्यायाधीश ने विवादित ढांचे में मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाले ग्रिल पर रखे गए ताले को खोलने का आदेश दिया और एफ हिंदू भक्तों द्वारा पूजा की अनुमति दी।1959 में निर्मोही अखाड़े द्वारा विवादित ढांचे के स्वामित्व का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था।1961 में, सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित ढांचे के स्वामित्व का दावा करते हुए एक और मुकदमा दायर किया गया था।1969 में देवता के अगले मित्र के रूप में देवकी नंदन अग्रवाल ने विवादित ढांचे के संबंध में एक मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया।1969 में, उपरोक्त मुकदमों को जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया।14 अगस्त, 1989 को उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे (श्वेत पत्र का परिशिष्ट-I) के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।जैसा कि ईयरलर ने उल्लेख किया है, श्वेत पत्र के पैरा 1.2 में कहा गया है किः

1 " इन दीवानी मुकदमों में अंतरिम आदेशों ने पक्षों को मूर्तियों को हटाने या उनकी पूजा में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 19 वास्तव में, इसलिए, दिसंबर, 1949 से 8 दिसंबर, ए 1992 तक संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया गया था।

दिसंबर 1949 से पहले जब मूर्तियों को राम-चबूतरे से विवादित ढांचे में स्थानांतरित किया गया था, तब भी हिंदू भक्तों द्वारा राम चबूतरे पर मुसलमानों की कोई आपत्ति किए बिना लंबे समय तक पूजा की जाती थी।

विवाद से परे।हालाँकि, 1934 से दिसंबर 1949 तक मस्जिद के रूप में बी विवादित संरचना के उपयोग के बारे में एक विवाद उठाया गया है।एक संस्करण यह है कि 1934 में कुछ गड़बड़ी के बाद, विवादित संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में 1934 से ही बंद कर दिया गया था, न कि केवल दिसंबर 1949 से।दूसरा पक्ष दिसंबर 1949 से पहले नमाज के लिए मस्जिद के कथित उपयोग पर विवाद करता है।मुकदमों में उत्तर प्रदेश सरकार का रुख यह था कि 1949 तक इस स्थान का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जाता था।6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी की।

भारत का संविधान सभी कार्यों को अपने हाथ में लेता है

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया।श्वेत पत्र में अध्याय II में "पृष्ठभूमि" का उल्लेख किया गया है और उसमें डी का उल्लेख नीचे किया गया हैः

" 2.1 .आर. जे. बी-बी. एम. विवाद के केंद्र में मांग है।• विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और उसके सहयोगी संगठनों ने अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान कहे जाने वाले स्थल के जीर्णोद्धार के लिए आवाज उठाई।6 दिसंबर, 1992 तक इस ई स्थल पर

1528 में 'मीर बाकी' द्वारा बनाई गई संरचना का कब्जा था, जिन्होंने इसे पहले मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बनाने का दावा किया था।इस संरचना को पुराने सरकारी अभिलेखों में मस्जिद जन्मस्थान के रूप में वर्णित किया गया है।अब इसे आम तौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है।

च

2.2 .विहिप और उसके सहयोगी संगठन अपनी मांग इस दावे पर आधारित करते हैं कि यह स्थल श्री राम का जन्म स्थान है और इस स्थल की याद में एक हिंदू मंदिर तब तक यहाँ खड़ा रहा जब तक कि इसे बाबर के आदेश पर नष्ट नहीं कर दिया गया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया।विहिप की मांग को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जी समर्थन मिला है।द.

विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण, मौजूदा ढांचे को हटाने या स्थानांतरित करने के बाद, 1989 और 1991 में हुए चुनावों के दौरान भाजपा के अभियान में एक प्रमुख मुद्दा था।हालाँकि, अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने आम तौर पर इस मांग का विरोध किया था और यह रुख अपनाया था कि

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. मंदिर बनना चाहिए, विवादित मुद्दे होने चाहिए

क.

या तो बातचीत द्वारा या न्यायालय के आदेशों द्वारा हल किया जाता है।

2.2 .विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से बातचीत के दौरान, एक मुद्दा जो सामने आया वह यह था कि क्या उस स्थान पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था

विवादित संरचना द्वारा कब्जा कर लिया गया था और क्या यह था

मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया।मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ कुछ प्रतिष्ठित इतिहासकारों की ओर से कहा गया था कि इन दोनों में से किसी भी दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं था।कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा यह भी कहा गया था कि यदि ये दावे

एस.

यह साबित हो गया कि मुसलमान स्वेच्छा से विवादित मंदिर को हिंदुओं को सौंप देंगे।स्वाभाविक रूप से विहिप और ए. आई. बी. एम. ए. सी. के बीच बातचीत में यह केंद्रीय मुद्दा बन गया।

XXX

XXX

XXX

डी.

2.12 .इस प्रकार ऐतिहासिक बहस अनिर्णायक बनी हुई है, हालांकि सहमति और मतभेद के क्षेत्रों की पहचान करने में बहुत प्रगति हुई है।निर्णायक निष्कर्ष केवल सक्षम व्यक्ति के संदर्भ के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्राधिकरण।हालाँकि, जैसा कि इस पत्र में कहीं और सामने आया है, बातचीत एक महत्वपूर्ण चरण में बाधित हो गई थी।अब विवादित साक्ष्य के साथ-साथ पूरा सबूत गायब हो गया है।

ई.

संरचना।यह दुखद और विडंबनापूर्ण है कि राम-चबूतरा और कौशल्या रसोई, जो पूजा स्थलों के रूप में जारी रहे

मुस्लिम और ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों के हाथों में आर. जे. बी.-बी. एम. संरचना के साथ गायब हो गए हैं।

च

भगवान राम के 'भक्त' होने का दावा करना।

2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आर. जे. बी. के बाहरी प्रांगण में पूजा की हिंदू संरचनाएं पहले से मौजूद थीं।

जी.

बीएम संरचना।हालाँकि, 22/23 दिसंबर, 1949 की रात को हिंदू मूर्तियों को मुख्य संरचना के केंद्रीय गुंबद के नीचे रखा गया था।अगली सुबह से इन मूर्तियों की पूजा बड़े पैमाने पर शुरू की गई।चूंकि इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी, इसलिए नागरिक प्रशासन ने आपराधिक संहिता की धारा 145 के तहत परिसर को कुर्क कर लिया।

एच.

प्रक्रिया।यह एम. आई. फारूकी बनाम की एक पूरी श्रृंखला का प्रारंभिक बिंदु था।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 21 घटनाएं जो अंततः ए संरचना के विध्वंस का कारण बनीं।इस श्रृंखला की मुख्य घटनाओं का सारांश परिशिष्ट-I में दिया गया है।

2.14 .मूर्तियों की स्थापना के तुरंत बाद हिंदू वादियों द्वारा दो दीवानी मुकदमे दायर किए गए थे जिसमें मूर्ति की स्थापना पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

विवादित बी संरचना से मूर्तियों को हटाने या पूजा करने के इच्छुक भक्तों के रास्ते में कोई प्रतिबंध लगाने से प्रशासन।इस आशय के अंतरिम आदेश दीवानी अदालत द्वारा जारी किए गए थे।इन आदेशों की पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1955 में की थी।

2.15 .इस प्रकार 1949 से विवादित सी संरचना के अंदर हिंदू मूर्तियां बनी रहीं।हिंदुओं द्वारा इन मूर्तियों की पूजा भी 1949 से बिना किसी रुकावट के जारी रही और तब से मुसलमानों द्वारा पूजा करने के लिए इस संरचना का उपयोग नहीं किया जाता था।

तब।यह विवाद 1986 तक निम्न स्तर पर बना रहा जब फैजाबाद के जिला न्यायालय ने डी मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाले ग्रिल पर रखे गए ताले को खोलने का आदेश दिया।बाबरी मस्जिद एक्शन नामक एक संगठन

मुस्लिमों के लिए विवादित मंदिर की बहाली की मांग करने वाली समिति (बी. एम. ए. सी.) अस्तित्व में आई और एक विरोध आंदोलन शुरू किया।दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए जनमत जुटाने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दीं।6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण श्वेत पत्र के अध्याय VIII में देश में सांप्रदायिक स्थिति के संदर्भ में दिया गया है, जो 6 दिसंबर, 1992 को आर. जे. बी.-बी. एम. संरचना के विध्वंस के बाद तेजी से बिगड़ गई थी और कई अन्य राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी।

" 8.11 .सरकार द्वारा 7 दिसंबर को सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिए गए जी निर्णयों का ऊपर उल्लेख किया गया है।

विध्वंस से जुड़े अपराधों का अभियोजन, 6 दिसंबर की घटनाओं से संबंधित उनकी चूक के लिए विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए

ध्वस्त संरचना और एच 22 के संबंध में उचित कदम उठाना।

क.

नया राम मंदिर।अंतिम दो निर्णयों को 27 दिसंबर को आगे विस्तार से बताया गयाः

" सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों में विवादित सभी क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।उपयुक्त निकटवर्ती क्षेत्र का अधिग्रहण करने का भी निर्णय लिया गया है।उस क्षेत्र को छोड़कर अधिग्रहित क्षेत्र जिस पर विवादित संरचना है

राम मंदिर और मस्जिद के निर्माण और क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए दो न्यासों को स्टैंड उपलब्ध कराया जाएगा।

" भारत सरकार ने राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय की राय लेने का अनुरोध करने का भी निर्णय लिया है।

एस.

सवाल यह है कि क्या उस स्थान पर कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जहां विवादित संरचना खड़ी थी।सरकार ने उच्चतम न्यायालय की राय का पालन करने और न्यायालय की राय को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्णय लिया है।विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण के बावजूद, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यादेश की घोषणा से पहले की स्थिति तब तक बनी रहे जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपनी राय नहीं देता।इसके बाद न्यायालय की राय के आलोक में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा।इन निर्णयों के अनुसरण में एक अध्यादेश नामित किया गया

डी.

ई.

' राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में 1 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 7 जनवरी 1993 को 'अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश' जारी किया गया था।उसी दिन संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय का भी उल्लेख किया गया था।अध्यादेश की प्रति परिशिष्ट-XV में है और संदर्भ में

च

परिशिष्ट-XVI "।

अयोध्या अध्यादेश, 1993 (1993 का सं. 8) में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण को अयोध्या अधिनियम, 1993 (1993 का सं. 33) में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसकी संवैधानिक वैधता की हम जांच करेंगे।

जी.

उक्त अध्यादेश, जिसे बाद में 1993 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत विशेष संदर्भ उसी दिन 7 जनवरी, 1993 को एक साथ बनाए गए थे।यह होगा

इस स्तर पर, इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण, 1993 का उक्त अधिनियम संख्या 33 और विशेष

एच.

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भ।

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 23

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

क.

अयोध्या में पूर्ववर्ती राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद संरचना को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके कारण समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा होती रही और अंततः 6 दिसंबर, 1992 को विवादित संरचना को नष्ट कर दिया गया।यह बी था जिसके बाद व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में मौतें, चोटें और संपत्ति का विनाश हुआ।उक्त विवाद ने इस प्रकार देश में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव के रखरखाव

को प्रभावित किया है।चूंकि सांप्रदायिक सद्भाव और भारत के लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना 'सी' को बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए एक परिसर की स्थापना के लिए विवादित संरचना और उपयुक्त आस-पास की भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक माना गया, जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके जिसमें एक राम मंदिर, एक मस्जिद, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, एक पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य उपयुक्त सुविधाएं स्थापित की जा सकें।2. अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993 तदनुसार राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1993 को जारी किया गया था।उक्त अध्यादेश के आधार पर अध्यादेश की अनुसूची में निर्दिष्ट अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

केंद्र सरकार को सौंपना और निहित करना।

3. यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है।एस. बी. चव्हाण

फोटो एफ

नई दिल्ली;

9 मार्च, 1993 "।

1

विशेष संदर्भ

जी.

" जहाँ एक विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या एक हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना अस्तित्व में थी

संरचना का निर्माण (इस तरह के संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित, जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, उस क्षेत्र में जिसमें संरचना गांव कोट रामचंद्र में खड़ी थी)

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी.5 एस सी आर।

24

फैजाबाद तहसील में परगना हवेली अवध में अयोध्या

क.

सदर, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में

प्रदेश;

2. और जहाँ उक्त क्षेत्र राजस्व प्लॉट संख्या में स्थित है।159 और उक्त गाँव कोट रामचंद्र में 160;

3. और चूंकि उक्त विवाद ने देश में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव के रखरखाव को प्रभावित किया है;

1

4. और जहाँ कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर उपरोक्त क्षेत्र केंद्र सरकार में निहित है

ग

अयोध्या अध्यादेश, 1993;

5. और जहां उक्त अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार को उपरोक्त क्षेत्र सौंपने के बावजूद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करने के बाद उक्त विवाद को निपटाने का प्रस्ताव रखा है।

डी.

भारत का न्यायालय और उक्त राय के संदर्भ में;

6. और यहाँ पहले जो कहा गया है उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो प्रश्न उठाया गया है वह इस तरह का और सार्वजनिक है।

महत्वपूर्ण है कि राय प्राप्त करना समीचीन है

ई.

उस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय;

7. अब, इसलिए, शक्तियों के प्रयोग में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त, मैं, भारत के राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा, इसके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करता हूं।

च

उस पर विचार और राय के लिए भारत का न्यायालय,

अर्थात्ः

राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद (आंतरिक और बाहरी परिसर सहित) के निर्माण से पहले हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी।

जी.

ऐसी संरचना के प्रांगण) उस क्षेत्र में जिस पर संरचना खड़ी थी?

एसडी /

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली;

एच.

तिथि 7 जनवरी, 1993 "। एम. आई. फारूकी बनाम

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे. जे.

25

अयोध्या अधिनियम, 1993 में अधिदेश क्षेत्र की प्राप्ति (सं. 1993 का ए 33)

[3rd अप्रैल, 1993] "अयोध्या में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण और उससे जुड़े मामलों या आनुषंगिक बी के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम

वहाँ तक।

जहाँ इस संबंध में लंबे समय से विवाद चल रहा है

उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में फैजाबाद सदर तहसील के परगना हवेली अवध में अयोध्या के कोटस रामचंद्र गांव में स्थित संरचना (इस तरह की संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित), जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है;

और जहाँ उक्त विवाद ने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और विभिन्न लोगों के बीच सद्भाव को प्रभावित किया है

डी.

देश में समुदाय; और जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और भारत के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है; और जहाँ उपरोक्त ई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अयोध्या में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण करना आवश्यक है;

इसे संसद द्वारा संसद के चालीसवें वर्ष में अधिनियमित किया जाए।

भारत गणराज्य निम्नानुसार हैः

च

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम को अयोध्या अधिनियम, जी 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण कहा जा सकता है।

(2) यह 7 तारीख को लागू हुआ माना जाएगा।

जनवरी, 1993 का दिन। 2.इस अधिनियम में परिभाषाएँ जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ, 26

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. (ए) "क्षेत्र" से क्षेत्र (सभी भवनों सहित) अभिप्रेत है।

क.

संरचनाएँ या उसमें शामिल अन्य गुण) निर्दिष्ट

अनुसूची में;

((ख) "अधिकृत व्यक्ति" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है।

या केंद्र द्वारा प्राधिकृत किसी न्यास के न्यासी

धारा 7 के तहत सरकार;

(ग) "दावा आयुक्त" का अर्थ है दावे।

धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त आयुक्त; (घ) "विहित" का अर्थ है इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित।

एक्ट करें।

एस.

अध्याय II

आयुष में क्षेत्र की प्राप्ति

3. कुछ क्षेत्रों के संबंध में अधिकारों का अधिग्रहण-और

डी.

इस अधिनियम के प्रारंभ से, क्षेत्र के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा और निहित होगा।4. निहित करने का सामान्य प्रभाव (1) यह माना जाएगा कि इस क्षेत्र में सभी परिसंपत्तियां, अधिकार, पट्टा, शक्तियां, प्राधिकरण शामिल हैं।

ई.

और विशेषाधिकार और सभी चल और अचल संपत्ति, जिसमें भूमि, भवन, संरचनाएं, जो भी प्रकृति या अन्य संपत्तियों की दुकानें शामिल हैं और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित जो स्वामित्व में इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले थे,

च

किसी भी व्यक्ति या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का कब्जा, शक्ति या नियंत्रण, जैसा भी मामला हो, और सभी रजिस्टर, नक्शे, योजनाएं, चित्र और अन्य दस्तावेज

जो भी प्रकृति उससे संबंधित हो।

(2) उपर्युक्त सभी संपत्तियाँ जो केंद्र में निहित हैं

जी.

धारा 2 के तहत सरकार, इस तरह के निहित बल द्वारा, किसी भी न्यास, दायित्व से मुक्त और मुक्त हो जाएगी,

बंधक, प्रभार, ग्रहणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले अन्य सभी बोझ और किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई कुर्की, निषेधाज्ञा डिक्री या आदेश जो किसी भी तरह से ऐसी संपत्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है या किसी भी प्राप्तकर्ता को नियुक्त करता है।

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 27 ऐसी संपत्तियों के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में क

कोई प्रभाव डालना बंद करें।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, कोई वाद, अपील या

केंद्र में निहित किसी भी संपत्ति से संबंधित अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में अन्य कार्यवाही

धारा 3 के तहत सरकार किसी भी अदालत, बी ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

5. सभी परिसंपत्तियों आदि को वितरित करने के लिए क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति या राज्य सरकार का कर्तव्य-(1) केंद्र सरकार धारा 3 के तहत उस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है जो उस सरकार सी में निहित है।

(2) धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को क्षेत्र सौंपने पर, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निहित होने से ठीक पहले क्षेत्र के प्रबंधन का प्रभारी केंद्र सरकार या अधिकृत को देने के लिए बाध्य होगा।

व्यक्ति, सभी परिसंपत्तियाँ, रजिस्टर और उनकी अभिरक्षा में अन्य दस्तावेज जो इस तरह के निहित होने से संबंधित हैं या जहां यह नहीं है

ऐसे रजिस्टरों या दस्तावेजों को देने के लिए व्यवहार्य, ऐसे रजिस्टरों या दस्तावेजों की प्रतियां जो अधिनियम में प्रमाणित हैं।

निर्धारित तरीके से।

ई 6.केंद्र सरकार की क्षेत्र को किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या न्यास में निहित करने का निर्देश देने की शक्ति (1)

धारा 3,4,5 और 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि यह संतुष्ट हो जाती है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद स्थापित कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, या किसी न्यास के न्यासी, ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार

हैं या इच्छुक हैं जो वह सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू करने के लिए उचित समझे, कि अधिकार, स्वामित्व और ब्याज या उनमें से कोई भी

जे.

क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में, केंद्र सरकार में निहित रहना जारी रखने के बजाय, उस प्राधिकरण या जी निकाय या उस न्यास के न्यासियों में निहित होना।

अधिसूचना या ऐसी बाद की तारीख जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) जब क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में कोई अधिकार, स्वामित्व और हित प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों में निहित हो।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एस. सी. आर. केंद्र के ऐसे अधिकार

क.

सरकार को ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में, ऐसे निहित होने की तारीख को और उससे, उस न्यास के उस प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों का अधिकार माना जाएगा।

(3) धारा 4,5,7 और 11 के प्रावधान, जहाँ तक

ऐसे प्राधिकारी या निकाय या न्यासियों के संबंध में लागू हो सकता है जैसा कि वे केंद्र सरकार के संबंध में लागू होते हैं और इस उद्देश्य के लिए "केंद्र सरकार" के लिए उसमें दिए गए संदर्भों को ऐसे प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा।

ग

अध्याय III

संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन

7. सरकार द्वारा संपत्ति का प्रबंधन (1)

किसी अनुबंध में कुछ भी निहित होने के बावजूद या

डी.

इस अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके बाद से इसके विपरीत किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का लिखत या आदेश,

केंद्र सरकार में निहित संपत्ति

धारा 3 का प्रबंधन केंद्र सरकार या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या इस संबंध में उस सरकार द्वारा अधिकृत किसी न्यास के न्यासियों द्वारा किया जाएगा।

ई.

(2) धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन में, केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उस क्षेत्र में मौजूद स्थिति जिस पर संरचना (आंतरिक और बाहरी परिसर सहित) है।

एफ.

इस तरह की संरचना के प्रांगण), जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, गाँव कोट में स्थित था।

अयोध्या में रामचंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले के तेशील फैजाबाद सदर में परगना हवेली अवध में रखरखाव किया जाता है।.

जी.

अध्याय IV

असंसदीय

8. राशि का भुगतान-(1) क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति का मालिक।

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 29 केंद्र सरकार द्वारा उस भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति की धारा 3 के तहत उस सरकार को ए हस्तांतरण और निहित करने के लिए नकद में दिया जाएगा।

भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि।

(2) केंद्र सरकार, बी के उद्देश्य से, उप-धारा (1) के तहत मालिक या मालिक के खिलाफ दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के दावे पर निर्णय लेने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक दावा आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

(3) दावा आयुक्त दावों को प्राप्त करने और उन पर निर्णय लेने के लिए अपनी सी प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(4) मालिक या मालिक के खिलाफ दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति दावे की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर दावा आयुक्त के पास दावा कर सकता है।

इस अधिनियम का प्रारम्भः.

डी.

बशर्ते कि यदि दावा आयुक्त संतुष्ट हो कि दावेदार को पर्याप्त कारण से रोका गया था

नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर दावे को प्राथमिकता देते हुए, दावा आयुक्त नब्बे दिनों की आगे की अवधि के भीतर दावे पर विचार कर सकता है और उसके बाद नहीं।ई 9.अन्य सभी अधिनियमों को ओवरराइड करने के लिए अधिनियम-इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे।

इस अधिनियम या किसी डिक्री या आदेश के अलावा किसी अन्य कानून या किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी साधन में असंगत

किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का।10. दंड कोई भी व्यक्ति जो इसके प्रभारी है

क्षेत्र का प्रबंधन और केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र से संबंधित अपनी अभिरक्षा में कोई संपत्ति, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या, जैसा भी मामला जी हो, ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतियां देने में विफल रहने पर, तीन साल तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

11. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण-एच 1 के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

30

केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति या इनमें से कोई भी

क.

उस सरकार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी या

सद्भावना से की गई किसी भी चीज़ के लिए अधिकृत व्यक्ति

या इस अधिनियम के तहत करने का इरादा है।

12. नियम बनाने की शक्ति (1) केंद्र सरकार

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकते हैं -

इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना।

(2) इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में होगा, कुल मिलाकर रखा जाएगा।

एस.

तीस दिनों की अवधि जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र या उपरोक्त सत्र के तुरंत बाद के सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद बनाया जाएगा।

डी.

प्रभाव केवल ऐसे संशोधित रूप में होता है या कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

उस नियम के तहत पहले किया गया कुछ भी।

13. निरसन और बचत-(1) के प्रावधानों के अधीन

ई.

उप-धारा (2), अयोध्या अध्यादेश, 1993 में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त में कुछ भी निहित होने के बावजूद

अध्यादेश, -

च

(क) गाँव कोट रामचंद्र में स्थित भूखंड सं. 242 के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित सं.उक्त अध्यादेश की अनुसूची की संख्या 1 को कभी भी केंद्र सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया और उसमें निहित नहीं माना जाएगा।

जी.

(ख) किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित उक्त भूखंड संख्या 242 से संबंधित अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही कभी भी कम नहीं हुई मानी जाएगी और ऐसा मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही (उस पर किसी भी न्यायालय के आदेश या अंतरिम आदेशों सहित) को बहाल किया गया समझा जाएगा।

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 31 ए से तुरंत पहले मौजूद स्थिति

उक्त अध्यादेश का प्रारंभ;

(ग) उक्त प्लॉट संख्या 242 के संबंध में उस अध्यादेश के तहत की गई कोई अन्य कार्रवाई या की गई चीज कभी नहीं की गई या नहीं की गई मानी जाएगी।

(3) इस तरह के निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।

एस.

अनुसूची

[खंड 2 (ए) देखें]

क्षेत्र का विवरण

XXX "D

XXX

XXX

सुनवाई में यह पुरजोर आग्रह किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भित तथ्य का सवाल अस्पष्ट है; इसका जवाब क्या है।

यह अपने आप में वास्तविक विवाद का निर्णायक नहीं है क्योंकि मुख्य प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है, और यह इस बात का भी कोई निश्चित संकेत नहीं देता है कि विशेष संदर्भ का उत्तर दिए जाने के बाद केंद्र सरकार विवाद को निपटाने के लिए किस तरह से कार्य करना चाहती है।यह आग्रह किया गया था कि संदर्भित प्रश्न अस्पष्ट होने के अलावा, अकादमिक है, और यह किसी भी संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है जिसे इस न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सके; कि संदर्भ का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य मुसलमानों के पूजा स्थल को छीनना और इसे हिंदुओं को देना है जो धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता को आहत करता है; और इसलिए, हमें विशेष संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करना चाहिए।भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।प्रारंभ में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह कहा गया था कि प्रश्न का उत्तर विवाद को निपटाने के लिए विभिन्न समूहों के बीच आगे की बातचीत का आधार प्रदान करेगा और केंद्र सरकार तब विवाद को हल करने के लिए उसके लिए उपलब्ध प्रभावी मार्ग तय करने में सक्षम होगी।विशेष संदर्भ के उद्देश्य के बारे में केंद्र सरकार के रुख को और स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने 14 सितंबर, 1994 को भारत संघ की ओर से लिखित रूप में एक बयान दियाः- एच.

ई.

42.

जी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी.5 एस सी आर।

32

" सरकार धर्मनिरपेक्षता की नीति पर कायम है और

क.

सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार।अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण के साथ-साथ राष्ट्रपति के संदर्भ का उद्देश्य हैः

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना

सौहार्द और दोनों देशों के बीच साझा भाईचारे की भावना

भारत के लोग।

सरकार राम मंदिर और मस्जिद के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उनके वास्तविक स्थान का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में अपनी राय देने के बाद ही किया जाएगा।

एस.

सरकार संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भित तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष को एक निर्णय के रूप में मानेगी जो अंतिम और बाध्यकारी है।

उच्चतम न्यायालय की राय के आलोक में और उसके अनुरूप, सरकार इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगी।

डी.

वार्ता की एक प्रक्रिया द्वारा विवाद।सरकार को विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय की राय का समुदायों के दृष्टिकोण पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा और वे अब तथ्यात्मक मुद्दे पर परस्पर विरोधी रुख नहीं अपनाएंगे

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया।

ई.

यदि ऊपर बताए गए समझौते पर बातचीत के प्रयास सफल नहीं होते हैं।सरकार उच्चतम न्यायालय की राय के आलोक में और उसके अनुरूप समाधान लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।इस संबंध में सरकार की कार्रवाई दोनों समुदायों को सौंपी जाएगी।यदि निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, अर्थात्, ध्वस्त संरचना के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर/संरचना मौजूद थी। सरकार की कार्रवाई होगी

च

हिंदू समुदाय की इच्छाओं का समर्थन।यदि, दूसरी ओर, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है, अर्थात्, वहाँ ऐसा कोई हिंदू मंदिर/संरचना मौजूद नहीं थी।

जी.

जे.

प्रासंगिक समय, तब सरकारी कार्रवाई मुस्लिम समुदाय की इच्छाओं के समर्थन में होगी।

विद्वान महान्यायवादी द्वारा लिखित रूप में दिया गया यह बयान

भारत संघ की ओर से रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनता है और इसे लिया जाना चाहिए।उस उद्देश्य को इंगित करने के लिए जिसके लिए विशेष संदर्भ के तहत

एच.

इस न्यायालय को अनुच्छेद 143 (1) दिया गया है।

3 एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 33

विवाद और इसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख पैरा 2.1,2,2 और 2.3 ए में किया गया है।

श्वेत पत्र के अध्याय द्वितीय का उल्लेख पहले किया गया था।यह वह पृष्ठभूमि है जिसमें 1993 के अधिनियम संख्या 33 की संवैधानिक वैधता और

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत किए गए विशेष संदर्भ की स्थिरता की जांच की जानी चाहिए।

अल।

अधिनियम सं. की वैधता।33 1993 का

मोटे तौर पर, समग्र रूप से क़ानून को चुनौती देने का ध्यान धर्मनिरपेक्षता, समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर है।विवादित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए चुनौती इस आधार पर भी है कि अधिग्रहण अनावश्यक था क्योंकि यह उसके भीतर के छोटे विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद से असंबंधित था।अधिनियम पर काफी उग्रता से हमला करने वाले कुछ पक्षों की ओर से एक बड़ा सी तर्क दिया गया है कि एक मस्जिद का स्थान

मुसलमानों द्वारा धार्मिक पूजा, स्वतंत्र रूप से कि क्या अधिग्रहण ने धर्म का पालन करने के अधिकार को प्रभावित किया, राज्य की अधिग्रहण की शक्ति से पूरी तरह से मुक्त है और इसलिए, क़ानून असंवैधानिक है क्योंकि केवल इसी कारण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है।हालाँकि, अन्य लोगों ने अधिग्रहण से प्रतिरक्षा के इस तर्क को केवल विशेष महत्व के स्थानों तक सीमित कर दिया, जिससे धर्म का पालन करने के अधिकार का एक आवश्यक और अभिन्न हिस्सा बन गया, जिसके अधिग्रहण के परिणामस्वरूप स्वयं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा।यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अधिग्रहण का उद्देश्य कानून को प्रविष्टि 42, सूची III के दायरे में नहीं लाता है, बल्कि ई प्रविष्टि 1, सूची II के लिए संदर्भित है और इसलिए, संसद के पास इसे लागू करने की क्षमता नहीं है।इसके बाद विद्वान वकील ने मुस्लिम हित का प्रचार करते हुए आग्रह किया कि यह कानून हिंदू हितों के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है और इसलिए, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के अलावा गैर-धर्मनिरपेक्षता और भेदभाव के दुष्प्रभावों से ग्रस्त है।उनके द्वारा यह भी आग्रह किया गया कि 7 दिसंबर, 1992 को प्रधानमंत्री के बयान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री सरकार ने ध्वस्त ढांचे (श्वेत पत्र के अध्याय 1 में पैरा 1,22) के पुनर्निर्माण के लिए और कानून में कुछ प्रावधानों को शामिल करके जी में ढांचे के विध्वंस के कार्य द्वारा मुस्लिम समुदाय के साथ किए गए अन्याय को कायम रखने का प्रयास किया है।

6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या।मुस्लिम समुदाय की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत निर्दिष्ट प्रश्न की सामग्री के संदर्भ में पढ़ा गया कानून, जैसा कि होना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए एक उपकरण को केवल छिपाना है।

6 तारीख को मस्जिद के विध्वंस के परिणामों को कायम रखें

दिसंबर, 1992।हिंदू विरोधियों की शिकायत है कि शरारत एच सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एसयूपीपी।

5 एस सी आर।

34

ए और कुछ लोगों द्वारा की गई बर्बरता के कृत्यों के लिए पूरे हिंदू समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश इस शर्मनाक कृत्य से समान रूप से आहत हैं और इसकी आलोचना करते हैं।वे आग्रह करते हैं कि बहुमत द्वारा यह अस्वीकृति

समुदाय बाद के चुनावों के परिणाम से स्पष्ट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हिंदू बहुमत द्वारा खारिज कर दिया गया था।उनका यह भी कहना है कि विवादित स्थल पर सदियों से मौजूद राम-चबूतरा और कौशल्या रसोई जैसी हिंदू संरचनाओं को ध्वस्त करने के तथ्य की अनदेखी की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के भीतर हिंदुओं के पूजा के निर्विवाद अधिकार में भी बाधा आई है।यह भी तर्क दिया जाता है कि विवादित क्षेत्र से अधिक किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए, कम से कम हिंदुओं से संबंधित अतिरिक्त क्षेत्र का अधिग्रहण, निश्चित रूप से, अमान्य है।

एस.

केंद्र सरकार की ओर से, यह आग्रह किया जाता है कि मौजूदा स्थिति में और व्यापक रूप से फैले सांप्रदायिक प्रकोप को देखते हुए

6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में हुई घटनाओं के कारण, केंद्र सरकार की राय में सबसे उपयुक्त तरीका यह था कि यह अधिग्रहण विशेष संदर्भ के साथ किया जाए ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि

डी.

प्रश्न जो समस्या के बातचीत से समाधान की सुविधा प्रदान करेगा, और यदि यह विफल रहता है, तो केंद्र सरकार को विवाद को हल करने और देश में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए कोई अन्य उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा।यह स्पष्ट किया गया था कि विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण का उद्देश्य उस समुदाय को वंचित करना नहीं था जो इसके लिए हकदार पाया जाता है, या अतिरिक्त क्षेत्र के किसी भी हिस्से को बनाए रखना नहीं था जो विवाद के उचित समाधान के लिए या अधिग्रहण के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक नहीं था, यह प्रस्तुत किया गया था कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव का आश्वासन एक प्रमुख संवैधानिक उद्देश्य था और 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में हुई घटना के मद्देनजर विवाद को बढ़ाना उस दिशा में एक आवश्यक कदम था, जो निस्संदेह धर्मनिरपेक्षता के पंथ को बढ़ावा देता है न कि इसे खराब करने के लिए।यह आरोप लगाया गया था कि

ई.

च

केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ या धर्मनिरपेक्षता विरोधी भेदभाव का आरोप लगाना पूरी तरह से अनुचित है।मुस्लिम समुदाय की ओर से एक और तर्क दिया गया कि दूसरे पक्ष द्वारा दायर मुकदमों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बचाव खुला है, जिसमें लंबे समय तक कब्जे के आधार पर प्रतिकूल कब्जा भी शामिल है।

जी.

1528 ईस्वी में इसके निर्माण के बाद से 400 से अधिक वर्षों से विवादित स्थल का अधिग्रहण भी समाप्त हो गया है, जिससे दूसरे पक्ष को अनुचित लाभ हुआ है।यह भी आग्रह किया गया कि पक्षों के बीच विवाद में मुख्य प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत किए गए विशेष संदर्भ का विषय नहीं था और इसलिए, एच के जवाब के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान नहीं होगा।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 35

सूट।तदनुसार यह आग्रह किया गया था कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के प्रतिस्थापन के बिना विवाद के निर्णय के लिए न्यायिक ए उपाय से वंचित है, जो संविधान के तहत अस्वीकार्य है।

इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले तर्कों से निपटने से पहले इस स्तर पर क़ानून के प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है।B उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है जिसके कारण

समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा ने अंततः 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसके बाद व्यापक रूप से सांप्रदायिक हिंसा फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कई लोगों की जान चली गई और संपत्ति का नुकसान हुआ।उक्त विवाद सी ने इस प्रकार देश में सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के रखरखाव को प्रभावित किया है।जाहिर है, भारत के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखना और बढ़ावा देना आवश्यक है।इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विवादित संरचना के स्थान का अधिग्रहण करना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित तरीके से आवश्यक आस-पास के क्षेत्र का उपयोग करना आवश्यक समझा गया।इस उद्देश्य के लिए, अयोध्या में निश्चित डी क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1993 को जारी किया गया था और साथ ही, उसी दिन, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय को यह संदर्भ भी दिया गया था।उक्त अध्यादेश को अधिग्रहण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

अयोध्या अधिनियम, 1993 (1993 का सं. 33) के कुछ क्षेत्र में इसी प्रभाव के लिए, ई (1) और धारा 1 (2) में प्रावधान है कि अधिनियम 7 जनवरी, 1993 को लागू हुआ माना जाएगा।उक्त अधिनियम के प्रावधानों पर अब विचार किया जाता है।

धारा 3 धारा 2 (ए) में परिभाषित "क्षेत्र" के संबंध में अधिकारों के अधिग्रहण का प्रावधान करती है।यह कहता है कि इस एफ अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके बाद से क्षेत्र के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित, इसके आधार पर होगा

अधिनियम, केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाता है और निहित किया जाता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "बनियान" का अर्थ उस संदर्भ से रंग लेता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और यह जरूरी नहीं कि हर प्रावधान या हर संदर्भ में समान हो।महाराज सिंह बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1977] 1 एस. सी. आर. 1072 पृष्ठ 1081 पर, यह आयोजित किया गया था,

जी.

" ..... क्या एक ही खंड में दो अलग-अलग इंद्रियों में 'निहित' करने की ऐसी रचना ध्वनि है?हां.ऐसा इसलिए है क्योंकि 'वेस्टिंग' फिसलन भरा शब्द है और इसके कई अर्थ हैं।संदर्भ पाठ को नियंत्रित करता है और उद्देश्य और योजना एच 36 की विशेष शब्दार्थ छाया या बारीकियों को प्रस्तुत करती है।

अर्थ।यही कारण है कि परिभाषा खंड भी अनुमति देते हैं

क.

स्वयं को प्रासंगिक मजबूरियों द्वारा संशोधित किया जाए।

कानून की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में धारा 3 और धारा 6 में "निहित" का अर्थ महत्वपूर्ण है।इसके उपयोग के बी संदर्भ के आधार पर यह क़ानून के विभिन्न हिस्सों या यहां तक कि एक ही धारा में भी भिन्न हो सकता है।

धारा 4 तब वेस्टिंग का सामान्य प्रभाव प्रदान करती है।जाहिर है, वेस्टिंग का प्रभाव धारा 3 में उपयोग किए गए "वेस्ट" शब्द के अर्थ और वर्तमान संदर्भ में वेस्टिंग के प्रकार पर निर्भर करेगा।की उप-धारा (i)

धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि इस क्षेत्र में सभी परिसंपत्तियां, अधिकार आदि शामिल माने जाएंगे, जो भी प्रकृति से संबंधित हों।उप-धारा (2) में आगे कहा गया है कि उपरोक्त सभी संपत्तियां जो धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित हैं, उन्हें इस तरह के निहित होने के बल पर मुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी बोझों से मुक्त किया जाएगा और किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई कुर्की, निषेधाज्ञा, डिक्री या आदेश जो किसी भी तरह से ऐसी संपत्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है या संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में किसी भी डी रिसीवर की नियुक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।दूसरे शब्दों में, इस तरह के निहित होने का प्रभाव उन सभी संपत्तियों को मुक्त करना है जो सभी बाधाओं की धारा के तहत केंद्र सरकार में निहित हैं और किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश के परिणामस्वरूप उनके उपयोगकर्ता को किसी भी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।धारा 4 की उप धारा (3) सभी लंबित मुकदमों और ई कानूनी कार्यवाही को कम करने का प्रावधान करती है।धारा 3 में "निहित" शब्द का अर्थ इस प्रावधान की वैधता पर असर डालता है क्योंकि मुकदमों आदि के उपशमन का परिणाम यह है कि इसमें केवल विवादित क्षेत्र के पूर्ण निहित होने से संबंधित है जो मुकदमों का विषय है और ऐसी स्थिति से संबंधित नहीं है जहां धारा 3 के तहत निहित होना किसी विशेष उद्देश्य के लिए सीमित प्रकृति का है, और भविष्य की घटना होने तक सीमित अवधि का है।एफ धारा 5 क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति या राज्य सरकार के कर्तव्य को इंगित करती है कि वह सभी परिसंपत्तियों आदि को केंद्र को वितरित करे।

सरकार इस तरह के निहित पर।उप-धारा (1) केंद्र सरकार को धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देती है।उप-धारा (2) क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निहित होने से ठीक पहले केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति को ऐसी निहित होने से संबंधित उनकी अभिरक्षा में सभी संपत्तियों आदि को देने के लिए बाध्य करती है।संक्षेप में, धारा 5 केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति या राज्य सरकार के संबंधित दायित्व के साथ की जाने वाली परिणामी कार्रवाई का प्रावधान करती है, ताकि इस तरह के निहित होने पर केंद्र सरकार को इसके प्रबंधन के साथ क्षेत्र का कब्जा दिया जा सके।

इसके बाद धारा 6 आती है जो अध्याय ए II का अंतिम खंड है, जिसका विस्तृत संदर्भ बाद में दिया जाएगा।इस स्तर पर इसकी सामग्री का एक सामान्य संदर्भ पर्याप्त है।धारा 6 में केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति है

क्षेत्र को किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या न्यास में निहित करना।

उप-धारा (1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, धारा 3,4,5 और 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि अधिकार, स्वामित्व और ब्याज या उनमें से कोई भी क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में, केंद्र सरकार में निहित रहने के बजाय, निर्दिष्ट तिथि से उस न्यास के उस प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों में निहित हो।यदि यह संतुष्ट है कि वही ऐसी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है और

च

शर्तें जो केंद्र सरकार उचित समझे

अधिरोपित करें।संक्षेप में, उप-धारा (1) केंद्र सरकार को उस क्षेत्र या उसके किसी भाग में अपने या उनमें से किसी भी अधिकार, स्वामित्व और हित को किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय या किसी न्यास के न्यासियों को ऐसे नियमों और शर्तों पर हस्तांतरित करने का अधिकार देती है जो वह उचित समझे।

केंद्रीय ई सरकार द्वारा इस तरह के हस्तांतरण के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए यह घोषणा की जाए कि ट्रांसफ्री तब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र या उसके हिस्से में वही अधिकार, अधिकार और ब्याज प्राप्त करेगा जो अधिनियम के आधार पर पहले केंद्र सरकार में निहित था।उप-धारा (2) धारा (1) के तहत की गई कार्रवाई का एक और परिणाम है और यह प्रावधान करता है कि धारा 4, एफ 5,7 और 11 जहां तक हो सके, ऐसे ट्रांसफ्री पर लागू होंगी जैसा कि वे केंद्र सरकार के संबंध में लागू होती हैं। यह हो सकता है

यहाँ यह याद किया जाना चाहिए कि धारा 4 के प्रभाव से संबंधित है

धारा 3 के तहत निहित करना; धारा 5 केंद्र सरकार या अधिकृत जी व्यक्ति को कब्जा आदि देने के लिए क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति या राज्य के कर्तव्य के लिए।धारा 7 केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन को उसके निहित होने पर; और धारा 11 केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति या इस अधिनियम के तहत उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा सद्भावना से की गई कार्रवाई को सुरक्षा प्रदान करती है।

एच 38

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. अध्याय 3 में केवल धारा 7 है जिस पर इसकी संवैधानिक वैधता को दी गई गंभीर चुनौती को देखते हुए बाद में विस्तार से विचार किया जाएगा।यह धारा केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित है, इसके निहित होने पर, उप-धारा (1) केंद्र सरकार द्वारा या किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा धारा 2 के तहत केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन के लिए प्रावधान करती है, किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी अनुबंध या लिखत या आदेश में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद।दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के प्रारंभ से किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के दस्तावेज या आदेश के किसी भी अनुबंध में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, केंद्र में निहित संपत्ति का प्रबंधन

धारा 2 के तहत सरकार केंद्र सरकार द्वारा या एक सी अधिकृत व्यक्ति द्वारा होगी, जो सरकार द्वारा अपनी ओर से इस प्रकार अधिकृत है और कोई और नहीं।यह प्रावधान केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित किसी भी पूर्व प्रावधान को स्पष्ट रूप से हटा देता है।उप-धारा (2) तब केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति के प्रबंधन के तरीके का प्रावधान करती है।यह आदेश देता है कि

केंद्र सरकार या धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित संपत्ति डी के प्रबंधन में अधिकृत व्यक्ति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मौजूद स्थिति उस क्षेत्र में है जिस पर संरचना (आंतरिक और बाहरी परिसर सहित) है।

इस तरह की संरचना के प्रांगण), जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, का रखरखाव किया जाता है।इसका अर्थ है कि धारा 7 की ई उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति के प्रबंधन की शक्ति को उप-धारा (2) द्वारा दिए गए अधिदेश में निहित कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है।अधिदेश यह है कि केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन में, केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति उस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा जिस पर संरचना (ऐसी संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित), जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि के रूप में जाना जाता है।

एफ बाबरी मस्जिद, खड़ी थी "।इस संदर्भ में "क्षेत्र" शब्द के अर्थ को लेकर कुछ बहस हुई थी।एक सुझाव यह था कि इस अभिव्यक्ति में उपयोग किए गए शब्द "क्षेत्र" का वही अर्थ है जो धारा 2 (ए) में निहित परिभाषा में है, यानी अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट पूरा क्षेत्र।धारा 2 स्वयं कहती है कि उसमें परिभाषाएँ परिभाषित शब्दों का अर्थ देती हैं "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो"।संदर्भ में

जी, जिसका उपयोग धारा 7 (2) में अभिव्यक्ति में "क्षेत्र" शब्द में किया गया है, यह स्पष्ट संकेत देता है कि इसका अर्थ धारा 2 (ए) के समान नहीं है, जिसका अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट पूरे क्षेत्र से है।

इसका अर्थ यह है कि यह केवल उस स्थान तक सीमित है जिस पर यह संरचना, जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, कौन सा स्थान या क्षेत्र निस्संदेह छोटा है और "एच अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र" के भीतर है। एम. आई. फारूकी बनाम

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 39

अध्याय IV में विविध प्रावधान हैं।इसमें धारा 8 ए केंद्र सरकार द्वारा भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के भुगतान का प्रावधान करती है।

धारा 3 के तहत सरकार को संपत्ति का हस्तांतरण और उसे उसके मालिक को सौंपना।धारा 8 के शेष भाग में राशि के भुगतान के लिए तंत्र के प्रावधान शामिल हैं।धारा 9 इस अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी अन्य कानून या किसी भी अदालत, बी न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के डिक्री या आदेश पर प्रबल प्रभाव डालती है।धारा 10 दंड का प्रावधान करती है।इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्र के प्रबंधन का प्रभारी है और केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत आवश्यक कब्जा आदि देने में विफल रहता है, वह प्रदान किए गए तरीके से दंडनीय होगा।धारा 11 केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत सद्भावना से किए गए या किए जाने के इरादे से कुछ भी करने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।धारा 12 में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति और नियम बनाने का तरीका शामिल है।धारा 13 अधिनियम की अंतिम धारा है जो पहले के अध्यादेश और बचत को निरस्त करने का प्रावधान करती है।

पूर्वगामी डी के अधिनियम संख्या 33 के प्रावधानों का एक संक्षिप्त विवरण है।

1993 , जिसकी संवैधानिक वैधता की जाँच चुनौती के आधारों के आलोक में की जानी चाहिए।धारा 2 में "निहित" शब्द का अर्थ और उसके द्वारा विचार किए गए निहित होने का प्रकार, धारा 4 के अनुसार सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में कमी सहित निहित होने का प्रभाव, केंद्र सरकार की क्षेत्र या किसी भी हिस्से को निहित करने का निर्देश देने की शक्ति

केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति के प्रबंधन के लिए प्रावधान करने वाली धारा 6 और धारा 7 के अनुसार किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या न्यास में इसका प्रभाव निम्नलिखित प्रावधान हैं -

संवैधानिकता के प्रश्न को तय करने के लिए विशेष महत्व।इस संदर्भ में धारा 8 का भी कुछ महत्व है।

अब हम उन आधारों के गुणागुण पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिन पर अधिनियम को संवैधानिक रूप से अमान्य माना जाता है।

विधायी प्रतिस्पर्धा विधायी क्षमता का पता प्रविष्टि 42 से लगाया जा सकता है।सूची III और

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रासंगिक समय पर राष्ट्रपति शासन होने के कारण, इन परिस्थितियों में संसद की जी विधायी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, कानून का सार और सार "संपत्ति का अधिग्रहण" है और यह पूरी तरह से प्रविष्टि 42, सूची III के दायरे में आता है।"सार्वजनिक व्यवस्था" से संबंधित प्रतियोगी प्रविष्टि प्रविष्टि 1, सूची 2 है।

" "सार्वजनिक व्यवस्था" के बजाय "संपत्ति का अधिग्रहण" मुख्य और सार है

कानून का।

40

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 बिहार राज्य में एस. सी. आर. ए बनामदरभंगा के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह और अन्य, [1952] एस. सी. आर. 889, यह बताया गया कि जहां अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य राज्य को हस्तांतरण करना था

भूमि के मालिकों और कार्यकाल धारकों के हितों, कानून का सार और सार राज्य सरकार को स्वामित्व का हस्तांतरण था और यह एक "अधिग्रहण" अधिनियम था।उपायुक्त और बी कलेक्टर, कामरूप और अन्य।वी.दुर्गा नाथ सरमा, [1968] 1 एस. सी. आर. 561, बचावत, जे. ने बताया कि संपत्ति के स्थायी अधिग्रहण के लिए एक कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि को बढ़ावा देने के लिए कानून नहीं है क्योंकि केवल

निजी संपत्तियों के अस्थायी कब्जे को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक कानून के रूप में माना जा सकता है।

एस.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रविष्टि 42, सूची III, जैसा कि अब मौजूद है, को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।• इसके अंतर्गतः

" संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण।

डी.

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम से पहले, प्रासंगिक प्रविष्टियां इस प्रकार थीं:

" सूची I, प्रविष्टि 33:

के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण या अधिग्रहण

ई.

संघ।

सूची II, प्रविष्टि 36:

प्रविष्टि 42 के प्रावधानों के अधीन, संघ के उद्देश्यों को छोड़कर, संपत्ति का अधिग्रहण या अधिग्रहण

च

सूची III।

सूची III, प्रविष्टि 42:

जिन सिद्धांतों पर अर्जित संपत्ति के लिए मुआवजे की मांग संघ या किसी राज्य के प्रयोजनों के लिए की जाती है या

जी.

किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाना है, और जिस रूप और तरीके से ऐसा मुआवजा दिया जाना है

दिया गया "।

इस प्रकार किए गए संशोधन द्वारा, प्रविष्टि 42, सूची III को पहले निकाले गए एच के रूप में पढ़ा जाता है जबकि प्रविष्टि 22, सूची I और प्रविष्टि 26, सूची II को हटा दिया गया है।

एम. आई. फारूकी बनाम।यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 41

संविधान (सातवां ए संशोधन) अधिनियम के परिणामस्वरूप सूची III में व्यापक प्रविष्टि 42 इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि इस तरह का अधिग्रहण अधिनियम इस प्रविष्टि के दायरे में स्पष्ट रूप से विफल रहता है और इसलिए, इस कानून को लागू करने के लिए संसद की विधायी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।इसलिए, चुनौती का यह आधार खारिज कर दिया गया है।

धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और बी समानता का अधिकार

धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हमले पर विचार करना अब उचित होगा, जो दो परिचर अधिकारों के साथ संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।तर्क यह है कि यह अधिनियम समग्र रूप से हिंदू समुदाय के पक्ष में और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता विरोधी है क्योंकि यह सी मस्जिद को ध्वस्त करने का प्रयास करता है, जो विवादित स्थल पर फैली हुई है, न कि इसके पुनर्निर्माण की तार्किक न्यायसंगत कार्रवाई का प्रावधान करने के लिए।

परिस्थितियों में उपयुक्त।यह आग्रह किया जाता है कि धारा 4 (3) में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

1528 ईस्वी से 400 से अधिक वर्षों तक मुस्लिम समुदाय को अपने बचाव से वंचित करने वाले सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को समाप्त करना, जब मीर डी बाकी द्वारा उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, एक वैकल्पिक

विवाद समाधान तंत्र प्रदान किए बिना, और इस तरह यह मुस्लिम समुदाय को उस न्यायिक उपचार से वंचित करता है जिसका वह कानून के शासन के तहत संवैधानिक योजना में हकदार है।यह आग्रह किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय को संविधान की धारा 143 (1) के तहत विशेष संदर्भ मूल प्रश्न का नहीं है, जिसका उत्तर स्वतः ही विवाद का समाधान कर देगा, बल्कि केवल एक अस्पष्ट और ई काल्पनिक मुद्दे का है, जिसका उत्तर एक कानूनी मुद्दे के रूप में विवाद के समाधान में मदद नहीं करेगा।यह भी आग्रह किया जाता है कि धारा 6 विवादित स्थल पर वास्तविक स्वामित्व के संदर्भ के बिना केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्राधिकरण, निकाय या न्यास को विवादित क्षेत्र सहित अधिग्रहित संपत्ति के हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा 7 7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देकर मस्जिद के विध्वंस की शरारत को कायम रखती है, जो हिंदुओं को विवादित स्थल में मुसलमानों को उस क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर रखते हुए किसी भी प्रकार की पूजा के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है और केंद्र सरकार द्वारा इस भेदभाव को किसी भी समय तक कायम रखा जा सकता है।यह आग्रह किया जाता है कि धारा 7 के प्रावधान में इस शरारत को कायम रखने की क्षमता है।धारा 8 का संदर्भ यह सुझाव देने के लिए भी दिया गया था कि यह अर्थहीन है क्योंकि विवादित स्थल पर स्वामित्व के सवाल का फैसला किया जाना बाकी है और

९

सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को कम करने के लिए, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके द्वारा इसका निर्णय लिया जा सके।धारा 8 पर आपत्ति स्पष्ट रूप से उस विवादित क्षेत्र के संदर्भ में है जिस पर स्वामित्व विवाद में है और अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट शेष क्षेत्र के लिए नहीं, जिसका स्वामित्व

एच 42

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. जो विवादित नहीं है।अधिग्रहण की वैधता को अन्य लोगों द्वारा भी चुनौती दी जाती है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो कुछ अधिग्रहित संपत्तियों के मालिक हैं और जिनके मामले में स्वामित्व विवादित नहीं है।उनका तर्क है कि उनकी संपत्ति का अधिग्रहण, जिसका अधिकार निर्विवाद है, अनावश्यक है।सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के अलावा जिन लंबित मुकदमों को समाप्त कर दिया गया है, उनके पक्षों ने भी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी है, भले ही अन्य आधारों पर।बी पर इन आधारों पर अनुच्छेद 14,25 और 26 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।यह

अतः चर्चा में इन आधारों को शामिल किया गया है।

चुनौती आधारित उचित विचार के लिए।धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और इस संदर्भ में एक क़ानून का अर्थ लगाने में अदालतों के कर्तव्य का उल्लेख करना उचित है।

एस.

संविधान द्वारा भारत के लोगों को आश्वस्त की गई राजनीति है -

प्रस्तावना में वर्णित है जिसमें "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़ा गया था

42nd संशोधन।यह गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालता है

अनुच्छेद 20 से 26 कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति विवेक की स्वतंत्रता और अपनी पसंद के धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के लिए समान रूप से हकदार होंगे, संक्षेप में, यह भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है और भारत के लोगों द्वारा अपने स्थायी विश्वास और पंथ के रूप में अपनाई गई जीवन शैली है।पटेल स्मारक व्याख्यान-1985 में एम. सी. सीतलवाड़

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा का उल्लेख करते हुए धर्मनिरपेक्षता ने इस प्रकार कहाः

" ..... विभाजन के आने ने महान पर जोर दिया

ई.

धर्मनिरपेक्षता का महत्व।विभाजन के बावजूद, ए

एक बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक, जिसका दसवां हिस्सा है

आबादी, स्वतंत्र के नागरिक बने रहे

भारत।नागरिकों के अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह भी थे।परिस्थितियों में, के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान

स्वतंत्र भारत, जिसके तहत सभी धर्म आनंद ले सकते थे

च

समान स्वतंत्रता और सभी नागरिकों को समान अधिकार, और जो

एक राष्ट्र में एक साथ विभिन्न धार्मिक

समुदाय, अपरिहार्य हो गए।

3/4

(पृष्ठों पर 481-82)

जी.

‘ ... . इसलिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, एक अर्थ में

राज्य जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और एक

उनके प्रति परोपकारी तटस्थता एक तरह से वास्तव में भारतीय पर्यावरण और जलवायु के लिए अधिक अनुकूल है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य "।

एच.

(पृष्ठ 485 पर)

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे. जे.

43

" ..... भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को अधिकतम संभव सामग्री दी जानी चाहिए।इसे धर्म से उत्पन्न या उससे जुड़ी सभी मनोवृत्तियों और प्रथाओं के उन्मूलन का संकेत देना चाहिए जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में हमारे विकास को बाधित करते हैं।राज्य और नागरिक दोनों द्वारा एक ठोस और गंभीर प्रयास

इस व्यापक अवधारणा के अनुसार धर्मनिरपेक्षता केवल बी हमारे लोकतांत्रिक राज्य के स्थिरीकरण और एक सच्चे और एकजुट भारतीय राष्ट्र की स्थापना की ओर ले जाती है।(पृष्ठ 488-89 पर)

भारत के राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल के संबोधन का एक संदर्भ

एस.

शर्मा, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति के रूप में, विश्व के डॉ. जाकिर हुसैन स्मारक व्याख्यान देते हुए "भारतीय लोकाचार में धर्मनिरपेक्षता" पर।

भारती, शांतिनिकेतन, 29 अप्रैल, 1989 उपयोगी है।इसमें, उन्होंने "धर्मनिरपेक्ष" शब्द की हमारी समझ और पश्चिम में या इसके शब्दकोश के अर्थ के बीच के अंतर का उल्लेख किया और कहाः

डी.

" हालाँकि, हम भारत में धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों की समानता की सहिष्णुता और समझ के दृष्टिकोण 'सर्व धर्म समाज' को दर्शाने के लिए समझते हैं।

XXX

XXX

XXX

ई.

" समझ, सह-अस्तित्व और सहिष्णुता का यह दार्शनिक दृष्टिकोण हमारे प्राचीन विचार की भावना है।

XXX

XXX

XXX

च

यजुर्वेद में कहा गया हैः

मेरी देश की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा है।

जी.

) यजूः३८ - १८ (

" सभी प्राणी मुझे एक मित्र की आँखों से देखें।मैं सभी प्राणियों को एक मित्र की आँखों से देख सकता हूँ।आइए हम एक-दूसरे को एक दोस्त की आंखों से देखें।

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी.5 एस सी आर।

44

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है

क.

अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में निहित हैः

ज निभव रनित भू ध निवाचस। आ ऊपर आ पृथ्वी + वी ये + ओक्स।

यह पृथ्वी, जो विभिन्न समझौतों और भाषाओं के लोगों को समायोजित करती है, एक शांतिपूर्ण घर की तरह -

हम सभी को लाभ पहुँचाएँ।

ता.....।

" हे धरती माता, अपने बच्चों के रूप में हमें सामंजस्यपूर्ण बातचीत करने की क्षमता दें; हम किसी के साथ मधुरता से बात करें।

एस.

एक और "।

और आरजी।वेद दृढ़ता से घोषणा करता हैः

एक ही आप ":राष्ट्रीय जनाना

डी.

" सभी मनुष्य एक ही जाति के हैं।"

इस प्रकार सर्व धर्म समभाव या धर्मनिरपेक्ष विचार और दृष्टिकोण के विकास के लिए प्राचीन भारतीय विचार द्वारा एक दार्शनिक और नृजातीय संयोजन प्रदान किया जाता है।यह ज्ञान उसी का वास्तविक केंद्र है जिसे अब जाना जाता है

ई.

हिंदू धर्म "।

आगे बढ़ते हुए, अन्य धर्मों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए

भारतीय लोकाचार के बारे में उन्होंने कहाः

" इस संबंध में दो पहलू उल्लेखनीय हैं।सबसे पहले, ईसाई धर्म या इस्लाम या पारसी धर्म की प्रारंभिक उपस्थिति

च

भारत और मुख्य भूमि पर उनकी स्थापना सैन्य विजय या विजय के खतरे के परिणामस्वरूप नहीं हुई थी।इन धर्मों को मुख्य धार्मिक अधिकारियों सहित स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित समायोजन और सह-अस्तित्व के दृष्टिकोण के आधार पर स्थान दिया गया था।दूसरा पहलू और भी महत्वपूर्ण हैःईसाई धर्म, इस्लाम और पारसी धर्म अपने साथ आध्यात्मिक और

जी.

मानवतावादी विचार सामंजस्यपूर्ण और वास्तव में, भारत में स्थापित धार्मिक विचार के मूल विचारों के समान हैं, जैसा कि वैदिक की बुनियादी मान्यताओं द्वारा उदाहरण दिया गया है।वेदांतिक,

बौद्ध और जैन दर्शन "।

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 45 संतों और पवित्र व्यक्तियों के प्रभाव का संकेत इस प्रकार दिया गया थाःक.

66 ..... इसलिए, इस्लाम में एक प्रकट धर्म के रूप में स्वाभाविक रुचि थी जो एक गहरे करिश्मे के पैगंबर द्वारा लाया गया था, जिन्होंने प्रतिकूलताओं का सामना किया था, और ईसाई धर्म में, जो यीशु मसीह के प्रकाश को फैलाता था, जिन्होंने मानवता के लिए एक भयानक सूली पर चढ़ाया था।कुरान बी में अब्राहम, इसाक, इश्माएल, जैकब, मूसा जैसे महान आत्माओं का भी उल्लेख किया गया है जिनका उल्लेख ईसाई धर्म के पुराने नियम में किया गया है, और जीसस, अल-फ़ातिहा या फ़ातिहा तू अल्फ़ाथा जिसे उम्मुल कुरान या कुरान का सार भी कहा जाता है, 'अल्लाह' को रब-उल-अलामिन या पूरे ब्रह्मांड के भगवान के रूप में संदर्भित करता है।यह उन्हें केवल सी मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रखता है।कुरान की दूसरी सूरह, जिसका शीर्षक "अल बखुराह" है, एक चेतावनी देती है, जिसे पूरे कुरान में दोहराया गया है, कि यह केवल किसी के पंथ का दावा नहीं है, बल्कि धर्मी आचरण है, जो सच्चा धर्म है।इस सूरह की आयतें 44,81 और 82 इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करती हैं।

डी.

डॉ. शर्मा ने "दिन-ए-इलाही" की स्थापना करने वाले अकबर द्वारा धर्मनिरपेक्षता के विकास में किए गए योगदान और उनके समर्थन का भी उल्लेख किया।

दारा शिकोह के धर्मनिरपेक्षता के अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा दिया गया।हिंदू धर्म पर मुस्लिम रहस्यवाद का प्रभाव और भारतीय लोकाचार में कबीर का योगदान स्थायी रहा है।धर्मनिरपेक्ष आदर्शों ने ई सिख धर्म का निर्माण किया और गुरुओं ने इसमें स्थायी योगदान दिया है।उन्होंने कहाः

" गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म के धर्मनिरपेक्ष आदर्श को और बढ़ा दिया।गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित पंक्तियाँ दिमाग में आती हैं।

च

देहुरा सीते सोनी, पू जा ओ आज ओए,

ा सब कुछ ऐसा ही है जिसे हम स्वीकार करते हैं।

अल्लाह अबहेख सोनी, पूरा ओ कू रा ओह, एक ही रूप है, एक ही बन गया है।

जी.

" मंदिर या मस्जिद, पूजा या नमाज़, पुराण या कुरान में कोई अंतर नहीं है।सभी मनुष्य समान हैं।

हाल के दिनों में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करने के बाद, डॉ. शर्मा ने निष्कर्ष निकालाः

एच 46

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर

" भारत के संविधान ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि

क.

स्पष्ट के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता

व्यक्ति और धर्म के बीच, धर्म और धर्म के बीच, धर्म और राज्य के बीच और राज्य और धर्म के बीच वांछनीय संबंधों की समझ

व्यक्तिगत "।

:

XXX

XXX

XXX

" मैं डॉ. ज़ाकिर हुसैन के भाषण के कुछ सार्थक शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा।“ हम कुछ ही समय में व्यक्ति और समूहों के बीच शांति चाहते हैं।ये सभी महत्वपूर्ण रूप से परस्पर निर्भरता हैं।अगर उपदेश की आत्मा

1

ग

जिस पर्वत पर बुद्ध का करुणा का दर्शन, अहिंसा की हिंदू अवधारणा और ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के लिए इस्लाम का जुनून एकजुट हो सकते हैं, तब हम दुनिया के लिए सबसे शक्तिशाली प्रभाव पैदा करने में सफल होंगे

शांति "।

डी.

एस. आर. बोम्मई बनामभारत संघ, [1994] 3 एस. सी. सी. 1, एक नौ-न्यायाधीश पीठ

भारतीय संदर्भ में "धर्मनिरपेक्षता" की अवधारणा का उल्लेख किया गया।जे. सावंत ने इस पहलू पर चर्चा की और सीतलवाड़ व्याख्यान का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार कहाःजैसा कि ऊपर कहा गया है, धार्मिक सहिष्णुता और सभी धार्मिक समूहों के साथ समान व्यवहार और उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा।

ई.

और उनके पूजा स्थल हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।हमने उक्त लक्ष्य को न केवल इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि यह हमारी ऐतिहासिक विरासत और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की आवश्यकता है, बल्कि सार्वभौमिक भाईचारे और मानवतावाद के पंथ के रूप में भी यह हमारा प्रमुख लक्ष्य है।

च

आस्था।कोई भी पेशा और कार्य जो उपरोक्त पंथ के विपरीत जाता है, आचरण का प्रथम दृष्टया प्रमाण है।

हमारे संविधान के प्रावधानों की अवज्ञा "।

(पृष्ठों पर 147-48) G इसी तरह, के. रामास्वामी, जे. ने उसी निर्णय में कहाः

" ..... यद्यपि "धर्मनिरपेक्षता" की अवधारणा को संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसका विस्तार,

मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों और उनके संबंधित प्रावधानों से संचालन और दृश्यता स्पष्ट है।इसकी प्रस्तावना में संशोधन करके इसे स्पष्ट किया गया था

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 47 संविधान 42 वां संशोधन अधिनियम।एक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता सबसे प्रमुख है

ऐसा प्रतीत होता है कि यह न केवल ईश्वर के विषय की कल्पना करता है, बल्कि मनुष्य और मनुष्य के बीच एक समझ की भी कल्पना करता है।धर्मनिरपेक्षता

संविधान ईश्वर विरोधी नहीं है और कभी-कभी इसे स्वतंत्र समाज में रहना माना जाता है।विशुद्ध रूप से धार्मिक मामलों को व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत छोड़ दिया जाता है और धर्मनिरपेक्ष बी भाग को लोक हित, व्यवस्था और सामान्य कल्याण के आधार पर राज्य द्वारा संभाला जाता है।राज्य व्यक्तिगत और निगमित धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म और आस्था के बावजूद नागरिक के रूप में व्यवहार करता है।

धार्मिक विश्वास और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और न ही एक दूसरे के खिलाफ पसंद करता है।इसलिए, धर्मनिरपेक्ष सी राज्य की अवधारणा सरकार के लोकतांत्रिक रूप के सफल संचालन के लिए आवश्यक है।नहीं हो सकता है।

लोकतंत्र यदि धर्मनिरपेक्षता विरोधी ताकतों को एक दूसरे के गले पर उड़ते हुए विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के अनुयायियों को विभाजित करने का काम करने की अनुमति दी जाए।धर्मनिरपेक्ष सरकार को इस प्रयास को नकारना चाहिए और समाज में व्यवस्था लानी चाहिए।धर्म सकारात्मक अर्थों में, नागरिक को अपने व्यक्ति के पूर्ण विकास की अनुमति देने के लिए एक सक्रिय साधन है, न केवल शारीरिक और भौतिक रूप से, बल्कि गैर-भौतिक और गैर-धर्मनिरपेक्ष जीवन में।(पृष्ठ 163 पर)

ई.

..... इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि संविधान ने धार्मिक भाग को व्यक्तिगत और धर्मनिरपेक्ष भाग के बीच सीमांकन किया है।राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता है, राज्य न तो किसी विशेष धर्म का समर्थक है और न ही किसी विशेष धर्म का विरोधी है, यह अलग खड़ा है, दूसरे शब्दों में एफ धर्म के मामलों में तटस्थता बनाए रखता है और सभी धर्मों को समान सुरक्षा प्रदान करता है।

विनियमन के अधीन और सक्रिय रूप से धर्मनिरपेक्ष भाग पर कार्य करता है।(पृष्ठ 168 पर) बी. पी. जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, जे. ने उसी संदर्भ में निर्णय में जी को इस प्रकार कहाः

" ..... जहाँ तक राज्य का संबंध है, इस देश के नागरिक अपने पसंद के धर्म, आस्था या विश्वास को मानने, पालन करने और प्रचारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी राज्य के दृष्टिकोण से, किसी व्यक्ति के धर्म, विश्वास या विश्वास को एच +

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

48

महत्वहीन है।इसके लिए, सभी समान हैं और सभी होने के हकदार हैं

क.

समान रूप से व्यवहार किया।यह समान व्यवहार कैसे संभव है, यदि

राज्य को किसी विशेष धर्म, नस्ल या जाति को प्राथमिकता देनी थी या बढ़ावा देना था, जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से अन्य सभी धर्मों, नस्लों और जातियों के प्रति कम अनुकूल व्यवहार है।सामाजिक न्याय, आस्था, आस्था या पूजा की स्वतंत्रता और स्थिति और अवसर की समानता के संवैधानिक वादों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि राज्य नहीं छोड़ता हैःकिसी व्यक्ति का धर्म, विश्वास या विश्वास उसके साथ व्यवहार करते समय उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों और उसके अधिकारों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए?इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक निष्क्रिय दृष्टिकोण या धार्मिक सहिष्णुता से अधिक है।यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की एक सकारात्मक अवधारणा है।इस मनोवृत्ति को कुछ लोग धर्म के प्रति तटस्थता या परोपकारी के रूप में वर्णित करते हैं।

एस.

तटस्थता।यह पश्चिमी उदार विचार द्वारा विकसित एक अवधारणा हो सकती है या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यह हर समय भारतीय लोगों के साथ एक स्थायी विश्वास हो सकता है।वह भौतिक नहीं है।सार यह है कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य है और संविधान की एक बुनियादी विशेषता है जिसकी पुष्टि की गई है

डी.

केशवानंद भारती, [1973] 4 एस. सी. सी. 225; [1973] पूरक।एस. सी. आर. 1 और इंदिरा एन. गांधी बनामराज नारायण; [1975] पूरक।.एससीसी 1:[1976] 2 एससीआर 847।इस संवैधानिक नीति के साथ असंगत कोई भी कदम, सीधे शब्दों में, असंवैधानिक है।इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म के मामलों में राज्य का कुछ भी कहना नहीं है।मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों के धर्मनिरपेक्ष मामलों को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं

ई.

और गणित।(एस. पी. मित्तल बनाम देखें।भारत संघ, [1983] 1 एस. सी. सी.

51 ; [1983] 1 एससीआर 729)।"

(जोर दिया गया)

च

(पृष्ठ 233 पर) अहमदी, जे. सावंत के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए,

रामास्वामी और जीवन रेड्डी, जेजे।इस प्रकार कहा गया हैः

जी.

" इस तथ्य के बावजूद कि 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हमारे संवैधानिक दर्शन में बहुत अधिक अंतर्निहित थी।'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

i

संभवतः क्योंकि यह एक बहुत ही लोचदार शब्द है जो सक्षम नहीं है

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 49 सटीक परिभाषा और शायद सबसे अच्छा अनिर्धारित छोड़ दिया।इस संशोधन द्वारा जो निहित था उसे स्पष्ट कर दिया गया था।

(पृष्ठ 77 पर)

संवैधानिक योजना से यह स्पष्ट है कि यह सभी व्यक्तियों और समूहों को धर्म के मामले में समानता की गारंटी देता है, चाहे उनका धर्म बी कुछ भी हो, इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य का कोई धर्म नहीं है।विशेष रूप से अनुच्छेद 25 से 28 के साथ पठित संविधान की प्रस्तावना इस पहलू पर जोर देती है और इंगित करती है कि इस तरह से भारतीय लोगों द्वारा अपनाए गए एक पंथ के रूप में संवैधानिक योजना में सन्निहित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की कसौटी पर किसी भी विधान की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय समझना होगा।धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इसका एक पहलू है

हमारे संविधान में योजना के स्वरूप को दर्शाने वाले कपड़े में केंद्रीय सुनहरे धागे के रूप में बुनी गई समानता का अधिकार।

इस संदर्भ में एम. एन. वेंकटचलैया, जे. द्वारा "लॉ इन ए प्लुरलिस्ट सोसाइटी" पर एक पेपर के कुछ उद्धरणों का उल्लेख करना उपयोगी है, जैसा कि वे उस समय (हम में से एक) थे।इसमें उन्होंने कहाः

डी.

" बहुवचन समाजों में कानून का उद्देश्य नहीं है

बहुसंख्यक मिल में अल्पसंख्यकों का प्रगतिशील एकीकरण।इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन व्यर्थ में इसे भंग करने की कोशिश होगी।फिर इसका उद्देश्य क्या है?एक बार फिर लॉर्ड स्कारमैन (ई प्लुरल सोसाइटी में अल्पसंख्यक अधिकार, पृ. 63) के शब्दों में:

..... कानून का उद्देश्य समाज को बनाने वाले समूहों को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें टूटने से रोकने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी साधन तैयार करना होना चाहिए और इस तरह से उस बहुवचन समाज को नष्ट करना चाहिए जिसमें वे एफ हैं।

सदस्य "।

एक बहुलवादी में, धर्मनिरपेक्ष राजनीति कानून शायद सबसे बड़ी एकीकृत करने वाली शक्ति है।कानून और उसके संस्थानों और प्रतीकों के लिए एक संवर्धित सम्मान; देश की विरासत और उपलब्धियों पर गर्व; यह विश्वास कि लोग कानून के तहत रहते हैं।

बहुलवादी विविधता में एकता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रणाली का संरक्षण अपरिहार्य है।"निष्पक्षता के रूप में न्याय" का रॉल्सियन व्यावहारिकता एक "अत्यधिक सर्वसम्मति" और गहरे सामाजिक विकास के लिए समाज की बुनियादी संरचना के मौलिक प्रश्नों पर गहरे बैठे समझौतों के रूप में काम करती है।

जी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी.5 एस सी आर।

50

एकता न्याय की एक राजनीतिक अवधारणा है न कि

क.

व्यापक नैतिक अवधारणा "।

XXX

XXX

XXX

" बहुलवाद के मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की क्या सीमाएँ हैं?कानून को गहराई को नहीं बढ़ाना चाहिए

दरार और अपने आप में उत्तेजना का एक स्रोत बन जाता है

बहुत ही ऐसी स्थिति जिसे वह ठीक करने का इरादा रखता है। "

XXX

XXX

XXX

" उन लोगों के लिए जो भय और असुरक्षा में रहते हैं सभी खुशियाँ और

ग

जीवन के चमकीले रंग उकेरे जाते हैं।आश्वासन और अपनत्व की भावना प्रदान करने की आवश्यकता है।यह कहना पर्याप्त नहीं है कि "यहाँ देखो।" मैंने तुमसे कभी गुलाब के बगीचे का वादा नहीं किया था।मैंने आपको कभी भी पूर्ण न्याय का वादा नहीं किया था।लेकिन पूर्ण न्याय एक अप्राप्य लक्ष्य हो सकता है।कम से कम यह परस्पर विरोधी हितों का एक सहनीय समायोजन होना चाहिए।

डी.

समाज।हालाँकि वास्तव में इस तरह के आवासों को ठोस रूप से प्राप्त करने के लिए कोई शाही मार्ग नहीं हो सकता है।बेंथम ने समानता की खोज को वितरण न्याय के सिद्धांत और सुरक्षा प्रदान करने के सिद्धांत के हिस्से के रूप में 'निराशा-रोकथाम' सिद्धांत के रूप में इंगित किया।

ई.

धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक अवधारणा और इसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए

एक बहुलवादी समाज में न्यायपालिका, साथ ही इस तरह के कानून की व्याख्या करने में अदालत का कर्तव्य, अब हम अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

सबसे पहले 1993 के अधिनियम संख्या 33 के प्रावधानों का विरोध करना आवश्यक है।

च

जिसके संदर्भ में चुनौती के आधारों की जांच की जानी है।जैसा कि पहले कहा गया है, "बनियान" शब्द का अर्थ उस संदर्भ से अलग है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है।जरूरी नहीं कि इसका मतलब हर स्थिति में पूर्ण निहित होना है और यह शीर्षक के साथ-साथ अवधि में सीमित निहित होने के जी अर्थ को वहन करने में सक्षम है।इस प्रकार धारा 3 में प्रयुक्त "बनियान" का अर्थ क़ानून के पाठ और इसके उपयोग के उद्देश्य के आलोक में निर्धारित किया जाना चाहिए।यदि निहित किसी भी तरह से असीमित है, तो अधिग्रहित संपत्ति के हस्तांतरण या प्रबंधन के अधिकार पर कोई सीमा नहीं हो सकती है।पूर्ण निहित होने की स्थिति में, संपत्ति के अधिग्रहण के बाद हस्तांतरण एच को सक्षम करने वाले प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है, हस्तांतरण का अधिकार एक आवश्यक घटना होने के कारण एम. आई. फारूकी बनाम।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 51

निरपेक्ष शीर्षक।ए के एक भाग के रूप में उसी क़ानून में धारा 6 का अधिनियमन

इसलिए, केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के अधिग्रहण की योजना, बिना किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार में एक पूर्ण मालिक के रूप में निहित होने की धारा 3 के तहत निहित होने का विपरीत संकेत है।किसी भी तरह से संपत्ति के प्रबंधन और उससे निपटने का अधिकार, धारा 7 का अधिनियमन जो विवादित क्षेत्र को शामिल करते हुए बी संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति पर एक स्पष्ट सीमा लागू करता है, जब तक कि हस्तांतरण धारा 6 में बताए गए तरीके से प्रभावी नहीं हो जाता है, केंद्र सरकार द्वारा विवादित संपत्ति में केवल एक सीमित और पूर्ण स्वामित्व के अधिग्रहण का स्पष्ट संकेत है।धारा 6 और 7 को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस अधिनियम द्वारा विवादित संपत्ति का अधिग्रहण एक विशेष उद्देश्य के लिए है और जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो संपत्ति को धारा 6 में प्रदान किए गए तरीके से हस्तांतरित किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार उस हस्तांतरण के समय तक 7 जनवरी, 1993 को उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य है जहां विवादित संरचना थी।प्रभावी होने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उस विवाद का समाधान है जिसने पहले बातचीत द्वारा इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की अवहेलना की है।विचार किए गए विवाद के समाधान के तरीके संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय के निर्णय के लिए निर्दिष्ट प्रश्न से संदर्भित और संबंधित हैं।यह एक अलग मामला है कि विवाद केवल निर्दिष्ट प्रश्न के उत्तर से हल करने में सक्षम नहीं हो सकता है।यह अधिनियम की धारा 4 (3) की वैधता तय करने के लिए सामग्री है जो सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को कम करती है जो ई को दर्शाती है कि अपनाया गया वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र केवल

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत दिया गया संदर्भ।यदि राष्ट्रपति का संदर्भ वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है और इसलिए, मुकदमे के पक्षों को न्यायिक उपचार से इनकार करने का प्रभाव पड़ता है, तो इसका स्वयं एक एफ हो सकता है।अधिनियम की धारा 4 (3) की संवैधानिक वैधता पर असर डालना।उस स्थिति में धारा 4 (2) को अमान्य घोषित किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप धारा 4 (3) द्वारा सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिसका प्रभाव यह है कि धारा 6 के तहत अधिग्रहित विवादित संपत्ति का केंद्र सरकार द्वारा कोई भी हस्तांतरण पुनर्जीवित मुकदमों में विवाद के निर्णय द्वारा निर्देशित और विनियमित किया जाएगा।यह, निश्चित रूप से, धारा 4 (3) की पृथकता जी के अधीन है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 6 में प्रयुक्त "निहित" शब्द के सही अर्थ का पता लगाने के लिए हमें पहले अधिनियम की धारा 6 और 7 की वैधता पर विचार करना चाहिए, जिस पर यह काफी हद तक निर्भर करता है।यदि अधिनियम की धारा 6 और 7, जो केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती हैं, को कायम नहीं रखा जा सकता है, तो एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] का समर्थन करता है।

5 एस सी आर।

52

इस मोड के माध्यम से अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित शीर्षक की धारा 3 में पढ़ी गई सीमा गायब हो जाएगी।इस कारण से, हम धारा 6 और 7 की वैधता की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

धारा 6 और 7 के बीच, यह धारा 7 है जो अधिक से अधिक लागू करती है

केंद्र सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध।यह आदेश देता है कि जिस क्षेत्र पर विवादित ढांचा खड़ा था, उसके बी प्रबंधन में उसे 7 जनवरी, 1993 को अधिग्रहण के समय जैसी स्थिति थी, वैसी ही स्थिति बनाए रखनी होगी।इस तरह की सीमा स्पष्ट रूप से अधिग्रहण के साथ असंगत है

संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व।इसलिए अधिनियम की धारा 7 (2) की वैधता पर विचार किया जाना चाहिए।

धारा 7, जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, एक अस्थायी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य इसे बनाए रखना है।

ग

विवादित क्षेत्र में यथास्थिति, जब तक कि विवाद के समाधान पर केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाता है।यह उस हस्तांतरण के उद्देश्य को प्रभावी बनाने और इसे सार्थक बनाने के लिए है ताकि अंतराल के दौरान विवादित क्षेत्र में मौजूदा स्थिति में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप अभ्यास की हताशा की किसी भी संभावना से बचा जा सके।जब तक यथास्थिति डी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक विवाद के समाधान पर अंतिम परिणाम विवादित क्षेत्र में किए गए किसी भी बदलाव से निराश हो सकता है जो विवादग्रस्त क्षेत्र को निराश कर सकता है।

सफल पक्ष के पक्ष में परिणाम का कार्यान्वयन और इसे अर्थहीन बनाना।विवादित संपत्ति में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश एक सर्वविदित तरीका है और संपत्ति के संरक्षण और वास्तविक संपत्ति के हितों की रक्षा के लिए विवाद के लंबित रहने के दौरान दिया जाने वाला सामान्य आदेश है।

ई.

निर्णय होने तक मालिक।मौजूदा स्थिति में बदलाव है

वास्तविक मालिक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के खतरे से भरा हुआ, अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।यह अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि की गई कवायद विवादित क्षेत्र के वास्तविक मालिक का पता लगाने, अंतराल के दौरान उसमें यथास्थिति बनाए रखने और इसे एफ के हकदार पाए जाने वाले वास्तविक मालिक को सौंपने के लिए है।

अब सवाल यह है कि क्या 7 जनवरी, 1993 को विवादित स्थल पर मौजूद यथास्थिति बनाए रखने के जनादेश वाली धारा 7 का प्रावधान हिंदू समुदाय के पक्ष में एक झुकाव है, जिसका उद्देश्य 6 दिसंबर, 1992 को जी मस्जिद को ध्वस्त करके मुस्लिम समुदाय के साथ किए गए अन्याय को कायम रखना है और इसलिए, यह एक धर्मनिरपेक्ष या भेदभावपूर्ण कार्य है जो प्रावधान को असंवैधानिक बनाता है।इसके लिए

इस उद्देश्य से 7 जनवरी, 1993 की स्थिति को उस स्थिति की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ याद करना आवश्यक है।7 जनवरी, एच 1993 को और उससे ठीक पहले की एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए दोनों समुदायों द्वारा विवादित क्षेत्र के तुलनात्मक उपयोग और उसमें प्रचलित पूजा के अधिकार को ध्यान में रखना आवश्यक है।

एम. आई. फारूकी बनाम का संदर्भ।यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 53

दोनों समुदायों द्वारा उस अवधि के दौरान तुलनात्मक उपयोगकर्ता ए इंगित करेगा कि क्या धारा 7 में विवाद के समाधान तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाला प्रावधान और धारा 6 द्वारा विचारित केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरण हिंदू समुदाय की ओर झुका हुआ है -

यह प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता या समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

जैसा कि पहले कहा गया था, हिंदू भक्तों द्वारा राम चबूतरा पर स्थापित मूर्तियों की पूजा, जो विवादित ढांचे के प्रांगण के भीतर विवादित स्थल पर खड़ी थी, दिसंबर 1949 में राम चबूतरा से विवादित ढांचे में उन मूर्तियों को स्थानांतरित करने से पहले भी मुसलमानों द्वारा बिना किसी आपत्ति के की गई थी; जनवरी 1950 में दायर एक मुकदमे में, निचली अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसके तहत मूर्तियां सी उस स्थान पर बनी रहीं जहां उन्हें 1949 में स्थापित किया गया था और हिंदू भक्तों द्वारा वहां मूर्तियों की पूजा जारी रही; यह अंतरिम आदेश था -

अप्रैल 1955 में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई; जिला न्यायाधीश ने 1 फरवरी, 1986 को विवादित संरचना में मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाले ग्रिल पर रखे गए ताले को खोलने का आदेश दिया और डी.

वहाँ हिंदू भक्तों के लिए मूर्तियों की पूजा; और यह स्थिति 6 दिसंबर, 1992 को संरचना के विध्वंस तक जारी रही जब राम चबूतरा को भी ध्वस्त कर दिया गया था।यह केवल 6 दिसंबर, 1992 को विध्वंस के अधिनियम के परिणामस्वरूप था कि उस स्थान पर सामान्य रूप से हिंदू भक्तों द्वारा मूर्तियों की पूजा में बाधा आई थी।विध्वंस के समय से, केवल पुजारी द्वारा मूर्तियों की पूजा जारी है।इस तरह विवादित स्थल के भीतर राम चबूतरे में 1949 से बहुत पहले से हिंदू भक्तों द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्तियों की पूजा का अधिकार 6 दिसंबर, 1992 को विध्वंस के अधिनियम के बाद से बाधित हो गया है, जिसके बाद से मूर्तियों की पूजा को केवल एक पुजारी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।दूसरी ओर, कम से कम दिसंबर 1949 से, मुसलमान विवादित स्थल पर किसी भी स्थान पर पूजा नहीं कर रहे हैं, हालांकि मुकदमों के मुकदमे में यह पता चल सकता है कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार था।

देश में फैलाए गए सांप्रदायिक नरसंहार ने देश को बाधित कर दिया

6 दिसंबर, 1992 को ढांचे के विध्वंस के परिणामस्वरूप प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव का और उल्लेख करने की आवश्यकता है। सांप्रदायिक तनाव के बढ़ने को रोकने और सांप्रदायिक जी समझौते और सद्भाव को प्राप्त करने के लिए उठाए गए किसी भी कदम

को, किसी भी तर्क के आधार पर, गैर-धर्मनिरपेक्ष, बहुत कम धर्मनिरपेक्ष विरोधी या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ कहा जा सकता है-भारतीय लोगों का एक पंथ जो लोकाचार में अंतर्निहित है।

तथ्यों का वर्णन इंगित करता है कि अधिनियम के तहत संपत्तियों का अधिग्रहण दोनों समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करता है न कि केवल एच. सुपर कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी. के अधिकारों को।

5 एस सी आर।

54

मुसलमान समुदाय।मुसलमानों द्वारा दावा किया गया हित केवल उस विवादित स्थल पर है जहाँ मस्जिद विध्वंस से पहले थी।इस दावे पर हिंदुओं की आपत्ति पर निर्णय लिया जाना चाहिए।अधिनियम के तहत अर्जित शेष पूरी संपत्ति ऐसी है जिस पर मुसलमानों द्वारा किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जाता है।इसके एक बड़े हिस्से में हिंदुओं की संपत्तियां शामिल हैं, जिनके स्वामित्व पर विवाद भी नहीं है।संपत्ति, जिसके संबंध में अधिकार विवादित नहीं है, सहित बड़े क्षेत्र बी के अधिग्रहण के लिए दिया गया औचित्य यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि निर्णय के अंतिम परिणाम को विवादित ढांचे के आसपास हिंदुओं की संपत्तियों के अस्तित्व से अर्थहीन नहीं बनाया जाना चाहिए, यदि मुसलमान विवादित स्थल के हकदार पाए जाते हैं।इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विवादित ढांचे को मुस्लिम समुदाय को सौंपने की आवश्यकता वाले विवाद के निर्णय में मुसलमानों के सफल होने की स्थिति में, उनकी सफलता को हिंदू मालिकों या आसपास की संपत्तियों के स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग करके विवादित क्षेत्र में उचित सफलता और अधिकारों के आनंद से वंचित करके विफल नहीं किया जाना चाहिए।जाहिर है, यही कारण है कि सफल पक्ष को उपलब्ध कराने के लिए आस-पास के क्षेत्र का भी अधिग्रहण किया गया है, जिसका वह हिस्सा जिसे डी आवश्यक माना जाता है, ताकि निर्णय के अंतिम परिणाम पर सफलता के फल का उचित आनंद लिया जा सके।यह स्पष्ट है कि आस-पास की संपत्तियों के अधिग्रहण का एक उद्देश्य मुकदमे में सफलता की स्थिति में मुस्लिम समुदाय द्वारा विवादित स्थल का प्रभावी आनंद सुनिश्चित करना है और आस-पास के क्षेत्र का अधिग्रहण मुख्य उद्देश्य के लिए आकस्मिक है और इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है।"मानस"

ई.

"भवन" और "सीता की रसोई", दोनों हिंदुओं से संबंधित इमारतें हैं जो विवादित स्थल को करीब से देखती हैं और अधिग्रहण की जाती हैं क्योंकि वे विवादित क्षेत्र के संबंध में स्थानों में रणनीतिक हैं।विवादित संरचना क्षेत्र, जो अपने आप में एक अनूठा वर्ग है, से निकटता को देखते हुए आस-पास के मंदिरों या धार्मिक भवनों को प्राप्त करने की आवश्यकता अनुमत है।एम. पद्मनाभ अयंगर बनाम देखें।आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य।, ए. आई. आर. (1990) ए. पी. 357 और अखाड़ा श्री ब्रह्म बुटा, अमृतसर बनाम। पंजाब राज्य और अन्य, आकाशवाणी (1990) पी और एच 198।इन निर्णयों में बताए गए सिद्धांत का स्वागत है क्योंकि यह एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है।

हालांकि, बाद के चरण में जब सटीक क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया जो है

जी.

अधिग्रहण के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, हो सकता है

यह निर्धारित किया गया है कि यह न केवल अनुमेय होगा, बल्कि यह भी वांछनीय होगा कि अनावश्यक अतिरिक्त क्षेत्र को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए और इसके पहले के मालिक को वापस कर दिया जाए।इस आधार पर कि विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद को निपटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह अनावश्यक है, आस-पास के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण की चुनौती की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे. जे.

55

लेकिन, यदि अनावश्यक क्षेत्र ए के बाद भी उसके मालिक को वापस नहीं किया जाता है

उद्देश्य के लिए आवश्यक सटीक क्षेत्र अंततः निर्धारित किया जाता है, यह ऐसी किसी भी संपत्ति के मालिक के लिए अनावश्यक को चुनौती देने के लिए खुला होगा।

अधिग्रहण का अधिग्रहण के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है।विवादित क्षेत्र के आसपास स्थित ऐसी किसी भी संपत्ति के निर्विवाद मालिकों द्वारा इस स्तर पर अधिग्रहण की चुनौती को अस्वीकार करना, उन्हें इस स्वतंत्रता के आरक्षण के साथ है।केंद्र सरकार को छोड़कर किसी के द्वारा आस-पास की संपत्तियों के अधिग्रहण को रद्द करने के उनके बी दावे का कोई विरोध नहीं है, जो आवश्यकता के आधार पर अधिग्रहण को उचित ठहराना चाहती है।हमारे द्वारा बनाए गए कानून के निर्माण पर, यह ऐसी आसन्न संपत्तियों के संबंध में लेने के लिए तार्किक, उचित और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण प्रतीत होता है जिसमें निर्विवाद मालिक के अलावा कोई और नहीं है।

स्वामित्व और ब्याज का दावा करता है।यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जैसा कि अयोध्या को कहा जाता है

तीर्थस्थल के रूप में हिंदुओं के लिए विशेष महत्व है क्योंकि प्राचीन मान्यता है कि भगवान राम का जन्म वहाँ हुआ था, यह मस्जिद

1526 ईस्वी में मीर बाकी द्वारा बनाई गई एक प्राचीन मस्जिद के रूप में मुस्लिम समुदाय के लिए महत्व। एक मस्जिद के रूप में, यह डी मुसलमानों द्वारा पूजा का एक धार्मिक स्थान था।यह दोनों समुदायों के लिए विवादित स्थल के तुलनात्मक महत्व को दर्शाता है और यह भी कि अधिग्रहण का प्रभाव हिंदू समुदाय के अधिकार और हित पर समान रूप से पड़ता है।इस पहलू का उल्लेख केवल इस तर्क के संदर्भ में किया गया है कि कानून न केवल इसकी धारा 7 बल्कि समग्र रूप से हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता विरोधी है।अधिनियम की धारा 7 (2) 7 जनवरी, 1993 को अस्तित्व में स्वीकार की गई स्थिति को रोकती है, जो हिंदू भक्तों के लिए पूजा का कम अधिकार था, जो 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस तक लंबे समय तक अस्तित्व में था और यह हिंदू समुदाय के लिए अधिक अनुकूल स्थिति पैदा नहीं करता है, जो उन्हें 6 दिसंबर, 1992 तक प्रचलित विवादित स्थल में पूजा का अधिक बड़ा अधिकार प्रदान करने के बराबर है।

7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखना, इसलिए, हिंदू समुदाय को कोई और लाभ प्रदान करने या देने का प्रभाव नहीं है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि 6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद के विध्वंस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कुछ उपद्रवी थे जिनकी पहचान और तुलना पूरे जी हिंदू समुदाय के साथ नहीं की जा सकती है और इसलिए, उपद्रवियों द्वारा इस तरह की बर्बरता के कृत्य को अधिनियम की संवैधानिकता का निर्णय लेने के उद्देश्य से पूरे हिंदू समुदाय के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। सामान्य रूप से संरचना के विध्वंस के खिलाफ हिंदुओं द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया और निंदा इस तथ्य की स्पष्ट गवाही देती है।उत्तर एच 56 में बाद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अस्वीकृति

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. प्रदेश उस प्रभाव की एक और परिस्थिति है।बदमाश जो

ध्वस्त की गई मस्जिद का कोई धर्म, जाति या पंथ नहीं था, सिवाय एक अपराधी के चरित्र और किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति के जन्म की मात्र घटना के।

विशेष समुदाय अपने अपराध के कलंक को उस समुदाय से नहीं जोड़ सकता है जिसमें वह पैदा हुआ था।

अधिनियम की धारा 7 (2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का एक अन्य प्रभाव यह है कि

यह सुनिश्चित करता है कि हिंदू समुदाय के लिए इस आधार पर अंतिम निर्णय तक 7 जनवरी, 1993 को उनके द्वारा पूजा की प्रथा के दायरे को बढ़ाने का प्रयास करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है कि वास्तव में उनके द्वारा पूजा का एक बड़ा अधिकार 6 दिसंबर, 1992 तक प्रचलन में था।यह कल्पना करना मुश्किल है कि धारा 7 (2) को हिंदू समुदाय के पक्ष में और इसलिए धर्मनिरपेक्षता विरोधी के रूप में कैसे माना जा सकता है।यह प्रावधान मुसलमानों के पूजा के अधिकार की प्रथा में कटौती नहीं करता है।

विवादित क्षेत्र में समुदाय, जहां कम से कम दिसंबर 1949 से वास्तव में उनके द्वारा प्रथा या पूजा का कोई अभ्यास नहीं किया गया है; और यह 7 जनवरी, 1993 को हिंदुओं द्वारा पूजा के कम किए गए अधिकार पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखता है।हालांकि, सीमित व्यायाम

डी.

7 जनवरी, 1993 को विवादित क्षेत्र के भीतर हिंदू समुदाय के कम किए गए रूप में पूजा के अधिकार का, जो 6 दिसंबर, 1992 को विध्वंस तक प्रयोग किए गए अधिकार से कम है, धारा 7 (2) में अधिनियमित फ्रीज द्वारा उचित और न्यायपूर्ण प्रतीत होता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मस्जिद को ध्वस्त करने वाले उपद्रवियों के हिंदू धर्म का पालन करने का दावा करने वाले व्यक्ति होने का संदेह है।इसलिए, हिंदू समुदाय को अपने सीने पर क्रूस उठाना चाहिए, क्योंकि उपद्रवियों के कुकर्म को उनके धार्मिक गुट से संबंधित होने का संदेह है।

हम कहते हैं कि यह उचित परिप्रेक्ष्य है, जिसमें क़ानून को समग्र रूप से और विशेष रूप से धारा 7 को देखा जाना चाहिए।इस प्रकार समग्र रूप से क़ानून और विशेष रूप से धारा 7 (2) को चुनौती देने के लिए तथ्यात्मक आधार

च

धर्मनिरपेक्षता का आधार, संविधान की एक बुनियादी विशेषता, और समानता और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अस्तित्व में नहीं है।

7 दिसंबर, 1992 और 27 दिसंबर, 1992 को विध्वंस के तुरंत बाद केंद्र सरकार के बयानों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा।यह आग्रह किया गया कि

जी.

7 जनवरी, 1993 को एक अध्यादेश जारी करने के लिए की गई कार्रवाई, जिसे बाद में अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय को संदर्भ देना हिंदू समुदाय के लाभ के लिए पहले के बयानों से पुनः प्रस्तुत करने के बराबर है।यह कहना पर्याप्त है कि पहले दिए गए बयान संसद की शक्ति को सीमित नहीं कर सकते हैं।

एच.

और एम. आई. फारूकी बनाम की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए सामग्री नहीं हैं।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 57

अधिनियमन।कानून की वैधता संविधान की कसौटी पर निर्धारित की जानी चाहिए न कि इससे पहले दिए गए किसी भी बयान पर। इसलिए हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 7 को असंवैधानिक बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता विरोधी या भेदभावपूर्ण होने की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

अब हम धारा 6 की वैधता की जांच करेंगे।धारा 6 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को अधिग्रहित क्षेत्र बी या उसके किसी हिस्से को किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या न्यास में निहित करने का निर्देश देने का अधिकार देती है।यह शक्ति पूरे अधिग्रहित क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से तक फैली हुई है।यह धारा 3,4,5 और 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद है।धारा 3 में क्षेत्र के अधिग्रहण और केंद्रीय क्षेत्र में इसके निहित होने का प्रावधान है।

सरकार।इसलिए, धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि

क्षेत्र का अधिग्रहण और केंद्र सरकार में इसका निहित होना इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या न्यास में निहित होने में कोई बाधा नहीं है।धारा 4 निहित करने के प्रभाव से संबंधित है और धारा 5 निहित क्षेत्र का कब्जा सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है, जिसे केंद्र को देने के लिए व्यक्ति या राज्य सरकार के संबंधित दायित्व के साथ निहित किया गया है।

सरकार या अधिकृत व्यक्ति।डी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही के उपशमन से संबंधित धारा 4 (3) पर अलग से विचार किया जाएगा।धारा 7 जिसे हम पहले ही बरकरार रख चुके हैं, मध्यावधि के दौरान केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित है जब तक कि केंद्र द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है।

धारा 6 (1) के तहत सरकार।धारा 7 को हमारे द्वारा विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने और अंतराल के दौरान अर्जित पूरी संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए एक अस्थायी प्रावधान के रूप में माना गया है।इस प्रकार, धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) इस आशय के क़ानून में एक अंतर्निहित संकेत है कि विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण और केंद्र सरकार में इसका निहित होना निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इसके बाद इसके हकदार व्यक्ति को इसके हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए है।

विवाद के निर्णय के परिणामस्वरूप जिसके समाधान के लिए यह कदम उठाया गया था, और क़ानून का अधिनियमन उस अभ्यास का हिस्सा है।अनुच्छेद 143 (1) के तहत अध्यादेश जारी करने के साथ-साथ संदर्भ बनाना, जिसे बाद में अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, उसी दिन इस विधायी इरादे का भी संकेत है कि विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण निरपेक्ष नहीं था, बल्कि विवाद के जी समाधान तक इसे वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में रखने तक सीमित था; और फिर इसके लिए अपनाए गए तंत्र में किए गए अंतिम निर्धारण के अनुसार इसे स्थानांतरित करना।

विवाद का समाधान।धारा 6 की उप-धारा (2) उप-धारा (1) के तहत की गई कार्रवाई के परिणाम को इंगित करती है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उप-धारा (1) के तहत की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, क्षेत्र या उसके हिस्से के संबंध में कोई भी अधिकार, स्वामित्व और हित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी. बन गया माना जाएगा।

5 एस सी आर।

58

ए हस्तांतरणकर्ता का।धारा 6 की उप-धारा (3) यह अधिनियमित करती है कि धारा 4,5,7 और 11 के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों के संबंध में लागू होंगे जो वे केंद्र सरकार के संबंध में लागू होते हैं।"जहाँ तक हो सके" पद इस तथ्य का संकेत है कि इनमें से सभी या कोई भी प्रावधान उप-धारा (1) के तहत हस्तांतरणकर्ता पर लागू हो भी सकता है और नहीं भी।यह हस्तांतरण बी की स्थिति के लिए, यदि आवश्यक हो, किसी भी स्तर पर और संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए प्रावधान करता है, क्योंकि धारा 7 (2) केवल विवादित क्षेत्र पर लागू होती है।हालाँकि यह प्रावधान विवाद के अनसुलझे रहने या स्थिति को स्वीकार नहीं करता है।

निरंतर जारी रखें।निर्णय तक हस्तांतरण पर प्रतिबंध, और उसके संदर्भ में, जिसे धारा 6 (1) में पढ़ा जाना है, केवल विवादित क्षेत्र से संबंधित है, जबकि अतिरिक्त क्षेत्र के किसी भी हिस्से का हस्तांतरण, जिसे विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद के निर्णय तक बनाए रखना आवश्यक नहीं हो सकता है, तब तक बाधित नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त क्षेत्र का अधिग्रहण पूर्ण रूप से इस कर्तव्य के अधीन है कि यदि इसे बनाए रखना अनावश्यक पाया जाता है, तो इसे मालिक को बहाल किया जाए, जैसा कि संकेत दिया गया है।धारा 3 और 6 में "बनियान" शब्द का अर्थ अलग-अलग तरीके से लिया जाना चाहिए।

विवादित क्षेत्र और उसके आसपास का अतिरिक्त क्षेत्र।

डी.

हिंदुओं से संबंधित निकटवर्ती निर्विवाद क्षेत्र का अधिग्रहण

इस आधार पर हमला किया गया कि यह अनावश्यक था क्योंकि इसका स्वामित्व निर्विवाद है।विवादित क्षेत्र से सटे बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण का कारण बताया गया है।इसलिए, यह विवाद के समाधान से असंबंधित नहीं है जो पूरे अधिग्रहण का कारण है।हालाँकि, प्रथम दृष्टया, आस-पास के क्षेत्र का अधिग्रहण, जिसके संबंध में स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है और जो हिंदुओं का है, हिंदुओं के खिलाफ एक झुकाव प्रतीत हो सकता है, फिर भी बारीकी से जांच करने पर ऐसा नहीं है क्योंकि यह सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और बढ़ावा देने के बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए और धर्मनिरपेक्षता के पंथ के अनुरूप है।एक बार जब यह पाया जाता है कि केवल विवादित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अधिग्रहण करने की अनुमति है, तो आस-पास

च

इसके लिए, अंतिम न्यायनिर्णायक के परिणाम को लागू करने के लिए विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण के उद्देश्य को प्रभावी बनाना।यह सुनिश्चित करने के लिए कि विवाद में मुस्लिम समुदाय की सफलता की स्थिति में उनकी सफलता सार्थक बनी रहे, आवश्यक माने जाने वाले आस-पास के क्षेत्र का विस्तार नीति के क्षेत्र में है न कि न्यायिक जांच का मामला या अधिनियम की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए आधार, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था।हालाँकि, यह केंद्र सरकार के कर्तव्य की चेतावनी के साथ है कि वह इसे उसके मालिक को बहाल करे, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, यदि बाद में यह अनावश्यक पाया जाता है; और कुल आवश्यकता निर्धारित होने पर मालिक को अनावश्यक अधिग्रहण को चुनौती देने की स्वतंत्रता का आरक्षण।

हम धारा 6 में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं जो इसे असंवैधानिक बना दे।

एच.

एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 59

ए के आधार पर निहित होने के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की स्थिति

इसलिए, अधिनियम की धारा 3 विवादित क्षेत्र के संबंध में एक सांविधिक प्राप्तकर्ता का कर्तव्य है, जिसमें अयोध्या में विवादित ढांचे से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवाद के निर्णय के अंतिम परिणाम तक विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का प्रबंधन और प्रशासन करना शामिल है।हालाँकि, विवादित क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की केंद्र सरकार में निहित होना निरपेक्ष है। अधिनियम द्वारा अधिग्रहित पूरे क्षेत्र के दो हिस्सों के संबंध में धारा 3 और 6 में "बनियान" के अर्थ में ये अलग-अलग बी रंग हैं।

अब सवाल विवाद के निर्णय के तरीके का है,

जिसका अंतिम परिणाम विवादित क्षेत्र के हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले अधिनियम की धारा 6 (1) द्वारा विचारित कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की जानी है।

धारा 4 की उप-धारा (2) में सभी लंबित मुकदमों को कम करने का प्रावधान है।

और धारा 2 के तहत केंद्र सरकार में निहित किसी भी संपत्ति से संबंधित अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में कानूनी कार्यवाही।विवादित क्षेत्र पर प्रतिद्वंद्वी के दावे, जिन पर लंबित मुकदमों में निर्णय लिया जाना था, अब मुकदमों के उपशमन के परिणामस्वरूप उसमें निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।इसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय द्वारा उठाए गए कई बचाव भी समाप्त हो जाते हैं, जिसमें मीर बाकी द्वारा 1528 ईस्वी में मस्जिद के निर्माण के बाद से 400 से अधिक वर्षों तक विवादित क्षेत्र पर प्रतिकूल कब्जा करना भी शामिल है।जाहिर है, अपनाया गया वैकल्पिक विवाद समाधान ई तंत्र उसी दिन किए गए एक साथ संदर्भ का है।

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय को प्रश्न के निर्णय के लिए भेजा गया है।उन मुकदमों में बनाए गए मुद्दों से यह स्पष्ट है कि मुकदमों में निर्धारण के लिए मुख्य प्रश्न किए गए संदर्भ में शामिल नहीं है, और इसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा उठाए गए बचाव भी शामिल नहीं हैं।यह भी स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर, चाहे वह कुछ भी हो, लंबित मुकदमों में निर्धारण के लिए मूल प्रश्न का उत्तर नहीं देगा और यह विवादित क्षेत्र से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवाद को अपने आप हल नहीं करेगा। इसलिए अनुच्छेद 143 (1) के तहत दिए गए संदर्भ को लंबित मुकदमों के प्रतिस्थापन में एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है।

अधिनियम की धारा 4 (3) द्वारा।इस कारण से, यह आग्रह किया गया था कि उपशमन

लंबित मुकदमों का निपटान विवाद के समाधान के लिए मुस्लिम समुदाय को उपलब्ध न्यायिक उपचार से इनकार करने और संविधान द्वारा परिकल्पित कानून के शासन के तहत निवारण की योजना के अनुसार उस आधार पर राहत देने के बराबर है।धारा 4 की उप-धारा (5) की वैधता इस आधार पर निर्धारित की गई है।

एच.

में 60

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख की सराहना करने के लिए, हमने विद्वान सॉलिसिटर जनरल को इस संबंध में भारत संघ के लिए एक स्पष्ट बयान देने की अनुमति दी।भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा लिखित दिनांक 14.9.1994 में दिया गया अंतिम बयान, जो रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, लगभग सुनवाई के समापन पर, यह भी संकेत नहीं देता है कि संदर्भित प्रश्न का उत्तर स्वयं मूल रूप से निर्णायक होगा।

बी विवादित स्थल पर दावे से संबंधित मुकदमों के पक्षकारों के बीच विवाद में प्रश्न।बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच बातचीत की प्रक्रिया का सहारा लेने का प्रस्ताव रखा है

निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद, और यदि वार्ता विफल हो जाती है, तो ऐसा मार्ग अपनाना जो परिस्थितियों में उचित लगे। इन परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत किए गए विशेष संदर्भ सी को एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है जो लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही के प्रतिस्थापन की अनुमति देता है।हमारी राय में, केवल यह तथ्य उप को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।

अधिनियम की धारा 4 की धारा (3)।श्रीमती को देखें।इंदिरा नेहरू गांधी/श्री राज नारायण बनाम।श्री राज नारायण/श्रीमती।इंदिरा नेहरू गर्धी, [1975] पूरक।एससीसी 1.घ हम तदनुसार धारा 4 की उप-धारा (3) को असंवैधानिक घोषित करते हैं।हालांकि, धारा 4 की उप-धारा (3) अलग करने योग्य है, और इसलिए, इसकी अयोग्यता शेष क़ानून को वैध बनाए रखने में बाधा नहीं है।

ई अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान की वैधता के लिए कोई गंभीर चुनौती नहीं है, सिवाय धारा 8 पर एक शुल्क योग्य हमले के।धारा 8 के लिए, यह आग्रह किया गया था कि इसके तहत मुआवजे के भुगतान का प्रदर्शन उस संपत्ति के संबंध में अव्यावहारिक होगा जिसका स्वामित्व विवाद में है।यह तर्क स्वयं शेष निर्विवाद संपत्ति के संबंध में ऐसी किसी कठिनाई की कल्पना नहीं करता है।इस दृष्टिकोण से हमने यह लिया है कि इस संबंध में धारा 3 के आधार पर केंद्र सरकार में निहित होना।

च

विवादित को केवल एक वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में दिया जाता है, और धारा 4 (3) को अमान्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप लंबित मुकदमों और कानूनी मामलों को फिर से शुरू किया जाता है।

कार्यवाहियों में, धारा 8 के अनुप्रयोग में कोई कठिनाई नहीं होगी।धारा 8 केवल विवादित क्षेत्र के बगल में और उसके आसपास होने के कारण विवादित क्षेत्र के अलावा पूरी तरह से अर्जित संपत्ति के लिए है।जी विवादित क्षेत्र को केवल केंद्र सरकार के अधिकार में लिया जा रहा है

वैधानिक प्राप्तकर्ता, इसके लिए मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यह न्यायिक निर्णय के विश्वसनीय कार्यान्वयन के लिए, मुकदमों में सफल पक्ष को, उसमें अंतिम न्यायिक फैसले के संदर्भ में, सौंपा जाना है।केंद्र सरकार द्वारा धारा 8 के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना है जब विवादित क्षेत्र एच के संबंध में अंतिम न्यायिक निर्णय के अनुसार, उसमें यथास्थिति बनाए रखते हुए एम. आई. फारूकी बनाम.

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 61

तब तक धारा 7 (2) के संदर्भ में।इस पहलू पर आगे कोई चर्चा नहीं है ए

आवश्यक है।गुटबाजी और कलह को बढ़ावा देने के लिए एक सख्त शाब्दिक निर्माण की तुलना में एक ऐसा निर्माण जिसे क़ानून की भाषा एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य को सहन कर सकती है और बढ़ावा दे सकती है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मस्जिद-अधिग्रहण से समुदाय सुनवाई में उठाया गया एक बड़ा सवाल यह था कि सुनवाई में कोई शक्ति नहीं है।

इस्लाम धर्म के पालन के लिए इसके महत्व की परवाह किए बिना किसी भी मस्जिद का अधिग्रहण करने के लिए राज्य।तर्क यह है कि एक मस्जिद, भले ही उसका इस्लाम धर्म के अभ्यास के लिए कोई विशेष महत्व न हो, मुसलमान कानून में मस्जिद के विशेष दर्जे के कारण प्राप्त नहीं की जा सकती है।यह तर्क विशेष महत्व की मस्जिद तक ही सीमित नहीं था, जिसके बिना धर्म का पालन करने का अधिकार कल्पनीय नहीं है क्योंकि यह इस्लाम के अभ्यास का एक आवश्यक और अभिन्न अंग हो सकता है।इस दृष्टिकोण से कि हमने केंद्र सरकार को उस विवादित क्षेत्र के वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में सीमित निहित किया है, जिसमें मस्जिद खड़ी थी, डी उद्देश्य के लिए इसे उसके हकदार पक्ष को सौंपना और तब तक उसमें यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है, यह प्रश्न किसी भी व्यावहारिक महत्व का नहीं हो सकता है क्योंकि उस संपत्ति के वास्तविक मालिक का कोई पूर्ण विनिवेश नहीं है।हम देख सकते हैं कि प्रस्तावित प्रस्ताव हमें स्वीकार करने के लिए बहुत व्यापक प्रतीत होता है क्योंकि यह अधिग्रहण की संप्रभु शक्ति को प्रतिबंधित कर देगा, भले ही इस तरह का अधिग्रहण ई के लिए एक निस्संदेह राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, अगर मस्जिद एक धर्म के रूप में इस्लाम के अभ्यास के लिए किसी विशेष महत्व के बिना पूजा के एक सामान्य स्थान के रूप में अधिग्रहित संपत्ति में स्थित हो।इससे यह भी अजीब परिणाम निकलेगा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में

इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के खिलाफ भेदभाव।इसे ध्यान में रखते हुए

डॉ. राजीव धवन एफ और श्री अब्दुल हन्नान ने जिस प्रबलता के साथ यह तर्क दिया कि अधिग्रहण केवल इसी कारण से अमान्य है, हमारे लिए इस प्रश्न पर निर्णय लेना आवश्यक है।

यह तर्क दिया गया है कि मस्जिद का अधिग्रहण भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन करता है।इसके लिए मुसलमान कानून के तहत मस्जिद की स्थिति के संदर्भ की आवश्यकता होती है।संविधान से पहले भी भारत में पूजा स्थलों को विशेष पवित्रता प्राप्त थी।पूजा स्थलों को विशेष सुरक्षा देने और ब्रिटिश भारत में विभिन्न धार्मिक

अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से रोकने के लिए, भारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय XV अधिनियमित किया गया था।यह अध्याय विशेष रूप से एच 62 से संबंधित अपराधों से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295,295 ए, 296,297 और 298 में एक धर्म।लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करते हुए संकेत दिया था कि

जिस सिद्धांत पर सभी सरकारों के लिए कार्रवाई करना वांछनीय था और भारत में ब्रिटिश सरकार समाज के विघटन का जोखिम उठाए बिना इससे अलग नहीं हो सकती थी।भारत के लोगों की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी करने के खतरे का भी संकेत दिया गया, जिससे पूरे देश में असंतोष फैल सकता है।

ब्रिटिश भारत में, मस्जिद में मुसलमानों और मंदिर में हिंदुओं की पूजा करने के अधिकार को हमेशा एक नागरिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।1950 से पहले, ब्रिटिश भारत में भारतीय न्यायालयों ने सी पूजा के अपने अधिकार के संबंध में विभिन्न समुदायों या संप्रदायों के बीच संतुलन बनाए रखा था।

भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी से पहले भी।मुथियालू चेट्टी और ओआरएस में मुख्य न्यायाधीश टर्नर।वी.बापून सैब, आई. एल. आर. 2 मद्रास 140 ने माना था कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और राज्य को तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।

घ. लोक कल्याण का ध्यान रखना।सुंदरम चेट्टी और ओआरएस में।वी.क्वीन, आई. एल. आर. 6 मद्रास 203 (एफ. बी.) ने आई. एल. आर. 2 मद्रास 140 को मंजूरी देते हुए मुख्य न्यायाधीश टर्नर ने कहाः

" ..... लेकिन इन और अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में

जाति या पंथ के आधार पर दावा किया गया, मैं देख सकता हूं कि

YE

उनकी उत्पत्ति उस समय हुई थी जब एक राज्य धर्म था

देश के सार्वजनिक और निजी कानून को प्रभावित किया, और उन सिद्धांतों के साथ शायद ही संगत हैं जो ब्रिटिश प्रशासन को विनियमित करते हैं, सभी नागरिकों के समान अधिकार और मामलों में राज्य की पूर्ण तटस्थता

धर्म। जब अराजकता या निरंकुशता कुएँ को स्थान देती है

च

आदेशित स्वतंत्रता, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन एक में परिवर्तन

दिशा जो की सहमति का आदेश देना चाहिए

देश की खुफिया जानकारी "।

(पृष्ठ 217 पर) जी मस्जिद में जिसे मस्जिद शाहिद गंज के नाम से जाना जाता है और अन्य बनाम।शिरोम।गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर, ए. आई. आर. (1938) लाहौर 369 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां एक मस्जिद पर प्रतिकूल रूप से कब्जा किया गया है,

मुसलमान, इसने मस्जिद के रूप में अपना पवित्र चरित्र खो दिया।इसलिए, यह विचार कि एक बार मस्जिद का निर्माण हो जाने के बाद, यह हमेशा एक मस्जिद के रूप में पूजा का स्थान बना रहता है, भारतीय न्यायालयों द्वारा अनुमोदित भारत का मुसलमान कानून नहीं था।एच ने आगे बहुमत द्वारा यह माना कि भारत में एक मस्जिद एक अचल एम. आई. फारूकी बनाम थी।

यू. ओ. आई. (जे. एस. वर्मा, जे.) 63

किसी विशेष स्थान पर संपत्ति और पूजा का अधिकार तब खो जाता है जब अधिकार ए

जिस संपत्ति पर यह खड़ा है, वह प्रतिकूल कब्जे से खो जाती है।दीन मोहम्मद के अल्पमत निर्णय में यह निष्कर्ष निकला।, जे. ब्रिटिश भारत का मुसलमान कानून नहीं है।लाहौर उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए बहुमत के विचार को ए. आई. आर. (1940) पी. सी. 116 में लाहौर उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील में प्रिवी काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

अदालत।प्रिवी काउंसिल ने कहाः "..... आधुनिक सीमा अधिनियमों में मस्जिद के उद्देश्यों के लिए वक्फ की गई संपत्ति के लिए किसी भी अपवाद को पढ़ना असंभव है, चाहे उसका उद्देश्य केवल मस्जिद के रखरखाव और संचालन के लिए धन प्रदान करना हो या उस उद्देश्य के लिए एक स्थान और भवन प्रदान करना हो।जबकि उनके प्रभुओं को उस धार्मिक भावना के साथ पूरी सहानुभूति है जो किसी पूजा स्थल की पवित्रता और अनुल्लंघनीयता को दर्शाती है, वे सीमा अधिनियम के तहत इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसी इमारत पर वक्फ के प्रतिकूल कब्जा नहीं किया जा सकता है, या यह कि जब तक इसे "मस्जिद" के रूप में संदर्भित किया जाता है या जब तक कि इमारत को जमीन पर नहीं गिराया जाता है या डी वह रूप नहीं खो देता है जो इसके मूल उद्देश्य को प्रकट करता है।(पृष्ठ 121 पर) यह भी संकेत दिया जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

पूजा स्थलों सहित सभी संपत्तियों पर समान रूप से लागू।इसके तहत ई अधिग्रहण का अधिकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के स्पष्ट प्रावधानों द्वारा निर्देशित था और पूजा स्थलों के अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए कार्यकारी निर्देश जारी किए गए थे।भूमि नियमावली का खंड 102

महाराष्ट्र राज्य का अधिग्रहण जो चर्चों, मंदिरों और मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थानों के अधिग्रहण से संबंधित है, एफ में महत्वपूर्ण है

इस संदर्भ में।अधिग्रहण की शक्ति संप्रभु या विशेषाधिकार शक्ति है

संपत्ति अर्जित करने के लिए राज्य।ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 300 ए या संविधान के पूर्ववर्ती अनुच्छेद 31 से स्वतंत्र है जो केवल राज्य द्वारा अधिग्रहण की शक्ति पर सीमाओं का संकेत देती है।सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू से ही संपत्ति हासिल करने के लिए राज्य की संप्रभु जी शक्ति को लगातार बरकरार रखा है।बी. के. मुखर्जी, जे. (जैसा कि वे तब थे) को चिरनजीतलाल चौधरी बनाम में रखा गया था।भारत संघ और अन्य, [1950] एस. सी. आर. 869 पृष्ठों पर 901-902 निम्नानुसारः

" प्रत्येक संप्रभु में यह अंतर्निहित अधिकार है कि वह व्यक्तिगत नागरिकों की निजी संपत्ति को ले और उसका उपयोग करे।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

64

सार्वजनिक उपयोग के लिए।यह अधिकार, जिसे प्रतिष्ठित के रूप में वर्णित किया गया है

क.

अमेरिकी कानून में क्षेत्र, कराधान की शक्ति की तरह है, राजनीतिक आवश्यकता की संतान है, और यह सरकार द्वारा निहित आरक्षण पर आधारित माना जाता है कि

इसके संरक्षण के तहत इसके नागरिकों द्वारा अर्जित निजी संपत्ति को लिया जा सकता है या सार्वजनिक लाभ के लिए इसका उपयोग नियंत्रित किया जा सकता है।

मालिक की इच्छाओं के बावजूद "।

पतंजलि शास्त्री, सी. जे., पश्चिम बंगाल राज्य बनाम।सुबोध गोपाल बोस और अन्य।, [1954] पृष्ठ 605 पर एस. सी. आर. 587 निम्नानुसार हैः

" ..... और ऐसी शक्तियों में संघ के लिए "संपत्ति के अधिग्रहण या अधिग्रहण" की शक्ति शामिल थी और

एस.

सूची I की प्रविष्टि संख्या 33 और सूची II की प्रविष्टि संख्या 36 में क्रमशः राज्य के उद्देश्य।इस प्रकार, जिसे विशिष्ट क्षेत्र की शक्ति कहा जाता है, जिसे महाद्वीपीय और अमेरिकी न्यायविदों के अनुसार राज्य की संप्रभुता में निहित माना जाता है

और तदनुसार स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है

अमेरिकी संविधान, एक एक्सप्रेस का विषय बना दिया गया है

डी.

हमारे संविधान में अनुदान "।

इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों से यह प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण के अधीन, मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि जैसे धार्मिक पूजा स्थलों को राज्य की अधिग्रहण की संप्रभु शक्ति के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है।इस तरह के अधिग्रहण से संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं होता है। प्रबंधन को संभालने से संबंधित निर्णयों का संपत्ति हासिल करने की राज्य की संप्रभु शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है।

खजमियन वक्फ एस्टेट आदि।मद्रास राज्य और एक अन्य, [1971] पृष्ठ 797 पर 2 एफ एस. सी. आर. 791 ने कहा हैः

" इसके बाद यह आग्रह किया गया कि धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण करके विधायिका

कला का उल्लंघन किया।26 (ग) और (घ) जो यह प्रावधान करते हैं कि धार्मिक संप्रदायों को स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार होगा।

जी.

चल और अचल संपत्ति और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन।ये प्रावधान संपत्ति अर्जित करने के राज्य के अधिकार को नहीं छीनते हैं।

धार्मिक संप्रदायों से संबंधित।वे मूल्यवर्ग संपत्तियों का स्वामित्व या अधिग्रहण कर सकते हैं और उन्हें कानून के अनुसार प्रशासित कर सकते हैं।इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति

एच.

उनके स्वामित्व का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।

एम. आई. फारूकी बनाम के परिणामस्वरूप।यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 65 अधिग्रहण के बाद वे उस संपत्ति के मालिक नहीं बन जाते।इसके बाद उस संपत्ति को प्रशासित करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि यह नहीं है

उनकी संपत्ति को लंबा करें।अनुच्छेद 26 इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है

संपत्ति अर्जित करने का राज्य का अधिकार।

आचार्य महाराजश्री नारंद्र प्रसादजी आनंद प्रसादजी महाराज

2

आदि।वी.गुजरात राज्य और अन्य, [1975] पृष्ठ 327-बी पर 2 एससीआर 317

328 , आयोजित किया गया हैः

"< ‘ ..... हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि अनुच्छेद 26 अन्य बातों के साथ-साथ चल और अचल वस्तुओं के स्वामित्व और अधिग्रहण के अधिकार की गारंटी देता है।

धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए अचल संपत्ति।हालाँकि, यह अधिकार राज्य के सी के अनिवार्य रूप से संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को छीन नहीं सकता है। यदि दूसरी ओर, राज्य द्वारा किसी धार्मिक संप्रदाय की संपत्ति का अधिग्रहण ऐसा साबित हो सकता है कि वह उसके चल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण के अधिकार को नष्ट या पूरी तरह से नकारात्मक कर सकता है और

किसी धार्मिक संस्था के अस्तित्व के लिए भी अचल संपत्ति के सवाल की ए. डी. में जांच करनी पड़ सकती है।

अलग रोशनी।

(जोर दिया गया)

1

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 25 में कोई संदर्भ नहीं है -

संविधान के अनुच्छेद 26 के विपरीत संपत्ति।संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने के अधिकार में आवश्यक रूप से संपत्ति हासिल करने या रखने या रखने का अधिकार शामिल नहीं है।इसी तरह यह अधिकार किसी भी और हर पूजा स्थल पर पूजा के अधिकार तक नहीं फैला है ताकि किसी विशेष स्थान पर पूजा करने में कोई बाधा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सके।संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास के लिए है जो धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है।एक प्रथा एक धार्मिक प्रथा हो सकती है लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं हो सकती है।

ई.

च

जबकि प्रार्थना या पूजा की पेशकश एक धार्मिक प्रथा है, जी में इसकी पेशकश

प्रत्येक स्थान जहाँ ऐसी प्रार्थनाएँ की जा सकती हैं, ऐसी धार्मिक प्रथा का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं होगा जब तक कि उस स्थान का उस धर्म के लिए कोई विशेष महत्व न हो ताकि वह उसका एक आवश्यक या अभिन्न अंग बन सके।विशेष महत्व रखने वाले किसी भी धर्म के पूजा स्थल

कि धर्म, इसे धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग बनाने के लिए, एक अलग आधार पर खड़ा है और इसके साथ अलग और अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

एच 66

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. पाँच-न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ, राजा सूर्यपालसिंह अन्य बनाम।उत्तर प्रदेश सरकार।, आकाशवाणी (1951) सभी।674 , आयोजितः "अनुच्छेद 25 (1) और 26, सी. एल. के आधार पर कुछ वक्फों और हिंदू धार्मिक संस्थानों की ओर से विद्वान वकीलों द्वारा तर्क दिए गए हैं।((ग) संविधान का।

यह कहा जाता है कि यदि वक्फ संपत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित की जाती है तो अपने धर्म का प्रचार करने के मुतवल्ली के अधिकार का उल्लंघन होता है, लेकिन अनुच्छेद 31 के तहत उस संपत्ति के अधिग्रहण (जिसके लिए अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्पष्ट रूप से विषय है) का ऐसे अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं है और किसी भी तरह से इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है।

यह अभ्यास "।

ग

(पृष्ठ 690 पर) यह तर्क दिया गया है कि एक मस्जिद को विशेष स्थान प्राप्त है

मुस्लिम कानून और एक बार जब एक मस्जिद स्थापित हो जाती है और उसी में नमाज अदा की जाती है तो कभी भी मस्जिद के दाता या संस्थापक को वापस नहीं किया जाता है और कोई भी मस्जिद अल्लाह और उसकी संपत्ति बनने के लिए हमेशा के लिए बनी रहती है।

डी.

इस्लामी आस्था रखने वाला व्यक्ति ऐसी मस्जिद में प्रार्थना कर सकता है और भले ही संरचना को ध्वस्त कर दिया जाए, वह स्थान वही रहता है जहां नमाज अदा की जा सकती है।जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया है, ब्रिटिश भारत में, एक मस्जिद को ऐसा कोई संरक्षण नहीं दिया गया था और मस्जिद को सीमा के क़ानून के ई प्रावधानों के अधीन किया गया था, जिससे मुसलमानों के उस संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से खोए हुए एक विशेष मस्जिद में प्रार्थना करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (26) श्रेणियों को समझती है।

भारतीय कानून द्वारा ज्ञात संपत्तियों का।संविधान के अनुच्छेद 387 में कहा गया है कि चर्च या मस्जिद आदि अनिवार्य रूप से अचल संपत्तियां हैं और अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण के अधीन हैं।प्रत्येक अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है।उचित परिप्रेक्ष्य में देखने पर, एक मस्जिद को कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलती है जो अन्य धर्मों के धार्मिक पूजा स्थलों के लिए उपलब्ध नहीं है।

जी.

सही स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, भारत में लागू होने वाले मुसलमान कानून के तहत, प्रतिकूल कब्जे से मस्जिद का अधिकार खो दिया जा सकता है।

(मुल्ला के मुहम्मद कानून के सिद्धांत, 19 वीं संस्करण देखें।एम. हिदायतुल्ला द्वारा-सेक.217 :और AIR (1940) PC 116)। यदि कानून में यही स्थिति है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि एक मस्जिद को एक अद्वितीय या विशेष दर्जा है, जो धर्मनिरपेक्ष भारत में अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में उच्च एच है।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 67

यह राज्य की संप्रभु या विशेषाधिकार ए शक्ति का प्रयोग करके अधिग्रहण से मुक्त है।एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज (प्रार्थना) कहीं भी, यहां तक कि खुले में भी अदा की जा सकती है।तदनुसार, इसके अधिग्रहण द्वारा निषिद्ध नहीं है

भारत के संविधान में प्रावधान।संप्रभु शक्ति के प्रयोग में राज्य द्वारा अधिग्रहण से प्रतिरक्षा के उद्देश्य से एक इस्लामी देश में एक मस्जिद की स्थिति चाहे जो भी हो, संविधान के तहत भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार में अधिग्रहण से इसकी स्थिति और प्रतिरक्षा बी अन्य धर्मों, जैसे चर्च, मंदिर आदि के पूजा स्थलों के समान और बराबर है। यह अन्य धर्मों के पूजा स्थलों से न तो अधिक है और न ही कम।जाहिर है, किसी भी धार्मिक स्थान का अधिग्रहण केवल असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किया जाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप धर्म का पालन करने का अधिकार समाप्त नहीं होना चाहिए, यदि उस स्थान का महत्व ऐसा है।इस शर्त के अधीन, अधिग्रहण की शक्ति किसी भी धर्म के किसी भी अन्य पूजा स्थल की तरह एक मस्जिद के लिए उपलब्ध है।पूजा का अधिकार किसी भी और हर स्थान पर नहीं है, जब तक कि इसका प्रभावी ढंग से अभ्यास किया जा सके, जब तक कि किसी विशेष स्थान पर पूजा करने का अधिकार स्वयं एक डी है।

उस अधिकार का अभिन्न अंग।संदर्भ की प्रमुखता इस दृष्टिकोण से कि हमने क़ानून (1993 का अधिनियम संख्या 33) की वैधता के प्रश्न को लिया है और इसकी धारा 4 (3) को छोड़कर पूरे क़ानून की वैधता को बनाए रखने के परिणामस्वरूप, लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही का पुनरुद्धार होता है जिसमें पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेना होता है, अनुच्छेद 143 (1) के तहत किया गया संदर्भ अनावश्यक और अनावश्यक हो जाता है।इस कारण से, हमारे लिए इस संदर्भ की स्थिरता पर की गई प्रस्तुतियों के गुण-दोष की जांच करना अनावश्यक है।तदनुसार, हम बहुत सम्मानपूर्वक संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करते हैं और एफ उसी का उत्तर देता है।

ई.

परिणाम यह है कि सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जाता है, और उन्हें निम्नलिखित के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और निर्णय लिया जाएगाः

कानून।इसके बाद शेष अधिनियम को वैध के रूप में बरकरार रखा गया कि विवादित क्षेत्र ने केंद्र सरकार को एक वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में निहित किया है, जिसका कर्तव्य है कि वह धारा 7 (2) में अधिनियमित फ्रीज के आधार पर अधिनियम में

प्रदान किए गए तरीके से इसका प्रबंधन और प्रशासन करे और केंद्र सरकार उस संपत्ति को किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या ट्रस्ट एच को सौंपने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी।

जी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी.5 एस सी आर।

68

ए लंबित मुकदमों में अंतिम निर्णय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार।लंबित कानूनी कार्यवाही में न्यायालयों की केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति

वैधानिक प्राप्तकर्ता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा खुले क्षेत्र की सीमा तक सीमित और सीमित होगा।केंद्र सरकार मुकदमे बी और अन्य कानूनी कार्यवाही में निर्णय को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और मुकदमों में किए गए अंतिम निर्णय पर विवादित क्षेत्र को उसी पक्ष को सौंपने के लिए बाध्य होगी।मुकदमों के पक्षकार हमारे निर्णय के आलोक में अपनी दलीलों में उपयुक्त संशोधन करने के हकदार होंगे।

समाप्त करने से पहले, हम परिणाम का संकेत देना चाहेंगे यदि पूरे अधिनियम को अमान्य माना गया था तो हमने जवाब देने से इनकार कर दिया था

उस निष्कर्ष पर संदर्भ।इसके परिणामस्वरूप उसमें किए गए सभी अंतरिम आदेशों के साथ-साथ कम की गई बुद्धि का पुनरुद्धार होगा।इसके परिणामस्वरूप हिंदू भक्तों द्वारा मूर्तियों की पूजा को स्वचालित रूप से पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसे भी दिसंबर 1992 से बंद कर दिया गया है, इसके सभी प्रभावों के साथ मुस्लिम समुदाय को कोई लाभ दिए बिना, जिनकी मस्जिद में डी पूजा की प्रथा (6 दिसंबर, 1992 को ध्वस्त) आई थी।

कम से कम दिसंबर 1949 से किसी भी कारण से रुकें।यह स्थिति, जब तक कि पुनर्जीवित मुकदमों में किसी भी अदालती आदेश द्वारा बाद में नहीं बदली जाती है, इसलिए मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगी।यह परिणाम उन मुसलमानों के लिए कोई सांत्वना नहीं हो सकता है, जिनकी मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप आहत होने की भावनाओं को दूसरे समुदाय को किसी भी वैध शिकायत का कारण दिए बिना यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से शांत किया जाना चाहिए, जिससे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना के लिए हानिकारक सांप्रदायिक भावनाओं को फिर से स्थापित करने की संभावना हो।

इसलिए, मुकदमों के पुनरुद्धार पर परिस्थितियों में सबसे अच्छा समाधान यह है कि 7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखी जाए, जब विवादित क्षेत्र में हिंदुओं द्वारा पूजा की प्रथा को इस हद तक कम करके मुकदमे में अंतरिम आदेशों को संशोधित करने के लिए कानून लागू हुआ कि उन्हें अधिक अधिकार प्रदान करने के बजाय अधिनियम के तहत यह कम हो गया है।

अदालत के आदेशों के तहत तब तक उपलब्ध है जब तक कि कानून द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।जी धारा 7 (2) हिंदू भक्तों द्वारा पूजा के लिए अंतरिम व्यवस्था को इस हद तक कम करके इस उद्देश्य को प्राप्त करती है और अदालत के आदेशों के तहत उन्हें प्राप्त बड़े अधिकार को कम करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे विवाद के अंतिम निर्णय तक बढ़ाया नहीं जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप विवादित क्षेत्र को उसी के हकदार पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है।यह धारा 7 (2) का उद्देश्य और वास्तविक प्रभाव होने के कारण, इसे बढ़ावा देता है और मजबूत करता है

एच. आई. इसे नकारने के बजाय धर्मनिरपेक्षता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता।

इस एम. आई. फारूकी बनाम को आयोजित करने के लिए।यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 69

धर्मनिरपेक्षता विरोधी और हिंदू समुदाय ए के पक्ष में झुका हुआ प्रावधान धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रयास को विफल करने और 6 दिसंबर, 1992 की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ताकतों का अनजाने में समर्थन करने के लिए होगा।

सामान्य

संदर्भ में कुछ सामान्य टिप्पणियां उपयुक्त हैं।हमें बार के विद्वान सदस्यों के प्रति अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय लोकाचार के लिए असाधारण और असामान्य महत्व के इस मामले की सुनवाई में हमारी सहायता की।विद्वान महान्यायवादी, विद्वान महान्यायवादी, मध्य प्रदेश के विद्वान महान्यायवादी, राजस्थान के विद्वान महान्यायवादी, श्री एफ. बी. नरीमन, श्री सोली जे. सी. सोराबजी, स्वर्गीय श्री आर. के. गर्ग, डॉ. राजीव धवन, श्री अनिल बी. दीवान, श्री सतीश चंद्र, श्री पी. पी. राव, श्री अब्दुल मन्नान, श्री एस. एन. मेहता, श्री आई. डी. 2, श्री वी. एम. तारकुंडे, श्री अशोक एच. देसाई, श्री शकील

अहमद सैयद, सुश्री एन. भगत और अन्य विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने बार की सर्वोच्च परंपराओं में उद्योग के बाद बड़े उत्साह के साथ उनकी बहुमूल्य सहायता की।श्री देवकी डी नंदन अग्रवाल, जो देवता के अगले मित्र के रूप में एक सूट में पक्षकारों में से एक थे, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और पूर्ण अलगाव के साथ बहस की।डॉ. एम. इस्माइल फारूकी भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, यह विशेष रूप से खुशी की बात थी कि मुस्लिम समुदाय के उद्देश्य की वकालत अन्य समुदायों से संबंधित बार के सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से की गई थी।इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ई इस तथ्य से स्पष्ट है कि सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए श्री अब्दुल मन्नान ने मुस्लिम समुदाय की ओर से तर्कों का समर्थन किया।श्री मन्नान का पारस्परिक भाव समान रूप से उत्साहजनक और आपसी विश्वास का संकेत था।जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी सुनवाई हुई, वह व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता की सच्ची अभिव्यक्ति थी।

च

सुनवाई ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया कि विवाद को उसी तरीके से और उसी भावना से क्यों हल नहीं किया जा सकता है जिसमें मामले पर बहस की गई थी, विशेष रूप से जब कुछ प्रतिभागी आम हैं और बातचीत करने और विवाद को हल करने की स्थिति में हैं।हम आशा करते हैं कि यह सुनवाई उस प्रक्रिया की शुरुआत रही है जो जी विवाद का एक सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करेगी और यह इस मामले की सुनवाई के साथ समाप्त नहीं होगी।यह एक ऐसा मामला है जो अनिवार्य रूप से बातचीत द्वारा मांग के लिए उपयुक्त है जो एक में समाप्त नहीं होता है

विजेता और हारने वाला जबकि निर्णय उस लक्ष्य की ओर ले जाता है।यह राष्ट्रीय हित में है कि विवाद के समाधान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के अंत में कोई हारने वाला न हो ताकि अंतिम परिणाम किसी में भी कोई गड़बड़ी न छोड़े।यह एच. सुपरम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी. पी. के आधार पर एक बातचीत समाधान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

5 एस सी आर।

70

ए जिसे इन मुकदमों में ऐसे समाधान के संदर्भ में एक डिक्री प्राप्त की जा सकती है।जब तक कोई ऐसा समाधान नहीं निकलता जो सभी को खुश कर दे, तब तक "हम भारत के लोगों" के बीच निरंतर सद्भाव की शुरुआत नहीं हो सकती।1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था।संसद के अध्यक्ष जॉन हेनरी बैरोज़ ने इसके उद्देश्य का संकेत दिया और

बी ने देखा "।यह बुद्धिमानी और लाभप्रद महसूस किया गया कि दुनिया के धर्म, जो सभी महाद्वीपों में कई बिंदुओं पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उन्हें एक कमरे में विवाद के लिए नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण सम्मेलन के लिए एक साथ लाया जाना चाहिए।संसद में स्वामी विवेकानंद ने 'हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में बताया जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है' और धर्मों की विविधता को 'एक ही प्रकाश जो विभिन्न रंगों से आता है' के रूप में वर्णित किया।सभा ने एक सार्वभौमिक प्रार्थना के रूप में प्रभु की प्रार्थना का पाठ किया और रब्बी एमली हिर्श ने घोषणा की "राष्ट्रीय धर्मों का दिन बीत चुका है।ब्रह्मांड के भगवान सभी मानव जाति को खुश करते हैं "।समापन सत्र में संसद के मुख्य दूरदर्शी लोगों में से एक, शिकागो के वकील चार्ल्स बोनी ने घोषणा की, "अब से दुनिया के धर्म एक-दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि मानव जाति को पीड़ित करने वाली विशाल बुराइयों के खिलाफ युद्ध करेंगे।"क्या हम पिछली शताब्दी के दौरान घोषित लक्ष्य की ओर बढ़े हैं?

" जैसे ही 1993 की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक हिंसा भारत में लौट आई, जो 16 वीं शताब्दी की एक मस्जिद पर विवाद के कारण शुरू हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान राम के सम्मान में एक प्राचीन हिंदू मंदिर के खंडहरों पर खड़ी है।यह कहा जा सकता है कि

' कट्टरवाद और बहुलवाद दो चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं जिनका सामना सभी ई धार्मिक परंपराओं के लोग करते हैं और "कट्टरपंथियों के लिए, धार्मिक निश्चितता की सीमाओं को कसकर संरक्षित किया जाता है; बहुलतावादियों के लिए, सीमाएं अच्छी बाड़ हैं जहां कोई पड़ोसी से मिलता है।कई कट्टरपंथियों के लिए,

धर्मनिरपेक्षता, जिसे धार्मिक दावों के खंडन के रूप में देखा जाता है, दुश्मन है; बहुलवादियों के लिए, धर्मनिरपेक्षता, जिसे एफ एकल धर्म के प्रभुत्व से सरकार के अलगाव के रूप में देखा जाता है, धार्मिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का आवश्यक सहवर्ती है।वर्तमान स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:वर्तमान में, सबसे बड़ा धार्मिक तनाव किसी एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच नहीं है; वे प्रत्येक धार्मिक परंपरा में कट्टरपंथी और बहुलवादी के बीच तनाव हैं।19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय सार्वभौमिकता की भावना को मैक्स मुलर जी द्वारा चित्रित किया गया था, जिन्होंने कहा था, "धर्म का जीवित आधार पाया जा सकता है।मैं लगभग हर पंथ में विश्वास करता हूं, चाहे भूसी कितनी भी भिन्न क्यों न हो।सोचिए इसका क्या मतलब है।इसका मतलब है कि सभी धर्मों के ऊपर और नीचे और पीछे एक है

शाश्वत, एक सार्वभौमिक धर्म "।वर्ष 1993 को "अंतर-धार्मिक वर्ष" के रूप में वर्णित किया गया है।

एच. समझ और सहयोग "।क्या सुलह की वह शताब्दी पुरानी भावना एम. आई. फारूकी बनाम है?

यू. ओ. आई. (जे. एस. वर्मा, जे.) 71

और 1993 को "अंतर-धार्मिक समझ और सहयोग का वर्ष" कहे जाने को सही ठहराने के लिए विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के नायकों की प्रतिक्रियाओं में सह-संचालन परिलक्षित हुआ?(" स्पैन में डायना एल. बी. सी. के. द्वारा "धार्मिक विविधता पर प्रतिबिंब"-सितंबर 1994)।यही वह आशा है जिसे भविष्य में साकार करना है।

बहाई धर्म में सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता के बारे में एक तटस्थ धारणा पाई जाती है।बहाई साहित्य का हिस्सा बनने वाली एक पुस्तिका, "सांप्रदायिक सद्भाव-भारत की सबसे बड़ी चुनौती" में, यह इस प्रकार कहा गया हैः..... सहिष्णुता और आत्मसात करने की भावना हॉल है।

इस सभ्यता के संकेत।कभी नहीं हुआ सवाल

सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकीकरण ने आज की तरह भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दिया।

XXX

XXX

XXX

" भय, संदेह और घृणा वे ईंधन हैं जो सांप्रदायिक वैमनस्य और संघर्ष की लौ को जलाते हैं।हालांकि डी भारतीय जनता विभिन्न लोगों के बीच सद्भाव पसंद करेगी।

समुदाय, इसके माध्यम से स्थापित नहीं किया जा सकता है

आवास 'अलग लेकिन समान', न ही अल्पसंख्यक संस्कृति के बहुसंख्यक संस्कृति में डूबने के माध्यम से -

जो भी हो "।

ई.

" विषम समुदायों के बीच स्थायी सद्भाव केवल मानव जाति की एकता की मान्यता के माध्यम से आ सकता है, एक एहसास है कि जातीय और धार्मिक आधार पर हमें विभाजित करने वाले मतभेदों का कोई आधार नहीं है।जिस तरह पृथ्वी पर अलग-अलग राष्ट्रों की कोई सीमाएं नहीं हैं, उसी तरह लोगों द्वारा लगाए गए सामाजिक, आर्थिक, जातीय और धार्मिक पहचान के भेद कृत्रिम हैं; उन्होंने केवल निहित स्वार्थ वाले लोगों को लाभान्वित किया है।दूसरी ओर, ग्रह या देश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विविध क्षेत्रों, जैसे पहाड़ और मैदानों, में से प्रत्येक के अद्वितीय लाभ हैं।भगवान द्वारा बनाई गई विविधता का अनंत मूल्य है, जी जबकि मनुष्य द्वारा लगाए गए भेद का कोई सार नहीं है।

हम इस तीव्र आशा के साथ समापन करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि में जल्द ही सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और शांति आएगी, जिनके पसंदीदा भजन (भजन) थे -

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी.5 एस सी आर।

72

ईश्वर की इच्छा और प्रार्थनाओं का सम्मान करें।

क.

" ईश्वर और अल्लाह दोनों आपके नाम हैं।

हे भगवान!यह ज्ञान सभी को प्रदान करें।

"

हम आशा करते हैं कि भारत के लोग उनके सुसमाचार को याद रखेंगे।

उपदेश दिया और अभ्यास किया, और अपने आदर्शों पर खरा उतरा।कभी न होने से देर हो जाना बेहतर है।निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारे निष्कर्ष, के साथ पढ़ा जाना चाहिए

चर्चा इस प्रकार हैः

(1) (क) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) सभी लंबित मुकदमों को समाप्त करती है।

और एक वैकल्पिक विवाद के प्रावधान के बिना कानूनी कार्यवाही

पक्षकारों के बीच विवाद के समाधान के लिए समाधान तंत्र।यह डी विवाद के समाधान के लिए न्यायिक उपचार का विलुप्त होना है जो कानून के शासन को नकारने के बराबर है।धारा 4 की उप-धारा (3)

अतः अधिनियम असंवैधानिक और अमान्य है।(1) (ख) अधिनियम के शेष प्रावधान किसी भी समस्या से ग्रस्त नहीं हैं।

हमारे द्वारा किए गए निर्माण पर अयोग्यता।अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) शेष अधिनियम से अलग की जा सकती है। तदनुसार, उप अधिनियम को छोड़कर शेष अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती

ई.

धारा 4 की धारा (3) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(2) इस्लामी देशों में लागू मुस्लिम कानून के तहत मस्जिद की स्थिति के बावजूद, इसके तहत मस्जिद की स्थिति

धर्मनिरपेक्ष भारत में लागू होने वाला मुसलमान कानून किसी भी धर्म के किसी भी अन्य पूजा स्थल के समान और बराबर है और इससे बड़ा कोई कानून नहीं है।

च

अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में राज्य की संप्रभु या विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग में अधिग्रहण से प्रतिरक्षा।(3) विवादित क्षेत्र से संबंधित लंबित मुकदमे और अन्य कार्यवाहियां, जिसके भीतर संरचना (ऐसी संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित), जिसे आमतौर पर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, विवाद के निर्णय के लिए पुनर्जीवित हैं, जिसमें किए गए अंतरिम आदेश भी शामिल हैं, सिवाय इसके कि अंतरिम आदेश अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों द्वारा संशोधित किए गए हैं।(4) अधिनियम की धारा 3 के आधार पर एच द्वारा केंद्र सरकार को उक्त विवादित क्षेत्र का निहित होना एम. आई. एफ. ए. आर. यू. यू. आई. बनाम के साथ एक वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में सीमित है।

यू. ओ. आई. [जे. एस. वर्मा, जे.] 73 अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता वाली धारा 7 ए के अनुसार इसके प्रबंधन और प्रशासन के लिए कर्तव्य।वैधानिक प्राप्तकर्ता के रूप में केंद्र सरकार का कर्तव्य अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विवादित क्षेत्र को सौंपना है, जिसमें अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन के लिए मुकदमों में किए गए निर्णय के संदर्भ में।यही वह उद्देश्य है जिसके लिए विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है।

(5) मुकदमों में आगे अंतरिम आदेश देने की अदालतों की शक्ति अधिनियम की धारा 7 के दायरे से बाहर के क्षेत्र तक सीमित और सीमित है।

(6) विवादित क्षेत्र सी के अलावा आस-पास के क्षेत्र का निहित होना

अधिनियम की धारा 3 के आधार पर केंद्र सरकार में अधिनियम द्वारा अर्जित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अनुसार उसके प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति के साथ पूर्ण है, जब तक कि यह अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय या किसी न्यास के न्यासियों में निहित नहीं हो जाता है।अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विवादित

क्षेत्र के अलावा आस-पास के क्षेत्र को उसके अधिग्रहण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस समय और संकेतित तरीके से आगे निहित किया जाना चाहिए।

(7) संविधान की धारा 3 और धारा 6 में "बनियान" शब्द का अर्थ

अधिनियम को विभिन्न संदर्भों में इस तरह से समझना होगा।

ई.

(8) अधिनियम की धारा 8 पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के मालिकों को मुआवजे के भुगतान के लिए है, जिसका स्वामित्व विवादित क्षेत्र से अधिक होने पर विवाद में नहीं है, जो केवल पुनर्जीवित मुकदमों का विषय है।यह उस विवादित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, जिसके स्वामित्व पर मुकदमों में निर्णय लिया जाना है और जिसके संबंध में केंद्र सरकार केवल वैधानिक प्राप्तकर्ता है जैसा कि एफ ने संकेत दिया है, मुकदमे में किए गए निर्णय के संदर्भ में इसे मालिक को बहाल करने का कर्तव्य है।

(9) निकटवर्ती क्षेत्र के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण की चुनौती

इस आधार पर कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद को निपटाने के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह अनावश्यक है, इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है।जी हालांकि, विवाद के निर्णय पर निर्धारित किए जा रहे उद्देश्य के लिए आवश्यक सटीक क्षेत्र पर अनावश्यक क्षेत्र को निर्विवाद मालिकों को बहाल किया जाना चाहिए।

(10) निर्विवाद मालिकों द्वारा अधिग्रहण की चुनौती को अस्वीकार करना

विवादित क्षेत्र के आसपास की कुछ धार्मिक संपत्तियों की, इस स्तर पर एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी.

5 एस सी आर।

74

ए उन्हें अपनी चुनौती को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता के साथ है, यदि आवश्यक हो तो

बाद में उपयुक्त चरण, केंद्रीय द्वारा निरंतर प्रतिधारण के मामले में

निर्धारित किए गए सटीक क्षेत्र से अधिक उनकी संपत्ति की सरकार

विवाद के निर्णय पर आवश्यक।

(11) नतीजतन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1993 का विशेष संदर्भ संख्या 1 अनावश्यक और अनावश्यक है और इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।इस कारण से हम बहुत सम्मानपूर्वक इसका उत्तर देने से इनकार करते हैं और उसी को वापस करते हैं।(12) उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता और विशेष संदर्भ की स्थिरता से संबंधित प्रश्न इन शर्तों में तय किए जाते हैं।

ग

इन चटाई का निपटान, तदनुसार, ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है।

BHARUCHA, J. हमें पांडित्य पढ़ने का लाभ मिला है

हमारे विद्वान भाई, वर्मा, जे. का निर्णय हम उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार डी को लेने में असमर्थ हैं और हमें सम्मानपूर्वक असहमति जतानी चाहिए।

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण की वैधता और राष्ट्रपति की रखरखाव क्षमता से निपटना सुविधाजनक है।

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत 7 जनवरी, 1993 का संदर्भ

एक आम राय में भारत का।

ई.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसा कि अब निर्धारित किया गया है, भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1993 में जारी अयोध्या पर श्वेत पत्र से ली गई है।यही वह आधार था जिसके आधार पर उक्त अधिनियम को कानून पुस्तिका में लाने के लिए विधेयक तैयार किया गया था और संदर्भ बनाया गया था।

च

" अयोध्या लंबे समय से पवित्र तीर्थस्थल रहा है क्योंकि इसकी

महाकाव्य रामायण में श्री राम के जन्म स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है।आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जानी जाने वाली संरचना को 1528 ईस्वी में अयोध्या में मीर बाकी द्वारा एक मस्जिद के रूप में बनाया गया था।कुछ वर्गों द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह उस स्थान पर बनाया गया था जिसे श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है जहां पहले एक मंदिर खड़ा था।(श्वेत पत्र का पैरा 1)।द.

जी.

विवादित संरचना का उपयोग मुसलमानों द्वारा प्रार्थना करने के लिए किया जाता था जब तक कि

22/23 दिसंबर, 1949 की रात, जब हिंदू मूर्तियों को विवादित ढांचे के मुख्य हिस्से के केंद्रीय गुंबद के नीचे रखा गया था।अगली सुबह से इन मूर्तियों की पूजा बड़े पैमाने पर शुरू की गई।चूंकि इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी, इसलिए नागरिक प्रशासन ने आपराधिक प्रक्रिया एम. आई. फारूकी बनाम की धारा 145 के प्रावधानों के तहत एच परिसर को जब्त कर लिया।

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 75

कोड।यह घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला का प्रारंभिक बिंदु था जो अंततः संरचना के विध्वंस का कारण बना।(पैरा 2,13 और 2.15)।1950 में हिंदू सज्जनों द्वारा दो मुकदमे दायर किए गए थे; इनमें से एक मुकदमे में, जनवरी 1950 में, संबंधित सिविल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित किए जिसके तहत मूर्तियां अपने स्थान पर रहीं और पूजा जारी रही।अंतरिम आदेश था

अप्रैल 1955 में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।1 फरवरी, 1986 को संबंधित जिला न्यायाधीश ने बी विवादित संरचना पर ताले खोलने का आदेश दिया और भक्तों को पूजा करने की अनुमति दी।1959 में निर्मोही अखाड़े द्वारा विवादित ढांचे के स्वामित्व का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था।1961 में सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित ढांचे के स्वामित्व का दावा करते हुए एक और मुकदमा दायर किया गया था।1989 में देवकी नंदन अग्रवाल ने देवता के अगले मित्र के रूप में, यानी उक्त मूर्तियों ने विवादित ढांचे के संबंध में एक मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया।1989 में उपरोक्त मुकदमों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया।14 अगस्त, 1989 को उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।(श्वेत पत्र का परिशिष्ट I) "।दिसंबर 1949 में विवादित ढांचे में मूर्तियों को रखने के साथ विवाद ने एक नए चरण में प्रवेश किया।आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिसर को कुर्क किया गया था।इसके तुरंत बाद दीवानी मुकदमे दायर किए गए।इन दीवानी मुकदमों में अंतरिम आदेशों ने पक्षों को मूर्तियों को हटाने या उनकी पूजा में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।नतीजतन, दिसंबर 1,949 से दिसंबर 1992 तक इस संरचना का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया गया था।(पैरा 1.2) 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था।“ विध्वंस।यह सबसे निंदनीय कृत्य था।ई इस कृत्य के अपराधियों ने न केवल एक पूजा स्थल के खिलाफ बल्कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांतों पर भी हमला किया। उस दिन शाम 5:45 बजे मूर्तियों को बदल दिया गया था जहां विवादित संरचना खड़ी थी और शाम 7:30 बजे तक उनके लिए एक अस्थायी संरचना के निर्माण पर काम शुरू हो गया था।(पैरा 1.20) लगभग 9.10 बजे भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 एफ के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में लेते हुए एक घोषणा जारी की और इसकी विधानसभा को भंग कर दिया।(पैरा 1.21.)

विवादित स्थल पर विवादित ढांचे के प्रांगण में राम चबूतरा नामक एक संरचना खड़ी थी।इस संरचना को भी 6 दिसंबर, 1992 (श्वेत पत्र का परिशिष्ट 5) को ध्वस्त कर दिया गया था।परिणामस्वरूप, वहाँ हिंदुओं द्वारा की जाने वाली जी पूजा, जो ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों द्वारा बिना किसी आपत्ति के काफी समय से चल रही थी, समाप्त हो गई।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लियाःसरकार यह देखेगी कि एच

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. एक ध्वस्त संरचना का पुनर्निर्माण किया गया है। और नए राम मंदिर के संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे।(पैरा 1.22)

27 दिसंबर, 1992 को 7 दिसंबर, 1992 को "ध्वस्त ढांचे के पुनर्निर्माण और नए राम मंदिर के संबंध में उचित कदम उठाने" के लिए लिए गए उपरोक्त निर्णयों का "विस्तार से वर्णन" किया गया था।

सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों में विवादित सभी क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।उपयुक्त निकटवर्ती क्षेत्र का अधिग्रहण करने का भी निर्णय लिया गया है।विवादित संरचना वाले क्षेत्र को छोड़कर अधिग्रहित क्षेत्र को दो न्यासों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें क्रमशः राम मंदिर और मस्जिद के निर्माण के लिए स्थापित किया जाएगा और

एस.

क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए।

भारत सरकार ने राष्ट्रपति से इस सवाल पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है कि क्या उस स्थान पर कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जहां विवादित संरचना थी।डी सरकार ने उच्चतम न्यायालय की राय का पालन करने और न्यायालय की राय को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का भी फैसला किया है।

विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण के बावजूद, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यादेश की घोषणा से पहले की स्थिति तब तक बनी रहे जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपनी राय नहीं देता।इसके बाद न्यायालय की राय के आलोक में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा।(पैरा 8.11)।एक अध्यादेश, जिसे उक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, 7 जनवरी, 1993 को जारी किया गया था।अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ उसी दिन दिया गया था।हम बाद में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करेंगे।वर्तमान में, संदर्भ को पूरी तरह से निर्धारित करना आवश्यक हैः

च

" जहाँ एक विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या एक हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना अस्तित्व में थी

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में फैजाबाद सदर तहसील के परगना हवेली अवध में जिस क्षेत्र में यह संरचना खड़ी थी, उस क्षेत्र में (इस तरह की संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित), जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, का निर्माण।

जी.

प्रदेश।

2. और जहाँ उक्त क्षेत्र राजस्व भूखंड में स्थित है

एच.

नं.159 और कथित गाँव में 160, रामचंद्र में नहीं; एम. आई. फारूकी बनाम

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 77 3.और चूंकि उक्त विवाद ने देश में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव के रखरखाव को प्रभावित किया है;

4. और जहाँ उपरोक्त क्षेत्र अयोध्या अध्यादेश, 1993 में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर केंद्र सरकार में निहित है;

5. और उपरोक्त क्षेत्र को उक्त अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार को सौंपने के बावजूद केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के बाद और उक्त राय के संदर्भ में उक्त विवाद को निपटाने का प्रस्ताव किया है।और यहाँ पहले जो कहा गया है उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो प्रश्न उठाया गया है वह इस तरह का और सार्वजनिक है।

यह महत्वपूर्ण है कि उस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो;

डी.

7. अब, इसलिए, शक्तियों के प्रयोग में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त, मैं, भारत के राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा, एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रश्न को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विचार और राय के लिए संदर्भित करता हूं:

अर्थात्,

क्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद (ऐसी संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित) के निर्माण से पहले उस क्षेत्र में हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी, जिस पर एफ संरचना खड़ी थी?

यह देखा जाएगा कि संदर्भ के पांचवें पाठ में कहा गया है कि "केंद्र सरकार उक्त विवाद को प्राप्त करने के बाद निपटाने का प्रस्ताव करती है।

डब्ल्यू

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय और उक्त राय के संदर्भ में।केंद्र सरकार की ओर से पेश विद्वान सॉलिसिटर जनरल जी ने कहा कि इसका मतलब है कि केंद्र सरकार "उच्चतम न्यायालय की राय के आलोक में और उसके अनुरूप एक समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध है।हालाँकि, इस स्तर पर यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि

सटीक तरीका जिससे समाधान की दिशा में प्रगति की जा सके।अगर वह

मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया, कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हुआ, केंद्रीय

सरकार उच्चतम न्यायालय की राय को लागू करने के लिए कदम उठाएगी।

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] का समर्थन करें।5 एस सी आर।

78

अस्पष्टता से बचने के लिए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल को निर्देश लेने और इस संबंध में केंद्र सरकार की स्थिति को लिखित रूप में रखने के लिए कहा गया था:यदि संदर्भ द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह था कि विवादित संरचना के निर्माण से पहले विवादित स्थल पर कोई हिंदू मंदिर या धार्मिक संरचना नहीं थी, तो क्या विवादित संरचना का फिर से निर्माण किया जाएगा?14 सितंबर, 1994 को विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में निम्नलिखित बयान बी दिया:

" सरकार धर्मनिरपेक्षता और सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार की नीति के साथ खड़ी है।अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण के साथ-साथ राष्ट्रपति के संदर्भ का उद्देश्य है:

एस.

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना

भारत के लोगों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना।

सरकार राम मंदिर और मस्जिद के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उनका वास्तविक स्थान होगा

डी.

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी राय देने के बाद ही निर्धारित किया जाता है

राष्ट्रपति के संदर्भ में।

सरकार संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भित तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष को एक निर्णय के रूप में मानेगी जो अंतिम और बाध्यकारी है।

ई.

उच्चतम न्यायालय की राय के आलोक में और उसके अनुरूप, सरकार बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को हल करने का प्रयास करेगी।सरकार को विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय की राय का समुदायों के दृष्टिकोण पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा और वे अब तथ्यात्मक मुद्दे पर परस्पर विरोधी रुख नहीं अपनाएंगे

च

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया।

यदि उपरोक्त बातचीत से हुए समझौते के प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो सरकार उच्चतम न्यायालय की राय के आलोक में और उसके अनुरूप समाधान लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, इस संबंध में सरकार की कार्रवाई समान होगी।

जी.

दोनों समुदायों के सम्मान में दिया गया।यदि निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, अर्थात्, ध्वस्त संरचना के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर/संरचना मौजूद थी, तो सरकारी कार्रवाई हिंदू समुदाय की इच्छाओं के समर्थन में होगी।यदि उस पर

एच.

दूसरी ओर, प्रश्न का उत्तर नकारात्मक, एम. आई. फारूकी बनाम में दिया गया है।

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 79 अर्थात्, ए में ऐसा कोई हिंदू मंदिर/संरचना मौजूद नहीं थी।

प्रासंगिक समय, तब सरकारी कार्रवाई मुस्लिम समुदाय की इच्छाओं के समर्थन में होगी।

विद्वान महान्यायवादी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या केंद्र सरकार ने किसी भी समुदाय की इच्छाओं के समर्थन में कार्य करने का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि वर्तमान में ज्ञात है या संदर्भ बी का उत्तर दिए जाने के बाद और बातचीत विफल हो गई थी।विद्वान महान्यायवादी केंद्र सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने में असमर्थ थे।यह कहना उचित होगा कि उनके पास ऐसा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि स्पष्टीकरण मांगे जाने के अगले दिन बहस बंद हो गई थी।

विवाद की विषय-वस्तु को संदर्भित करना अब प्रासंगिक है।केंद्र सी में

विवाद की मांग विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान के पुनर्निर्माण के लिए की गई है।6 दिसंबर, 1992 तक, इस स्थल पर 1528 में मीर बाकी द्वारा बनाई गई संरचना का कब्जा था, जिन्होंने पहले मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर इसे बनाने का दावा किया था।" विहिप और उसके सहयोगी संगठनों ने अपनी मांग इस दावे पर आधारित की कि यह स्थल श्री राम का जन्म स्थान है और इस स्थल की याद में एक हिंदू मंदिर यहां तब तक खड़ा रहा जब तक कि इसे बाबर के आदेश पर नष्ट नहीं कर दिया गया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया।" बातचीत के दौरान विवाद का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से एक मुद्दा सामने आया कि क्या विवादित ढांचे के कब्जे वाले स्थान पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था और क्या इसे मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर के आदेश पर ध्वस्त किया गया था। यह कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा कहा गया था कि यदि ये दावे साबित हो जाते हैं, तो मुसलमान स्वेच्छा से विवादित मंदिर को मुस्लिम समुदाय को सौंप देंगे।

हिंदू "।[श्वेत पत्र के अनुच्छेद 2,1,2 और 3।]अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया हैः

च

" विवादित संरचना की जगह और एक परिसर की स्थापना के लिए उपयुक्त आस-पास की भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक माना गया, जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके, जिसमें एक राम मंदिर, एक मस्जिद, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, एक पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य उपयुक्त सुविधाएं स्थापित की जा सकें।जी.

इस अधिनियम को "अयोध्या में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण और उससे जुड़े मामलों" के लिए प्रावधान करने के लिए क़ानून पुस्तिका में रखा गया है।

या उससे आनुषंगिक "।अधिनियम में कहा गया है कि उपरोक्त संरचना से संबंधित "लंबे समय से विवाद" था जिसने देश में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव के रखरखाव को प्रभावित किया था।सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और एच 1 को बढ़ावा देना आवश्यक था।

भारत के लोगों के बीच एक सांप्रदायिक सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना।अयोध्या में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण करना आवश्यक था।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण।

यह अधिनियम धारा 1 (2) के कारण लागू हुआ माना जाता है।

7 जनवरी, 1993 को (जिस तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था)

बी पास)।धारा 2 (ए) "क्षेत्र" को भवनों, संरचनाओं या अन्य संपत्तियों सहित अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है।

इसमें शामिल हैं।धारा 2 (बी) "अधिकृत व्यक्ति" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "ए

व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या केंद्र द्वारा अधिकृत किसी भी न्यास के न्यासी

धारा 7 के तहत सरकार।"

धारा 3 के कारण, अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके बाद से,

एस.

क्षेत्र के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित हस्तांतरित किया जाता है और

केंद्र सरकार में निहित।

धारा 4 (1) में कहा गया है कि इस क्षेत्र में सभी परिसंपत्तियां शामिल मानी जाएंगी।

अधिकार, पट्टा, शक्तियाँ, अधिकार और विशेषाधिकार और सभी संपत्ति,

(घ) चल और अचल, और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, जो इसके प्रारंभ होने से ठीक पहले थे।

किसी व्यक्ति या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में यह अधिनियम

सरकार. और सभी रजिस्टर, नक्शे, योजनाएं, चित्र और अन्य

उससे संबंधित किसी भी प्रकृति के दस्तावेज।धारा 4 (2) के कारण

केंद्र सरकार में निहित सभी संपत्तियाँ

ई धारा 3, इस तरह के निहित बल द्वारा, किसी भी न्यास, दायित्व, बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार और अन्य सभी से मुक्त और मुक्त हो जाएगी।

उन्हें प्रभावित करने वाली बाधाएं और कोई संलग्नक, निषेधाज्ञा, डिक्री या

ऐसे उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का आदेश

किसी भी तरह से संपत्ति या पूरे के संबंध में किसी भी प्राप्तकर्ता की नियुक्ति

या ऐसी संपत्तियों के किसी भी हिस्से का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।धारा 4 (3)

एफ में कहा गया है कि केंद्र में निहित किसी भी संपत्ति से संबंधित अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही।

धारा 3 के तहत सरकार जो किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी

या अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अन्य प्राधिकरण "

कम करें "।

जी.

धारा 5 केंद्र सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देती है।

उस क्षेत्र का कब्जा सुरक्षित करने के लिए जो उसमें निहित है।

धारा 6 इस प्रकार हैः

" (1) धारा 3,4,5 में कुछ भी निहित होने के बावजूद

एच.

और 7 केंद्र सरकार, यदि यह संतुष्ट हो कि कोई एम. आई. फारूकी बनाम।

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 81

प्राधिकरण या अन्य निकाय, या किसी न्यास के न्यासी, या ए

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए इच्छुक है या इच्छुक है जो वह सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश देकर अधिरोपित करना उचित समझे कि अधिकार, स्वामित्व और ब्याज या उनमें से कोई भी क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में, केंद्र सरकार में निहित रहने के बजाय, उस प्राधिकरण या उस न्यास के न्यासियों के बी निकाय में निहित है।

$

अधिसूचना या ऐसी बाद की तारीख जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) जब उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय या न्यासी सी में उसके क्षेत्र या भाग के संबंध में कोई अधिकार, स्वामित्व और हित निहित होता है, तो ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में केंद्र सरकार के ऐसे अधिकार, ऐसे निहित होने की तारीख को और उससे, उस न्यास के प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों के अधिकार बन गए हैं।

1

डी.

(3) धारा 4,5,7 और 11 के प्रावधान, जहां तक हो सके, केंद्र सरकार के संबंध में लागू होंगे और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार को दिए गए संदर्भों को ऐसे प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा।

ई.

"संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन" शीर्षक वाले अध्याय के तहत धारा 7 एकमात्र धारा है, और यह इस प्रकार हैः

" (1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके बाद से, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी अनुबंध या लिखत या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, एफ के तहत केंद्र सरकार में निहित संपत्ति

धारा 3 का प्रबंधन केंद्र सरकार या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या इस संबंध में उस सरकार द्वारा अधिकृत किसी न्यास के न्यासियों द्वारा किया जाएगा।

(2) धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन में, केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उस क्षेत्र में मौजूद स्थिति जिस पर संरचना (ऐसी संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित), जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, गाँव कोट एच 82 में थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

अयोध्या में रामचंद्र, परगना हवेली अवध में,

क.

तहसील फैजाबाद सदर, फैजाबाद जिले में

उत्तर प्रदेश राज्य बना हुआ है "।

धारा 8 के कारण किसी भी भूमि, भवन, संरचना या

"क्षेत्र" में शामिल अन्य संपत्ति केंद्र द्वारा दी जाएगी।

बी सरकार नकद में भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर सभी राशि जो हस्तांतरित की गई है और निहित है।

धारा 3 के तहत केंद्र सरकार।निर्णय लेने के लिए

मालिक का दावा, केंद्र सरकार को एक दावा नियुक्त करना है

कमिश्नर।दावा 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है।

अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से।

एस.

धारा 9 यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम के प्रावधानों में

किसी में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभाव

तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि या इसके द्वारा प्रभावी कोई साधन

अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर,

न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण।धारा 10 गैर के लिए दंड का प्रावधान करती है

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन।धारा 11 अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। धारा 12

केंद्र सरकार को प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है

1

अधिनियम से।धारा 13 के कारण अध्यादेश निरस्त कर दिया जाता है।

अधिनियम का अब विश्लेषण किया जा सकता है।

ई.

" अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत "क्षेत्र" वह है जो अनुसूची में निर्दिष्ट है।पुनः, धारा 3 के तहत "क्षेत्र" वह है जो अनुसूची में निर्दिष्ट है।धारा 4 (1) के कारण "क्षेत्र" में ऐसी संपत्ति और सभी चल और अचल संपत्ति और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न

होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल हैं।"क्षेत्र", दूसरे शब्दों में, अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र में चल और अचल संपत्ति का पूरा बंडल और अन्य सभी शामिल हैं।

च

उसमें या उससे उत्पन्न होने वाले अधिकार और हित।धारा 4 (2) के कारण संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल केंद्र सरकार में निहित है और सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है।

धारा 7, (1) धारा 3 के तहत केंद्र सरकार जी में निहित संपत्ति की बात करती है।इसलिए, यह संपत्ति और अधिकारों के पूरे समूह की बात करता है।इनका प्रबंधन केंद्र सरकार या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या इस तरह से अधिकृत किसी भी न्यास के न्यासियों द्वारा किया जाना है।संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल के प्रबंधन में केंद्र सरकार या

प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उससे पहले की स्थिति

इस अधिनियम का उस क्षेत्र में प्रारंभ जिस पर संरचना (

आंतरिक और बाहरी प्रांगण-यार्ड का एच परिसर). खड़ा था... एम. आई. फारूकी बनाम।

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 83

बनाए रखा "।धारा 7 (2) में यह प्रावधान केवल ए क्षेत्र के उस हिस्से से संबंधित है जिस पर विवादित संरचना (विवादित स्थल) थी।अब, "अधिकृत व्यक्ति" के बारे में, धारा 7 (1) में कहा गया है कि संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल का प्रबंधन केंद्र सरकार या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी न्यास के न्यासियों द्वारा किया जाएगा।यह, जैसा कि धारा 7 (2) से पता चलता है, धारा 2 (बी) के तहत "अधिकृत बी व्यक्ति" है।वह धारा 6 (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या अन्य निकाय या न्यासी नहीं हो सकता है।दूसरे शब्दों में, संपत्ति और अधिकारों के पूरे समूह का प्रबंधन करने की शक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है।

या व्यक्तियों का निकाय या किसी न्यास के न्यासी भले ही उन्हें उन नियमों और शर्तों का पालन करने की आवश्यकता न हो जो केंद्रीय

सरकार धारा 6 (1) के तहत अधिरोपित करना उचित समझ सकती है।

ग

" केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन में

धारा 3 "(जिसे धारा 4 (1) के साथ पढ़ा जाता है, का अर्थ है संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल)" केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उस क्षेत्र में जिस पर संरचना (ऐसी संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगण के परिसर सहित) खड़ी थी, उस स्थिति को बनाए रखा जाए।धारा 7 (2) में यह प्रावधान "इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मौजूद स्थिति", यानी 6/7 जनवरी, 1993 की रात को आधी रात से पहले मौजूद स्थिति की बात करता है।इसलिए, इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल के प्रबंधन में, 6/7 जनवरी, 1993 की रात को आधी रात से पहले विवादित स्थल पर मौजूद स्थिति को बनाए रखा जाए।

दायित्व संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल के "प्रबंधन" के संबंध में डाला गया है।इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार या एफ

अधिकृत व्यक्ति को 7 जनवरी, 1993 से पहले विवादित स्थल पर की जा रही पूजा को जारी रखना आवश्यक है।इसके लिए प्रावधान किया गया है, भले ही धारा 4 (2) के कारण, इस संबंध में न्यायालय के आदेशों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता हो कि केंद्र सरकार द्वारा विवादित स्थल सहित संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल का क्या उपयोग किया जाएगा।इस संबंध में एक संकेत दिया गया है।

धारा 6 द्वारा।धारा 6 एक सक्षम प्रावधान है।धारा 6 (1) के कारण, संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल के केंद्र सरकार में निहित होने के बावजूद, "केंद्र सरकार, यदि यह संतुष्ट हो जाती है कि एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी. पर या उसके बाद स्थापित किसी भी न्यास का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय या न्यासी।

5 एस सी आर।

इस अधिनियम का प्रारंभ ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है या इच्छुक है जो वह सरकार प्रत्यक्ष रूप से अधिरोपित करने के लिए उचित समझे कि संपत्ति या अधिकारों के पूरे समूह या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज या उनमें से कोई भी, केंद्र सरकार में निहित रहने के बजाय, उस न्यास के उस प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों में निहित होगा।इसके बाद, धारा 6 (2) के कारण, संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल या उसके ऐसे हिस्से में केंद्र सरकार के अधिकार, जो धारा 6 (1) के तहत निहित किए गए हैं, ऐसे निहित होने की तारीख को और उससे उस न्यास के प्राधिकरण या निकाय या न्यासियों के अधिकार बन गए हैं।दूसरे शब्दों में, जब संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में निहित किया जाता है, तो संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल में केंद्र सरकार के सभी अधिकार

क.

एस.

या उसका ऐसा भाग जो निहित किया गया है, उस प्राधिकरण या निकाय या न्यास को हस्तांतरित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह निहित है।

क.

धारा 6 के प्रावधान संपत्ति के पूरे बंडल पर लागू होते हैं और

अधिकार; अर्थात, वे विवादित स्थल पर भी लागू होते हैं।विवादित स्थल

किसी प्राधिकरण या निकाय या न्यास में भी निहित किया जा सकता है जो उन नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है जिन्हें केंद्र सरकार लागू करना उचित समझती है।वे नियम और शर्तें अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं हैं, और न ही उस ओर से कोई संकेत उपलब्ध है।एकमात्र प्रतिबंध लगाया गया है

आई.

ऐसे प्राधिकारी या निकाय या न्यास पर, उन नियमों और शर्तों के अलावा, जिन्हें केंद्र सरकार लागू करना उचित समझती है, वे धारा 7 में दिए गए हैं।यह धारा 6 (3) में बताया गया है।धारा 4,5 ई और 11 के प्रावधान जो धारा 6 (3) में भी उल्लिखित हैं, वे ऐसे प्रावधान हैं जो प्राधिकरण या निकाय या न्यास को सशक्त और संरक्षित करते हैं।

धारा 7 संपत्ति और अधिकारों के पूरे समूह के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित है।धारा 7 (1) में कहा गया है कि इसका प्रबंधन किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी न्यास के व्यक्तियों या न्यासियों के निकाय द्वारा; दूसरे शब्दों में, प्राधिकृत व्यक्ति।धारा 7 (2) केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति को संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल का प्रबंधन करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है कि अधिनियम के प्रारंभ से पहले जिस क्षेत्र में विवादित संरचना खड़ी थी, वहां "मौजूदा स्थिति" को बनाए रखा जाए।द सेंट्रल

इसलिए, सरकार या अधिकृत व्यक्ति विवादित स्थल के संबंध में जी "स्थिति" बनाए रखने के लिए बाध्य है क्योंकि यह 6/7 जनवरी, 1993 की रात को आधी रात से पहले था, और संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल के "प्रबंधन" में ऐसा करना आवश्यक है।इसका तात्पर्य यह है कि न केवल ध्वस्त संरचना के मलबे को वैसे ही बनाए रखा जाना चाहिए जैसे वह खड़ा है, बल्कि यह भी कि विध्वंस के बाद विवादित स्थल पर रखी गई मूर्तियों को वहीं रखा जाना चाहिए जहां वे हैं और एच के सामने की गई पूजा जारी रखी जानी चाहिए।

चूँकि अधिनियम में संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल का उपयोग करने का इरादा नहीं है और चूंकि धारा 7 के प्रावधान उस प्राधिकरण या निकाय या ट्रस्ट पर भी लागू होते हैं जिसमें केंद्र सरकार धारा 6 के प्रावधानों के तहत संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल या उसके किसी भी हिस्से को निहित कर सकती है, इसलिए धारा 6 के प्रावधानों को पढ़ना संभव है।

धारा 7 के प्रावधान स्थायी प्रकृति के हैं।इसलिए स्वयं पढ़े गए अधिनियम में सुझाव दिया गया है कि मूर्तियां विवादित स्थल बी पर अनिश्चित काल के लिए रहेंगी और उनके सामने पूजा की जाती रहेगी।

धारा 8 किसी भी भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति के मालिक को उसके बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देती है।उस ओर से दावों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दावा सी आयुक्त द्वारा विचार किया जाना है।अपने दावे को स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए, मालिक को अधिग्रहित की गई संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करना होगा।इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमे जो धारा 4 (3) के कारण समाप्त हो जाते हैं, विवादित स्थल के स्वामित्व से संबंधित हैं।दूसरे शब्दों में, विवादित स्थल के स्वामित्व के निर्णय के लिए मंच को अदालतों से दावा आयुक्त के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है।उपरोक्त अपने आप में अधिनियम का एक विश्लेषण है।इसे इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन के संदर्भ में भी पढ़ना आवश्यक है।

संदर्भ.उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि एक योजनाबद्ध स्थापना के लिए संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल का अधिग्रहण आवश्यक है।पूर्ण आवास "एक राम मंदिर, एक मस्जिद, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, एक पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य उपयुक्त सुविधाएं"।प्राधिकरण या अन्य निकाय या किसी भी न्यास के न्यासी जो ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के इच्छुक हैं जिन्हें केंद्र सरकार लागू करना उचित समझती है, एफ के तहत

धारा 6 के प्रावधान, संपत्ति के पूरे बंडल का एक हिस्सा और राम मंदिर और संगत सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के अधिकार के साथ निहित होंगे।इस तरह से इच्छुक किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या न्यास को संपत्ति के पूरे बंडल के दूसरे हिस्से के साथ निहित किया जाएगा और एक मस्जिद और संगत सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव का अधिकार दिया जाएगा। इसलिए पढ़ें, धारा 7 में निहित संपत्ति और अधिकारों के पूरे बंडल के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित प्रावधान अंतरिम प्रावधान हैं, जो धारा 6 के तहत निहित होने तक काम करते हैं।धारा 6 के प्रावधानों, उद्देश्यों और कारणों के विवरण और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, विवादित स्थल और आसपास की भूमि का अधिग्रहण एच. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] प्रस्ताव के विवाद के समाधान तक इसे बनाए रखना है।

5 एस सी आर।

86

विवादित स्थल के संबंध में ए।विवाद का समाधान संदर्भ में बताए गए तरीके से होना है।इस तरह के समाधान पर विवादित स्थल को मस्जिद या राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और आसपास के क्षेत्र में अन्य धर्म के पूजा स्थल और मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के पूजा स्थलों के लिए सहायक सुविधाएं होंगी।धारा 3 के प्रावधान बी की वैधता, जिसके कारण संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाता है और निहित होता है, और इसलिए, अधिनियम की ही।इसका पालन करने वाले प्रावधानों की वैधता पर निर्भर करता है, विशेष रूप से, धारा 4।

धारा 4 (1) में कहा गया है कि इस क्षेत्र में सभी परिसंपत्तियां शामिल मानी जाएंगी।

ग. अधिकार, पट्टाधारिता, शक्तियां, प्राधिकरण और विशेषाधिकार और सभी चल और अचल संपत्ति और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले किसी व्यक्ति या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में थे।

सरकार।... ..... और सभी रजिस्टर, नक्शे, योजनाएं, चित्र और उससे संबंधित किसी भी प्रकृति के अन्य दस्तावेज।धारा 4 (2) के कारण

डी.

धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित सभी संपत्तियां, इस तरह के निहित होने के बल पर, मुक्त हो जाएंगी और उनसे मुक्त हो जाएंगी।किसी भी न्यास, दायित्व, बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले अन्य सभी बोझों और किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी कुर्की, निषेधाज्ञा, डिक्री या आदेश का किसी भी तरह से ऐसी ई संपत्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित करने या ऐसी संपत्तियों के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में किसी भी रिसीवर की नियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा।धारा 4 (3) में कहा गया है कि केंद्र में निहित किसी भी संपत्ति से संबंधित अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही।

धारा 3 के तहत सरकार जो अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित थी "

च

कम करें "।धारा 8 के कारण किसी भी भूमि, भवन, संरचना या

"क्षेत्र" में शामिल अन्य संपत्ति केंद्र द्वारा दी जाएगी।

सरकार नकद में भूमि, भवन, संरचना या अन्य संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि जो धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को हस्तांतरित की गई है और निहित है।इस तरह के दावों का निर्णय जी ए क्लेम कमिश्नर द्वारा किया जाना है, जो अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का हकदार है।जैसा कि श्वेत पत्र से पता चलता है, ध्वस्त संरचना को 1528 में एक मस्जिद के रूप में बनाया गया था।इसका उपयोग 1528 से 22/23 दिसंबर, 1949 की रात तक एक मस्जिद के रूप में किया गया था, जब मूर्तियों को उसमें रखा गया था।अदालतों के आदेशों के कारण मूर्तियाँ विवादित ढांचे में बनी हुई हैं।एच ने 1986 में पारित अदालत के आदेशों के तहत मूर्तियों की सार्वजनिक पूजा एम. आई. फारूकी बनाम।

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 87

अनुमति दी गई।यह स्थिति 6 दिसंबर, 1992 तक जारी रही।

जब विवादित संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था।अधिनियम की धारा 4 का प्रभाव यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो

विवादित ढांचे में रखी गई मस्जिद को प्रशासित किया, और मुस्लिम समुदाय 1528 से 1949 तक विवादित स्थल के प्रतिकूल कब्जे का अनुरोध करने का अपना अधिकार खो देता है, यदि अद्यतित नहीं है।यह मानते हुए कि बी की मूर्तियां केवल अदालतों के आदेशों के तहत विवादित संरचना में बनी रहीं।कानून के आधार पर विवादित स्थल के स्वामित्व के न्यायिक निर्धारण के बजाय, विवादित स्थल और आसपास की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और एक मस्जिद और उस पर एक मंदिर के साथ एक परिसर की योजना बनाई गई है।विवादित स्थल का क्या होगा, यह संदर्भ और उस पर आधारित वार्ताओं में पूछे गए प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है।संदर्भ में सी से पूछा गया प्रश्न है:विवादित स्थल पर विवादित संरचना के निर्माण से पहले हिंदू मंदिर या कोई अन्य हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी या नहीं।विद्वान महान्यायवादी ने निष्पक्ष रूप से कहा कि न्यायालय को इस प्रश्न को यह पूछते हुए पढ़ना चाहिए कि क्या विवादित स्थल पर विवादित स्थल के निर्माण से ठीक पहले कोई हिंदू मंदिर या अन्य हिंदू धार्मिक संरचना थी।विवाद, यह याद रखा जाएगा, डी यह था कि विवादित स्थल पर एक राम मंदिर खड़ा था और विवादित संरचना के लिए जगह बनाने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया था; हालाँकि, सवाल यह है:क्या उस पर "कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना" थी?

विवादित स्थल।दूसरा, इस मुख्य तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि विवादित ढांचे के लिए जगह बनाने के लिए मंदिर, यदि कोई हो, को ध्वस्त किया गया था या नहीं।विवादित स्थल के स्वामित्व के बारे में विवाद मुआवजे के पुरस्कार के उद्देश्य से विचार के लिए बने रहते हैं।इस उद्देश्य के लिए किसी न्यायालय के समक्ष नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दावा आयुक्त के समक्ष अधिकार स्थापित करना होगा, जो अपनी प्रक्रिया तैयार करने का हकदार है।सिविल न्यायालय में अपील या निर्देश का कोई अधिकार इस परिणाम के लिए प्रदान नहीं किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक उपाय को छोड़कर दावा आयुक्त का निर्णय अंतिम F होगा।उपरोक्त कारणों से, अधिनियम की धारा 4 और 8 के प्रावधानों को मनमाना और अनुचित माना जाना चाहिए।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान, जैसे -

वे सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय को वाद करने और उपरोक्त प्रतिकूल अधिकार स्थापित करने के अधिकार से वंचित करते हैं और विवादित स्थल के संबंध में उनकी शिकायत के निवारण को संदर्भ द्वारा उठाए गए सीमित प्रश्न के उत्तर और उसके बाद की बातचीत तक सीमित करते हैं और अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपत्ति और अधिकारों का पूरा बंडल केंद्र सरकार को सौंपते हैं, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जो मूल एच का एक हिस्सा है।

जी 88

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

Agg.gm

संविधान की एक संरचना, जिसे एक धार्मिक समुदाय के पक्ष में और दूसरे के खिलाफ झुकाया जा रहा है।

कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियादी विशेषताओं का एक हिस्सा है

केशवानंद भारती बनाम.केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी 225।एस. आर. मामले में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की।

बी बोम्मई बनामभारत संघ, [1994] 3 एस. सी. सी. 1.न्यायमूर्ति सावंत ने संविधान की प्रस्तावना और उसमें शामिल विभिन्न अनुच्छेदों का विश्लेषण किया और कहा कि ये प्रावधान, निहितार्थ से, एक धर्मशासित राज्य की स्थापना को प्रतिबंधित करते हैं और राज्य को किसी विशेष धर्म के साथ अपनी पहचान बनाने या उसका पक्ष लेने से रोकते हैं।राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया गया था।के. रामास्वामी, जे. ने गाँधीजी द्वारा लिखे गए शब्दों को उद्धृत किया जो अब उतने ही उपयुक्त हैं जितने वे तब थे जब उन्होंने उन्हें लिखा थाःमुसलमानों का अल्लाह ईसाइयों का ईश्वर और हिंदुओं का ईश्वर है।जे. बी. पी. जीवन रेड्डी ने कहाः

" जहां तक राज्य का संबंध है, इस देश के नागरिक अपने पसंद के धर्म, आस्था या विश्वास को मानने, पालन करने और प्रचारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी राज्य के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति का धर्म, आस्था या विश्वास महत्वहीन है।इसके लिए, सभी समान हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करने का अधिकार है।यह समान व्यवहार कैसे संभव है, यदि राज्य को किसी विशेष धर्म, नस्ल या जाति को पसंद करना या बढ़ावा देना है, जिसका अर्थ है अन्य सभी धर्मों, नस्लों और जातियों के साथ कम अनुकूल व्यवहार।सामाजिक न्याय, आस्था, आस्था या पूजा की स्वतंत्रता और स्थिति और अवसर की समानता के संवैधानिक वादे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं जब तक कि राज्य किसी व्यक्ति के धर्म, आस्था या विश्वास को अपने विचार से पूरी तरह से अलग नहीं करता है।

डी.

ई.

उसके साथ व्यवहार करना, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य और उसके अधिकार?इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता के एक निष्क्रिय दृष्टिकोण से अधिक है।यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की एक सकारात्मक अवधारणा है।इस मनोवृत्ति को कुछ लोग धर्म के प्रति तटस्थता या परोपकारी के रूप में वर्णित करते हैं।

च

तटस्थता।यह पश्चिमी द्वारा विकसित एक अवधारणा हो सकती है।

उदार विचार या यह, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, हर समय भारतीय लोगों के साथ एक स्थायी विश्वास हो सकता है।वह भौतिक नहीं है।सार यह है कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य है और संविधान की एक बुनियादी विशेषता है जैसा कि संविधान में पुष्टि की गई है।

जी.

केशवानंद भारती बनाम.केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी. 225 और इंदिरा एन. गांधी बनाम।राज नारायण, [1975] पूरक।एससीसी 1:[1976] 2 एससीआर 347।इसके साथ असंगत कोई भी कदम

संवैधानिक नीति, सीधे शब्दों में, असंवैधानिक है।

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 89

राज्य का कोई धर्म नहीं है।राज्य ए को सम्मानित करने और धारण करने के लिए बाध्य है।

सभी धर्मों के बीच भी तराजू।यह एक धर्म के उद्देश्य को दूसरे के नुकसान के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान धारा 3,4 और 8 हैं।दूसरे ने

अधिनियम के प्रावधान केवल धारा 3,4 और 8 के सहायक और आनुषंगिक हैं।चूँकि धारा 3,4 और 8 के मुख्य प्रावधान असंवैधानिक हैं, इसलिए बी अधिनियम स्वयं खड़ा नहीं हो सकता है।

धारा 7 के प्रावधानों को इस निष्कर्ष के समर्थन में संदर्भित किया गया है कि अधिनियम एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म के पक्ष में है।

धारा 7 (1) के प्रावधान केंद्र सरकार को "किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या किसी भी न्यास के न्यासियों" को अधिग्रहित क्षेत्र का प्रबंधन सौंपने का अधिकार देते हैं।धारा 7 (2) में कहा गया है कि "धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के प्रबंधन में केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि -

जिस क्षेत्र में "विवादित संरचना" बनी हुई है, उस क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मौजूद स्थिति बनी हुई है।यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि "संपत्ति के प्रबंधन" के दौरान "स्थिति" को बनाए रखना आवश्यक है।"इस अधिनियम के प्रारंभ" से पहले विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था, मूर्तियों को विवादित स्थल पर रखा गया था और उनकी पूजा शुरू हो गई थी। इसलिए, धारा 7 (2) में यह अपेक्षा की गई है कि पूजा तब तक जारी रहे जब तक प्रबंधन जारी रहे।इस तरह के प्रबंधन को कब तक जारी रखना है और किस घटना पर यह समाप्त होगा, इसका संकेत नहीं है।इस प्रकार, धारा 7 (2) विवादित स्थल पर पूजा के प्रदर्शन को कायम रखती है।इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि उस पर संरचना को "सबसे निंदनीय कार्य" में नष्ट कर दिया गया था।इस कृत्य के अपराधियों ने न केवल पूजा स्थल के खिलाफ बल्कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और कानून के नियम एफ के सिद्धांतों पर भी हमला किया।... ..... ” (श्वेत पत्र, पैरा 1.35) इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि

जिस स्थान पर पूजा की जानी है, उसके संबंध में विवाद है; कि, जैसा कि श्वेत पत्र में कहा गया है, 22/23 दिसंबर, 1949 की रात तक, जब मूर्तियों को विवादित ढांचे में रखा गया था, विवादित ढांचे का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा था; और यह कि मुस्लिम समुदाय के पास है

उस पर नमाज़ पढ़ने का दावा।पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के लिए कार्यवाही के दौरान संदर्भ दिया गया था।यह किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने और इसके लिए प्रावधान करने के लिए एक क़ानून है

15 अगस्त, 1947 को किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना।यह आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी. के किसी भी स्थान का धर्मांतरण नहीं करेगा।

5 एस सी आर।

90

किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग की पूजा एक ही धार्मिक संप्रदाय के किसी अलग वर्ग या किसी अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में की जाती है।यह घोषणा करता है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो उस तारीख को मौजूद था।यह निर्दिष्ट किया गया है कि कानून में निहित कुछ भी उस पूजा स्थल पर लागू नहीं होगा जो अयोध्या में विवादित संरचना बी थी और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही पर लागू होगी।पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था कि 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में जो हुआ था, वह फिर कभी नहीं हो सकता।प्रस्तुतिकरण इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि भारतीय दंड संहिता में धर्म से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान हैं।धारा 295 में कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी पूजा स्थल या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र मानी गई किसी भी वस्तु को किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से या इस ज्ञान के साथ नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या अपवित्र करता है कि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा इस तरह के विनाश, क्षति या अपवित्रता को अपने धर्म का अपमान मानने की संभावना है, उसे दंडित किया जाएगा।धारा 295 एक ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भारत के नागरिकों के किसी भी डी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से, शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा अपमान करता है या उस वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने का प्रयास करता है।जिन्होंने विवादित को ध्वस्त कर दिया

6 दिसंबर, 1992 को जमीन पर बनी संरचना इन प्रावधानों से बाधित नहीं हुई थी।इसी तरह की सोच रखने वाले अन्य लोगों के पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों से विचलित होने की संभावना कम है।

ई.

भारत के संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक

धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।संविधान के भाग III में अनुच्छेद 15, जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, राज्य को भेदभाव करने से रोकता है

धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ।धर्मनिरपेक्षता को संविधान में गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है।इसका उद्देश्य सभी धर्मों को संरक्षित और संरक्षित करना है, एफ सभी धार्मिक समुदायों को एक समान स्थान पर रखना है।इसलिए, जब अधिकांश भारतीय नागरिकों के धर्म के अनुयायी किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल पर दावा करते हैं और हमला करते हैं और संख्या के आधार पर ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जो सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए अनुकूल होती हैं, तो यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह उस पूजा स्थल की रक्षा करे और उसे विकृत करे।

सार्वजनिक व्यवस्था, इस उद्देश्य के लिए कानून और व्यवस्था जी के ऐसे साधनों और ताकतों का उपयोग करना जो आवश्यक हैं। संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पूजा स्थल का अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं है।ऐसी परिस्थितियों में पूजा स्थल के अधिग्रहण को माफ करना संविधान से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को समाप्त करना है।

हमें एक चेतावनी जोड़नी होगी।यदि कानून की अदालत में पूजा स्थल का अधिकार एच विवाद में है और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में है, तो एम. आई. फारूकी बनाम के लिए दो पाठ्यक्रम खुले हैं।

यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 91

केंद्र सरकार।यह संबंधित न्यायालय में पूजा स्थल का एक नियुक्त प्राप्तकर्ता होने के लिए आवेदन कर सकता है, ताकि इसे अपने अधिकार के अंतिम निर्णय तक सुरक्षित रखा जा सके, या यह ऐसा कानून बना सकता है जो इसे संबंधित न्यायालय द्वारा अपने अधिकार के निर्णय तक पूजा स्थल का वैधानिक प्राप्तकर्ता बनाता है।किसी भी स्थिति में, केंद्र सरकार उस पार्टी को पूजा स्थल सौंपने के लिए खुद को बाध्य करेगी जिसके पक्ष में इसका शीर्षक पाया जाता है।

विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत कियाः

जब परस्पर विरोधी दावे किए जाते हैं और गहरी भावनाएँ शामिल होती हैं, तो एक समाधान एक या दूसरे को चोट पहुँचा सकता है।

भावनाएँ, लेकिन उस कारण से इसे सी आंशिक या तटस्थता की कमी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

जब समुदायों के बीच सौहार्द और सद्भाव को खतरा होता है, तो मदद करना राज्य के धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यों में से एक है

एक समाधान की दिशा में पक्षकार जो सरकार को लगता है कि समय के साथ स्वीकार किया जाएगा, यदि तुरंत नहीं, डी और जिसका प्रभाव संघर्ष और संघर्ष की हिंसा को कम करने और कम करने का होगा।अधिनियम और

संदर्भ समुदायों के बीच सौहार्द और सद्भाव बहाल करने की दिशा में एक प्रयास है।उनका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष है।

ई.

हम ऊपर बताए गए कारणों से सहमत नहीं हो सकते हैं।

अब अनुच्छेद 25 (1) का संक्षिप्त संदर्भ दिया जा सकता है।इसमें लिखा हैः "25. विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का पालन और प्रचार (1) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है।

जी.

अनुच्छेद 25 (1) व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।आयुक्त को देखें,

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम।श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, [1954] एस. सी. आर. 1005 1021 में।धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है।धर्मनिरपेक्षता निरपेक्ष है; राज्य धर्मों के साथ इस आधार पर अलग व्यवहार नहीं कर सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अनुच्छेद 15 और 16 के प्रावधानों पर प्रकाश डालता है।अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करने के लिए बाध्य करता है।दायित्व किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है।अनुच्छेद 16 (1) घोषणा करता है कि किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

राज्य के अधीन।अनुच्छेद 16 (2) आवश्यकता को नकारात्मक रूप से रखता हैःकोई नागरिक बी शाल नहीं!धर्म के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अयोग्य होगा या उसके साथ भेदभाव किया जाएगा।एक बार फिर,

इस संबंध में दायित्व किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है।धर्म के मामलों में राज्य के लिए आवश्यक "व्यावहारिक" दृष्टिकोण को अनुच्छेद 27 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विशेष रूप से विनियोजित की जाती है।अनुच्छेद 29 (2) को इसकी पूर्ण शर्तों के लिए भी नोट किया जा सकता है; किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है या धर्म के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है।

यह हमें संदर्भ पर लाता है।अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है,

डी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विवादित स्थल के स्वामित्व के बारे में मुकदमे और जिस उद्देश्य के लिए संदर्भ दिया गया था, कहा जा सकता है कि

अनावश्यक हो जाते हैं।दूसरी ओर, यह कहा जा सकता है कि मुकदमों का पुनरुद्धार केंद्र सरकार को अयोध्या में विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान लाने के लिए बातचीत करने से नहीं रोकता है और ऐसी बातचीत संदर्भ द्वारा पूछे गए प्रश्न के दिए गए उत्तर पर निर्भर करती है।हम करेंगे,

ई.

इसलिए, संदर्भ से निपटें, और इस आधार पर आगे बढ़ें कि यह अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के तहत बनाए रखने योग्य है।

1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

च

" यह बिल्कुल सच है कि अनुच्छेद 143 (1) के तहत भले ही प्रश्नों को इस न्यायालय को उसकी सलाहकार राय के लिए भेजा जाता है, यह न्यायालय हर मामले में ऐसी सलाहकार राय देने के लिए बाध्य नहीं है।अनुच्छेद 143 (1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्न इस न्यायालय द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद, वह ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है।अनुच्छेद 143 (2) द्वारा निर्धारित प्रावधान में "होगा" शब्द के उपयोग के विपरीत "हो सकता है" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सामने लाता है कि किसी दिए गए मामले में, यह न्यायालय सम्मानपूर्वक अपनी सलाहकार राय व्यक्त करने से इनकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उसे प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए।

ना.

जी.

एच. एम. आई. फारूकी बनामयू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 93 ने अन्य प्रासंगिक तथ्यों ए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अग्रेषित किया।

विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, [1979] 3 एस. सी. आर. 476 के संदर्भ में इस न्यायालय ने कहाः

" अनुच्छेद 143 (1) को व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है जो बी का प्रावधान करता है कि कानून या तथ्य का कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए भेजा जा सकता है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या

उत्पन्न होने की संभावना है और यदि प्रश्न ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है।यद्यपि अनुच्छेद 143 (1) के तहत किए गए छह संदर्भों में से किसी में भी तथ्य के प्रश्न सी को न्यायालय में संदर्भित नहीं किया गया है, वह अनुच्छेद राष्ट्रपति को तथ्य के प्रश्नों पर भी संदर्भ देने का अधिकार देता है बशर्ते कि लेख की अन्य शर्तें पूरी हों।यह नहीं है।

यह आवश्यक है कि जिस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगी गई है, वह वास्तव में उत्पन्न हुआ होगा।राष्ट्रपति के लिए यह सक्षम है कि वह अनुच्छेद 143 (1) के तहत एक पूर्ववर्ती चरण में एक संदर्भ दे, अर्थात्, उस स्तर पर जब राष्ट्रपति का समाधान हो कि प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है और क्या यह ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को तय करना है।संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का सादा कर्तव्य और कार्य उस प्रश्न पर विचार करना है जिस पर राष्ट्रपति ने संदर्भ दिया है और राष्ट्रपति को अपनी राय रिपोर्ट करना है, बशर्ते कि प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो।

यह निर्णय लेने के लिए न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है।यदि, जिस तरीके से प्रश्न तैयार किया गया है या किसी अन्य उचित कारण से न्यायालय

यह समझते हुए कि इस प्रश्न का उत्तर देना उचित या संभव नहीं है, वह इसका उत्तर देने में बाधाओं को इंगित करके संदर्भ को वापस करने का हकदार होगा।इस न्यायालय का जी को किसी निर्देश का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार केवल अनुच्छेद 143 के खंड (1) और (2) में उपयोग किए गए विभिन्न वाक्यांशों से नहीं निकलता है, इस अर्थ में कि खंड (1) में यह प्रावधान है कि न्यायालय राष्ट्रपति को अपने निर्दिष्ट प्रश्न पर अपनी राय दे सकता है, जबकि खंड (2) में प्रावधान है कि न्यायालय एच 94 पर अपनी राय राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] प्रस्तावः5 एस सी आर।

सवाल करते हैं।खंड (2) के अधीन उत्पन्न होने वाले मामलों में भी, यद्यपि

क.

यह प्रश्न कि इस संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, न्यायालय बिना उत्तर दिए संदर्भ को वापस करने में उचित हो सकता है यदि वह वैध कारण से पाता है कि प्रश्न जवाब देने में असमर्थ है।

जवाब दिया।इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ हम करेंगे

ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार करें।

}

इसलिए, यह न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने का हकदार है, यदि वह मानता है कि ऐसा करना उचित या संभव नहीं है।

तो, लेकिन इसे अपने कारणों का संकेत देना चाहिए।

हमारे विचार में, संदर्भ का उत्तर निम्नलिखित कारणों से नहीं दिया जाना चाहिए।.

अधिनियम और संदर्भ, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक धार्मिक समुदाय का पक्ष लेते हैं और दूसरे को नापसंद करते हैं; संदर्भ का उद्देश्य हैः

इसलिए, यह धर्मनिरपेक्षता का विरोध करता है और असंवैधानिक है।इसके अलावा,

संदर्भ एक संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

डी.

दूसरा, संदर्भ के पांचवें पाठ में कहा गया है कि "केंद्र सरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के बाद और उक्त राय के संदर्भ में उक्त विवाद को निपटाने का प्रस्ताव करती है।"(जोर दिया गया।) यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार न्यायालय की राय के संदर्भ में विवाद को निपटाने का प्रस्ताव नहीं करती है, यह बातचीत के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में न्यायालय की राय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है।इस तरह की बातचीत के परिणामस्वरूप विवाद के समाधान को "उक्त राय के संदर्भ में" विवाद का समाधान नहीं कहा जा सकता है।निर्देश प्राप्त करने और न्यायालय को यह बताने के लिए कहा गया कि यदि संदर्भ द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है तो मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने ऊपर उद्धृत बयान दिया।इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि इस परिस्थिति में भी कि यह न्यायालय यह मानता है कि विवादित स्थल पर विवादित संरचना के निर्माण से पहले कोई हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद नहीं थी, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

" ई ई

तीसरा, प्रश्न के संबंध में साक्ष्य का पहलू है।

संदर्भित।यह हमारा सुझाव नहीं है कि कानून की अदालत जी इस तरह के प्रश्न का निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है।यह तब किया जा सकता है जब पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के विशेषज्ञ साक्ष्य का नेतृत्व किया जाए, और प्रतिपरीक्षा में परीक्षण किया जाए। दोनों स्टैंड के प्रमुख नायक संदर्भ में दिखाई नहीं दे रहे हैं; वे न तो साक्ष्य का नेतृत्व करेंगे और न ही प्रतिपरीक्षा करेंगे।विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई सबूत पेश नहीं करेगी, लेकिन वह अदालत के समक्ष वह सामग्री रखेगी जो उसने पिछली बातचीत के दौरान दोनों पक्षों एच से एकत्र की थी।न्यायालय के लिए अपर्याप्त सुसज्जित होने के कारण

आई. एम. आई. फारूकी बनाम।यू. ओ. आई. [भरुचा, जे.] 95

ऐसी सामग्री की जांच और मूल्यांकन करने के लिए उसे ए क्षेत्र में विशेषज्ञों को नियुक्त करना होगा और उनका मूल्यांकन बिना किसी चुनौती के किया जाएगा।इस तरह के मूल्यांकन पर न्यायिक राय देने की अंतर्निहित अयोग्यता के अलावा,

राय एक या दोनों पक्षों की आलोचना के लिए उत्तरदायी होगी कि यह उन्हें या उनके साक्ष्य को सुने बिना प्रस्तुत किया गया था। इसका आम तौर पर कोई महत्व नहीं होता क्योंकि उन्होंने दूर रहने का विकल्प चुना था, लेकिन इस राय का उद्देश्य बातचीत के लिए एक सार्वजनिक वातावरण बनाना है और आलोचना को जनता के कान लगेंगे, इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहना कि यह इस न्यायालय की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा।

अयोध्या एक तूफान है जो गुजर जाएगा।इसके कारण उच्चतम न्यायालय की गरिमा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता है।

एस.

हमने जो भी अवलोकन किया है, वह संदर्भित करने वाले प्राधिकारी का प्रतिबिंब नहीं है।हम भारत के राष्ट्रपति के पद और उसके वर्तमान पदधारी के लिए सर्वोच्च सम्मान करते हैं; उनकी धर्मनिरपेक्ष साख सर्वविदित है।

अधिनियम और संदर्भ पर हमने जो निर्माण किया है, उसे ध्यान में रखते हुए, क्रमशः उनकी वैधता और रखरखाव के लिए डी अन्य चुनौतियों पर चर्चा करना न तो आवश्यक है और न ही उचित है।हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि हमें यह तर्क मिला कि अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था था

?

विधान और इसलिए, संसद की क्षमता से परे

प्रशंसनीय है।

हम विद्वान महान्यायवादी के उस आश्वासन के लिए ऋणी हैं जो उन्होंने न्यायालय को दिया है।हम उन सलाहकारों के ऋणी हैं जिनके पास

अगर हम श्री आर. के. गर्ग को अलग करते हैं, तो यह उनके असामयिक निधन के कारण है।

इससे पहले कि हम अंतिम आदेश पारित करें, सामान्य प्रकृति के कुछ अवलोकन क्रम में प्रतीत होते हैं।हिंदू धर्म एक सहिष्णु आस्था है।यह वह सहिष्णुता है जिसने इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को इस भूमि पर आश्रय और समर्थन पाने में सक्षम बनाया है।हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उदारवादी हिंदू को दूसरे के पूजा स्थल को तोड़कर उसके स्थान पर मंदिर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।यह हमारी तीव्र आशा है कि उस उदार राय को सामान्य अभिव्यक्ति मिलेगी और सांप्रदायिक भाईचारे से अयोध्या में विवाद में एक सौहार्दपूर्ण जी आएगा।

अदालत द्वारा इसे हल करने से बहुत पहले समाधान।

गांधी जी को फिर से उद्धृत करने के लिए, "भारत एक राष्ट्र नहीं रह सकता क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं।... ..... दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्रीयता और एक धर्म समानार्थी शब्द नहीं हैं, न ही इसमें एच है।

भारत में ऐसा कभी हुआ है। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

96 .

अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया है।

क.

असंवैधानिक होने के नाते।अधिनियम की वैधता को बाधित करने वाली रिट याचिकाओं की अनुमति है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमे के लिए वापस लिए गए मुकदमों के मुद्दों का जवाब इस न्यायालय को तदनुसार दिया जाता है।

राष्ट्रपति का संदर्भ सम्मानपूर्वक, बिना उत्तर दिए वापस किया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

मामलों का निपटारा किया गया।

यू. आर

3

1

.